12.23 hrs.

## MOTION RE: REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES —Contd

**Mr. Speaker:** The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Violet Alva on the 24th April, 1959, namely:

> "That this House takes note of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1957-58 laid on the Table of the House on the 9th December, 1958."

Shri Ganpati Ram was in possession of the House. He may continue his speech.

**श्री गणपति राम** (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन मैं निवेदन कर रहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा जो अस्पृश्यता निवारण के लिए सहायता दी जाती है, उसका कितना दुरुपयोग होता है। इस विषय में मैं बतलाना चाहता हूं कि केन्द्र की ओर से प्रादेशिक सरकारों को जो कोटा दिया जाता है हर साल के खर्च के लिए वह खर्च नहीं होता है। मैंने उत्तर प्रदेश का हवाला आपके सामने पेश किया था। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह बतलाने की कृपा करें कि १९५५-५६ में अस्पृश्यता निवारण के लिए उत्तर प्रदेश को जो सहायता दी गई, उसमें से कितना रुपया खर्च किया गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५६-५७ में, १९५७-५८ में और १९५८-५९ में अस्पृश्यता निवारण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो सहायता दी गई थी, उसमें से ज्यादातर रुपया लैप्स हो गया था, वह रुपया खर्च नहीं किया गया। मैंने यहां तक भी देखा है कि केन्द्र से जो सहायता दो संस्थानों को दी जाती है, एक भारतीय हरिजन सेवक संघ को और दूसरी भारतीय दलित वर्ग संघ को, इन दोनों में भी विभेद किया गया है। यह कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि केन्द्र का व्यवहार भी इस तरीके का है कि वह एक संस्था के साथ एक तरह से सलूक करता है और दूसरी संस्था के साथ दूसरी तरह का। हरिजन सेवक संघ को बगैर किसी प्रकार की कोई शर्त के, बगैर दस परसेंट की रेस्ट्रिक्शन लगाये हुए, रुपया दिया जाता है और भारतीय दलित वर्ग संघ को दस परसेंट चन्दे की शक्ल में रुपया एकत्र कर लेने के बाद ही कोई सहायता देना स्वीकार किया जाता है। इसके बारे में भारतीय दलित वर्ग संघ ने आपको लिखा भी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जिस ने देश से अस्पृश्यता दूर करने का बीड़ा उठा रखा है, देश में सामाजिक स्वतंत्रता ले आने का, सामाजिक बराबरी का दर्जा देने का दायित्व अपने कंधों पर लिया है, वह दें आर्गेनाइजेशंस के साथ जोकि एक सा काम करती हैं, भेदभाव बरतती है, एक को जब रुपया दिया जाता है तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, दूसरी को जब दिया जाता है तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस लगा कर वह उसके काम में बाधा पहुंचाना चाहती है और अगर यही मंशा है, तो ऐसी सहायता की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय, इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

12.24 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैंने पिछले दिन भी कहा था कि केन्द्र की तरफ से और प्रान्तीय सरकार की तरफ से भी अस्पृश्यता निवारण के लिए जो काशी मंदिर प्रवेश का आन्दोलन चल रहा था, एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि दिखावे मात्र का काम करने से काम नहीं चल सकता है। इसके लिए हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे।

अब मैं हरिजनों और शड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को जो वजीफे दिये जाते हैं, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज अप्रैल का महीना खत्म होने जा रहा है। हर जिले से यह सूचना जा

[श्री गणपति राम]

रही है कि अधिकांश हरिजन छात्रों और बैकवर्ड क्लासिज के छात्रों को वजीफे नहीं मिल पाये हैं। माननीय मंत्री महोदय ने उस दिन कहा था कि अब हम यह जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों पर डालने जा रहे हैं जिससे उन वजीफों का डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से हो सके। मैं कहूंगा कि यह अपनी जिम्मेदारी को खिसकाने का एक तरीका है। अगर आप वजीफे देना चाहते है तो केन्द्र से ही दें। अगर यह जिम्मेदारी स्टेट्स पर डालते हैं तो मै कहना चाहता हूं कि उनके पास इतना रुपया नहीं है कि वे दे सके। आपने कभी नही कहा है कि हरिजनो इत्यादि की बढती हुई संख्या के मुताबिक हम रुपया देंगे। साथ ही आपने यह भी कभी नही कहा है कि जिस प्रान्त में हरिजन छात्रो की सख्या जितनी है, उसके अनुपात से हम रुपया देंगे। इस तरीके से मैं कहना चाहता हू कि अपनी जिम्मेदारी को यह टालने का एक तरीका मात्र होगा। इसके खिलाफ हरिजन समाज और शड्यूल्ड ट्राइब्स की समाज बडे जोरो से प्रोटेस्ट करने जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर ही रहे और पैसे का न्यायोचित ढग से वितरण हो।

अब मैं रिजर्वेशन आफ सीट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हू। माननीय मत्री महोदय ने उस दिन कहा था कि सन् १९६० में यह रिजर्वेशन खत्म होने जा रहा है और सन् १९६२ में हम इस चीज को देखेंगे कि इस बीच देखेंगे कि यह चीज किस तरह से चलती है। सन् १९६२ में हम गौर करेगे कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है,। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९६० में जो कास्टीट्यूशन का प्राविजन खत्म हो रहा है क्या आप यह नही कर सकते हैं कि पाच साल के लिए या दस साल के लिए जितना भी आप मुनासिब समझे, इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंशन ग्रांट कर दें। अगर आप अब नही कर सकते हैं या पहले ही एक्सटेंशन ग्राट नही करते हैं और दो साल के लिए इस चीज को छोड़ देते हैं, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप दो साल के बाद एक्सटेंशन ग्रांट कर ही देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप की यह जिम्मेदारी होती है लडके को आगे बढाने की, लडके को पढाने की, उसी ढंग से स्टेट की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान की गरीब पिछडी हुई समाज को आगे ले जाने की ओर मैं चाहता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से वहन करे। अगर आप ऐसा नही करते हैं तो मैं कहना चाहता हू कि यह सब चीज जो आप कर रहे है, केवल दिखावापन है।

सर्विसिज में रिजर्वेशन की बात भी है। आपके यहा से इसके बारे मे एक सर्कुलर निकाला गया था कि इनको इनका कोटा दिया जाये। मै नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हू कि क्या आपने कभी तकलीफ गवारा की है कि आप देखें कि केन्द्र के हर विभाग में सन् १९५० से लेकर अब तक कितने बैकवर्ड क्लासिज के लोग, कितने शड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट आये, कितने चुने गये और उनमें से जो नही चुने गये, वे क्यो नही चुने गये और जो उनमें अयोग्यतायें पाई गईं उनको दूर करने का क्या रास्ता निकाला जा सकता है। यह कहा जाता है कि शड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट प्राय अनसूटेबल होते है। मैं यह कह सकता हू कि यह वही मैंटेलिटी है, जोकि अंग्रेजों की हुआ करती थी कि हिन्दुस्तान स्वराज्य के लायक नही है। क्या मैं नम्रतापूर्वक पूछ सकता हूं कि हम में से बहुत से लोग जिस वक्त स्वराज्य दिया गया, स्वराज्य करने लायक नही थे? क्या हम में से बहुत से लोग शायद मंत्री बनने काबिल थे, बडे बडे ऊंचे पदो पर नियुक्त किये जाने के काबिल थे? लेकिन मौका दिया गया और जिन लोगों को मौका मिला, उन्होंने ईमानदारी के साथ, योग्यता दिखा कर और कर्मनिष्ठा का परिचय दे कर अपनी जिम्मेवारियों को

अच्छी प्रकार से निभाया । क्या इसी तरीके से आप हरिजनों की नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं ? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि सन् १९३८ से १९४० तक, सन् १९४० से १९४२ तक जो डिसोजा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर मुसलमानों को सर्विसिज में बेटेज नहीं दिया गया था और बेटेज दे करके उनकी संख्या सर्विसिज में नहीं बढाई गई थी ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन जिन लोगों को इस तरह से बेटेज देकर नौकरी में रखा गया, वे सब के सब नाकाबिल निकले ? अगर वे नाकाबिल नहीं निकले तो आप इस एक्सपेरिमेंट को हरिजनों के केस में क्यों नहीं चालू करते ? अगर आप यह नहीं करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपकी नियत साफ नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल जब आई० ए० एस० का रिक्रूटमेंट हो रहा था, उस वक्त २६ सीटें इनके लिए रिजर्व की गई थी । १३२ कैंडिडेट आये । उनमें से केवल आठ ही आपने रखे । अगर आप चाहते इन लोगों को रखना तो आप इनको एक साल के लिए या छ: महीने के लिए एप्रेंटिसशिप में रख करके, थोडी सी ढील उनके केस में करके, उनको बराबरी के दर्जे पर ला सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ।

अभी थोडे दिन पहले यह सुना गया था कि वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई मिनिस्टरी में कुछ जगहें खाली हैं और वहां पर सेक्शन आफिसर्स को असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड २ बनाने के लिए उनके केस में १५ बरस की सर्विस के बजाय १२ बरस की सर्विस जरूरी बनाई गई है । लेकिन वहां के अधिकारी यह कहते हैं कि जो हम ने पेनल बना रखा है, वह जब तक खत्म नहीं होता है तब तक शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रोमोशन नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे । अगर पेनल को पहले खत्म किया गया तो कंसेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब उनको प्रोमोशन मिलेगी तब उनकी सर्विस १३-१५ या १६ वर्ष की हो जायेगी । क्या इस विषय में आप कोई सक्रिय कदम नहीं उठा सकते हैं । मैं देखना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट सच्चे मानों में शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासिज इत्यादि के हितों की किस प्रकार से रक्षा करती है । हिम्मत के साथ आप कदम बढ़ायें, ठोस कदम उठायें । सरकार का उद्देश्य केवल संतोष करके पूरा नहीं हो सकता है । इस तरह से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है ।

उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए आपने कितना काम किया है, यह मैं जानना चाहूंगा । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री, काटेज इंडस्ट्री वे चला सकें या इसको बढ़ावा दे सकें, इसके लिए प्रथम योजना में तथा द्वितीय योजना में कितना रुपया उनके लिए अलग रखा है तथा कितना उन पर खर्च किया है और कितना नहीं हुआ है । क्या आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना मे शामिल करने के लिए तथा रुपया अलग रखवाने के लिए कोई स्कीमें सबमिट की थी जिस से हरिजनों की आर्थिक दशा सुधर सके ? अगर नहीं की थीं तो यह किस की जिम्मेदारी है ? इसके लिए आप जिम्मेवार हैं । देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना आपके हाथ में है । आज यह कहा जाता है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की आर्थिक हालत बहुत ऊंची हो रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह पता लगाने की कोशिश की है कि पिछले दस बरसों में कितने शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने इनकम-टैक्स देना शुरू किया है, कितने शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट लाइसेंस दिये गये हैं । इन की आमदनी क्या है, क्या इसका पता लगाने की भी कोशिश की गई है ? बल्कि आज तो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि जिन हरिजनों की मंथली इनकम २५० रुपये या २०० रुपये महीना है उनके बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा की सुविधा थी, वह नहीं रहेगी । अगर इस तरह की ही भावना है तो

[श्री गजपति राम]

मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दे रहे हैं कि सारे देश में अनिवार्य शिक्षा चालू की जाये, फ्री शिक्षा दी जाये और दूसरी तरफ हरिजनों के लिए आप इस ढंग की रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस तरफ भी आप ध्यान दें।

मेरा एक सजेशन और भी है। बहुत दिन से मांग चली आ रही है और शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने भी अपनी रिकमेन्डेशन में कहा है कि सर्विसेज में ज्यादा अच्छे तरीके से भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमिशन में एक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधि भी रखा जाय ताकि वह देख सके कि उन का रिजर्वेशन कोटा पूरा होता है या नहीं। मैं चाहता हूं कि इस सिफारिश पर, जैसी कि हरिजनों और बैकवर्ड एरियाज की मांग भी है, आप ध्यान दें और इस चीज को हमेशा जेरे-गौर रखें।

जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है वह तो मैं ने आप से कहा। मैं आप से यह भी पूछना चाहूंगा कि अभी तक गृह उद्योग विभाग को जो सहायता आप की तरफ से या किसी और विभाग की तरफ से दी गई, उस में कितने की मांग की गई थी और कितना उस पर खर्च किया गया, कितना लोन दिया गया या कितनी तकावी दी गई ? इसके आंकड़े भी आप ने सदन के सामने पेश नहीं किये क्योंकि इस तरफ आप का ध्यान नहीं है। छुआछूत के बारे में आप की आवाज है कि हम उसे खत्म करना चाहते हैं। उस के लिए मैं एक स्पेशल सुझाव देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि यह कलंक देश से दूर हो तो इंटर कास्ट डाइनिंग और इंटर कास्ट मैरेज का सिस्टम, भले ही दूसरी जगह आप न शुरू करें, लेकिन सर्विसेज में भर्ती के लिए आप अपने रूल्स और रेगुलेशन्स में इस चीज को जरूर रखें। आप उस में एक नियम यह जरूर रखिये कि उन्हीं आदमियों को सर्विसेज में प्रिफरेंस दिया जायेगा जो इंटर कास्ट मैरेज को प्राथमिकता देंगे या करेंगे।

इसी के साथ मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर ८० या ९० लाख रिफ्यूजी आये, उन के लिए तो आप ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनायी। उनके उद्धार के लिए, शैक्षणिक और सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए तो विचार किया गया, लेकिन जहां पर ७ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट्स और करीब डेढ या २ करोड़ शैड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं उन के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री का प्रस्ताव रख कर उन की अवस्था को सुधारने के लिए आप एक प्रगतिशील कदम नहीं उठाना चाहेंगे ?

जहां एक तरफ हमारे शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर अपनी योग्यता और ईमानदारी का परिचय देते हैं, वहां पर मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जो उन के असिस्टेंट महोदय शैड्यूल्ड कास्ट्स के वेलफेअर के लिए रखे गये हैं और जो बनारस के एक गांव में गये थे, उन के कहने पर वहां के जमींदारों ने ३०० एकड़ हरिजनों को, जो कि उस की जमीन पर खेती करते थे, एजेक्ट करवा दिया। उन्होंने एन्क्वायरी की और पाया कि यह सब चीजें हो नहीं हैं। उन्होंने इस को मंजूर भी किया लेकिन अफसरों के बहकावे में आ कर यह रिपोर्ट दे दी कि १४०० एकड़ जमीन तो दूसरे लोगों ने हड़प ली है और ३०० एकड़ जो बाकी है उसे हरिजन हड़प लेना चाहते हैं। दूसरे भले ही सारी जमीन को हड़प जावें लेकिन हरिजन वेलफेअर वाले अफसर इस तरह की रिपोर्ट देने से नहीं हिचक सकते। बड़े शोक की बात है कि हमारे लिए इस तरह के कानून बने हुए हैं तब भी हमारे अफसरों के द्वारा इस तरह की बातें होती हैं।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। केवल इतना कहना चाहूंगा कि हरिजनों के

सामाजिक, शैक्षणिक और औद्योगिक उत्थान के लिए आप जितना शक्ति कदम उठा सकें, उठायें।

**Shri R. K. Gaikwad** (Nasik): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after adoption of the Constitution on 26th November 1949, the President of India, in view of article 338 of the Constitution, appointed a Special Officer to safeguard the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the year 1950. The duty of the Special Officer is to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution and report to the President upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament. So while considering the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1957-58, we have to see what constitutional safeguards have been investigated by the officer concerned and what Government have done in that behalf.

First of all, I will deal with article 17 of the Constitution which says:

> "'Untouchability' is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of 'untouchability' shall be an offence punishable in accordance with law".

Government were also pleased to bring forward the Untouchability (Offences) Bill which was passed into the Untouchability (Offences) Act in 1955. Now, the question before us is as to whether untouchability has been removed. The Commissioner says in his Report under reference:

> "From the information available, it is also seen that in the State of Madhya Pradesh, out of the cases registered under the Act during the years 1955, 1956 and 1957, as many as 27, 42 and 33 cases respectively were
>
> "not challenged for want of evidence. This would suggest that people in that State still hesitate to come forward to give evidence in such cases. A large number of cases which were compounded during these years would *prima facie* indicate the developing tendency of the people to live peacefully with the Scheduled Caste people and to compromise themselves to the present condition".

In my opinion, the presumption of the Commissioner is not correct. The Scheduled Caste people in the villages are put at the mercy of the caste Hindus. They have to depend wholly and solely on the sweet will of the caste Hindus. They are not self-supporting. Under the circumstances, the Scheduled Caste people have to surrender and act according to the desire of their masters, caste Hindus; if the Scheduled Caste people do anything against the desire of the caste Hindus, they are harassed. They are boycotted, they are beaten too.

I have no time at my disposal to explain in detail what this boycott means. This boycott means nothing less than stopping everything and making it impossible for them to live in the village because they have to earn their bread from the caste Hindus, because even when they want to go for answering the calls of nature they have to go to the fields of the caste Hindus.

My information is this, that in Punjab State roundabout Delhi the Scheduled Castes are prevented from going to the open fields for answering their calls of nature and that is why Scheduled Caste people have dug pits in their own small houses—latrines—which I have seen and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also seen. That is the position.

**An Hon. Member:** It is wrong.

Another Hon. Member: That is correct.

Shri B. K. Gaikwad: I have seen the thing with my own eyes (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order; now, let us hear the hon. Member

Shri B. K. Gaikwad: I want to ask Government one question in this behalf. Have they ever attempted to make the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people self-supporting? My answer is, 'No'. If they have done something, let them explain.

When the Scheduled Caste people demand Government land for cultivation, at many places, it is refused. If they want to start any business or industry, as my hon. friend just now said the licences are refused to them under the pretext that their forefathers were not doing this business in the past, as if doing business or getting licences has become the monopoly of certain individuals or certain classes of people That should be stopped immediately. We have demanded, we have moved resolutions in the Central Advisory Board also, and the matter is after all receiving attention. Nobody knows how long it will take.

An Hon. Member: That has been refused by the Commerce Ministry.

Shri B. K. Gaikwad: That is going on. The Commissioner says, in his Report on page 15—

> "The Tribal Welfare Directorate, Madhya Pradesh has, however, compiled a list of villages where untouchability is still prevalent in the State. This list consists of 3,260 villages spread over eight Districts in the State. The Government of Orissa has intimated that in 8,606 villages spread over eight Districts"—he mentions some names—it is not necessary as they have already been mentioned in the Report—"untouchability is still observed."
>
> "Information relating to remaining Districts of Orissa is not yet received."

Sir, what action have Government taken on this Report? In Madhya Pradesh, in these 8 districts, there are 3,260 villages where untouchability is observed and in Orissa there are 8,606 villages where untouchability is observed. If Government have the slightest regard for the Constitution and legislation they have passed, what have they done? If not, why not? Why have not Government launched cases against the villagers who observe this untouchability?

I know it is the duty of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to report the matter to the Government. But, it is for the Government to take action. I just want to know what action Government have taken in this matter (*Interruption*). They will not take any action.

Then, I will come to wells. You will find that there is not one instance but thousands and thousands of instances where the Scheduled Caste people are not allowed to draw water from public wells. When we demand information, it is said that information is not available. The Commissioner has mentioned this in his report. What can the poor Commissioner do? He can only write to the State Governments through the Central Government asking for information. When the information is not supplied to him, what can he do? Government is responsible for this.

One thing which I must mention here is this. The Congress Government is ruling here at the Centre and you will see that in almost all the States, except Kerala, Congress Governments are working. That being so, when certain information is demanded, why is it being refused? Is this the co-ordination?

Shri M. R. Krishna (Karimnagar—Reserved—Sch. Castes): They do not have.

**An Hon. Member:** They are not interested in it

**Shri B. K. Gaikwad:** Whatever the presumption of my hon friends may be, the information is there with the Government but they are ashamed to provide that information In case the information comes forth, I think, they will have to hang their heads in shame because at thousands of places the public wells are not open to the Scheduled Caste people

The new policy of Government is this Supposing a new well has to be constructed It is said that the villagers should contribute 50 per cent for digging the well When this question comes, naturally, the caste Hindu villagers say, if the well is going to be thrown open for all, why should they contribute 50 per cent? So, generally they do not pay 50 per cent of the cost and the Scheduled Caste people are naturally being very poor they are not in a position to pay So, you will find that no wells are constructed in villages We are sitting here in an air-conditioned hall But, if you go to the villages, you will find that even on public wells the Scheduled Caste people have to wait for hours together for getting water If nobody provides them with water they have to take water of the dram My hon friend the Minister, Shri Datar, will also realise this If he accompanies us to the villages where we can show all these things to him

Where there are no public wells, there are private wells The caste Hindu people can quench their thirst by taking water from these private wells All people go and take water from these wells except the Scheduled Caste people If we go to Government and represent the grievance they say, 'That is a private well and you will not be allowed to draw water from a private well'

In this matter, I was going to request the Government to come forward boldly and make an announcement to the effect that all wells which are used for drinking purposes, whether they are public wells or private wells, should be thrown open to all. Not only that My proposal is this that Government should have a squad of policemen—just as they have for slum clearance in Delhi where we find the police going and demolishing the houses and throwing away the materials I want such a police squad to be appointed only to look after this thing, namely, that the wells are thrown open to these Scheduled Caste people (*Interruption*) And, my proposal is that the head of the squad should be a Scheduled Caste man who will take more interest in this Let there be other constables from other communities, but the head of the squad at least must be a Scheduled caste man who will look to the interests of the Scheduled Caste people

**Shri Sonavane** (Sholapur—Reserved —Sch Castes) Why not the head of the Home Ministry?

**Shri B. K. Gaikwad:** I come to articles 23 and 43 Article 23 of the Constitution says:

> "Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law"

Article 43 reads:

> "The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and in particular the State shall andeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas"

**13 hrs**

That is the provision in the Constitution Now, I want to ask whether

[Shri B K Gaikwad]

*begar* or forced labour has been abolished It is there, everywhere, throughout India .

**An Hon Member:** Not in Punjab

**Shri B. K Gaikwad:** It is there in U P You can go to any place in India and you will find out for yourself Forced labour is taken by the Government as well as by the villagers, by prominent persons of the village No action has been taken by the Government Last time, speaking on Minimum Wage Bill, I had said that people are paid Rs 4 or Rs 5 per month and are asked to work for the whole month This is nothing but forced labour, it is there in U P and all the other States (*Interruption*) No work is provided, no living wage is given, no decent standard of living is provided to the people of our country, particularly to the Scheduled Castes and Tribes What is the Government going to do in this matter? The Constitution cast a duty to provide work, to give a living wage and ensure a decent standard of living When is the Government going to do this?

Article 46 of the Constitution clearly states that the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation This clause specifically refers to weaker sections of the people Several millions of Scheduled Castes people have accepted Buddhism and hence they are no more Scheduled Castes people They do not call themselves so Appendix X of part II of the report of the Commissioner deals with the concessions granted by the State Governments and the Union Administration to these Scheduled Castes converts to Buddhism In that you will find that except Punjab no other State has done anything in the matter My suggestion is that the Scheduled Caste people who have embraced Buddhism are weaker sections of the country and the Government should, therefore, continue all these concessions in regard to education, economic aid, appointments to services to these people which they were getting before as Scheduled Castes even without amending the Constitution

Article 335 says that the claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State In every yearly report, the Commissioner is bringing to the notice of the Government the fact that their percentage is very low So many hon Members who have spoken on this have also thrown light on this and they have pointed out that the percentage of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in Class I and II service is hardly one per cent It is not even one per cent I want to ask the Government as to what action has been taken to fill up the percentage? When questions are raised on the floor of this House, lame excuses are given by the Government what suitable candidates are not coming forth to fill up the reserved posts Suitability has become one of the wonders of India, if not of the world! Even after satisfying all conditions in regard to educational qualifications, these candidates are made unfit I will tell you one or two things I have come across and I think my Congress friends and the Government will also consider this sympathetically

The ex-Congress President, Shri Dhebar, was once the Chief Minister of Saurashtra He found that the percentage reserved for the Scheduled Castes and Tribes was not filled up. When he asked the Secretary to fill it up, the Secretary told him that there were no suitable candidates from the Scheduled Castes and Tribes for the posts to be filled in When we were

discussing this matter in the Estimates Committee, we were told this Shri Dhebar ordered the Secretary that no vacancy should be filled up till a suitable candidate from the Scheduled Caste or Tribe was forthcoming You know what happened and what magic that order created? Immediately after that, the Secretary found suitable candidates from the Scheduled Castes and Tribes Then those candidates were appointed This is what Shri Dhebar did in Saurashtra Let my Congress friends and the Ministry take lessons from that

**Shri M R Krishna:** Rajaji did so

**Shri B K Gaikwad:** We appreciate it If the Congress people do something we do appreciate, we have got the capacity of appreciation

There is another instance to illustrate the 'suitability' I will now quote the name of that officer because he is now a retired officer my— friend Shri M K Jadhav He is a retired Collector of the revenue department of the Bombay State In 1926, after he passed B A (Hons), he applied to the Collector for getting a job He was appointed as a clerk under one Mamlatdar in Poona district Within a couple of months, that Mamlatdar reported to the Collector that he, Mr M K Jadhav was unfit to work as a clerk He was a B A (Hons) and still he was unfit to work as a clerk and he was removed In the year 1927, the Governor of Bombay declared that he wanted to appoint some direct recruits from the so-called depressed claseses The Scheduled Castes were called depressed classes in those days Shri Jadhav was one of the candidates and fortunately he was selected for the post of a Deputy Collector in the revenue department After receiving training for a few months, he was posted to Poona district fortunately where that Mamlatdar was working He was the man who was working as a clerk under the Mamlatdar and who was made unfit by his report has come as his boss, as Deputy Collector Not only that I have no time at my disposal to explain the whole thing

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon Member's time is up

**Shri B. K Gaikwad:** I have not finished half

**Mr Deputy-Speaker:** I was to give 15 minutes that may be reduced to even ten minutes But I have given him 25 minutes Still he wants more time

**Shri B. K. Gaikwad** Thank you very much You are always very kind to me

**Mr Deputy-Speaker:** This time I may not be so kind as he wants me to be He should try to finish now

**Shri B. K. Gaikwad:** A kind man is always kind Now, Sir, I will finish Shri Jadhav was there as a Deputy Collector and later on as Collector also and then retired as Collector He had given several judgments as a Collector and District Magistrate Several appeal were there but in not a single case his decision was changed by the appellate courts Not only that He was known as the most efficient officer Therefore, a man who was found unfit for clerk's post was an efficient Collector This is the sort of efficiency That is why I say, do not go, do not be led by what the Public Service Commission says that Scheduled Castes and Tribes people were not found suitable

**Mr. Deputy-Speaker.** That is not desirable It should not be said "Don't be led by what the Public Service Commission says in its report that a particular man is not desirable" The Public Service Commission is an independent body created statutorily under the Constitution We have every faith in that, and I will not allow any aspersion or insinuation to be made against the Public Service Commission by the hon Members I

[Mr Deputy-Speaker]

would advise him to withdraw that remark He has made a slip He meant others

**Shri K U. Parmar** (Ahmedabad-Reserved-Sch Castes) We have to bring a resolution about setting up a supervisory body to have a check on that

**Mr Deputy-Speaker:** Instead of Public Service Commission, he may say other officers

**Shri B. K Gaikwad:** The UPSC says that candidates are not found suitable In the last session, or in this session itself if I mistake not, hon Minister, Shri Datar made an announcement "Whatever recomendations are made by the UPSC, we are not bound to accept that We have got our own views" I have not got it here, but I can show that He is nodding his head saying no, no

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar):** He is misquoting me

**Mr Deputy-Speaker.** He has always said, rather that has been the position of the Home Ministry, that almost in all cases they have been guided by the advice given by the UPSC

**Shri Datar:** During the last two years that has been the case in all cases

**Mr. Deputy-Speaker:** Yes That was disclosed here very recently Now the hon Member says that the Minister said that they are not bound by the recommendations Theoretically they may or may not be bound, but they have always acted upon the advice they got

**Shri B K. Gaikwad:** I just want to show where the shoe pinches I will explain where the shoe pinches

**Shri Datar:** Sir, the remarks made by the hon Member about the Public Service Commission may be withdrawn or . .

**Mr Deputy-Speaker:** They should be withdrawn

**Shri B K Gaikwad:** What, Sir?

**Mr. Deputy-Speaker:** His remarks about the Public Service Commission that the Minister should not be led by the advice of the Public Service Commission that candidates are not suitable

**Shri B K Gaikwad** I withdraw them I will be always at your disposal, Sir, and also at the disposal of the hon Minister, Shri Datar

**Mr Deputy-Speaker:** I am sorry, I am not now at his disposal He should conclude now

**Shri B K Gaikwad:** Sir, I will finish There is one bad practice in force When there are reserved seats the Central Government for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, particularly in Class I and Class II posts, and when candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been found unsuitable, then the posts are made "non-reserved" and these posts are filled in by non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribes candidates Due to this provision, Sir, intentional and mischievous attempts are being made by several prominent leaders and big officers in consultation with each other They are all interested in these posts They want to appoint their sons, sons-in-law or other relatives to these class I and class II posts It is a temptation They all make a common cause in order to reach this goal They make a conspiracy to victimise the poor Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates by calling them unsuitable, unfit, and make room for their favourite persons If Government is really honest and sincere to their duties I propose that as Shri Dhebar did in Saurashtra as Chief Minister our Central Government also should do the same thing They should make a public announcement that no class I and class II posts should be filled by non-Scheduled

Caste and non-Scheduled Tribes candidates and the posts should be kept vacant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates till they are available. Sir, you will find that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who are found unsuitable and unfit today will be found suitable and fit tomorrow.

Sir, may I have two more minutes?

**Mr. Deputy-Speaker:** I will only allow him now to sit down.

Shri Barman. Before the hon. Member starts his speech I would like to say one thing. There are more than 80 hon. Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and every one of them has expressed a desire to speak and participate in this discussion Besides, there are other hon Members who are also anxious to take part in this discussion Therefore, my difficulty can very well be appreciated, how I can accommodate them I would, herefore, request hon Members to take as little time as possible, if they can. Every hon. Member should not try to discuss every article of the Constitution; they should pick up some portion of it which they want to bring to the notice of the House.

श्री डहके (मडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया) उपाध्यक्ष महोदय, मै चाहता हू कि शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिशन की रिपोर्ट पर विचार आज ५ बजे शाम तक बढा दिया जाय क्योकि २५ जनवरी सन् १९६० में रिजरवेशन का कास्टी यूशनल राइट खत्म हो जाता है । यह सातवी रिपोर्ट है जिस पर कि हम अपनी अपनी आत्मा के ऊपर बल देकर बहस कर सकते हैं और इसलिए हमें अपनी पूरी तस्वीर रखने का अवसर मिलना चाहिए और आज ५ बजे शाम तक के लिए इसको बढ़ा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह तसल्ली है कि जिन साहबान को भी बोलने का अवसर मिलेगा वह पूरी तरह से वह तस्वीर रख सकेंगे और पूरी तस्वीर इस हाउस के सामने रख दी जायेगी । अब जहा तक कि इस रिपोर्ट पर विचार ५ बजे शाम तक बढ़ाये जाने का सवाल है तो यह हो सकेगा और जो आखिरी आध घटा बचता है वह भी अगर आप चाहेंगे तो मै दे दूगा ।

**Shri Barman** (Cooch-Bihar-Reserved-Sch. Castes): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I shall abide by the advice that you have just now given, not to go on repeating what has been said by others. In fact, Sir, this is the Seventh Report that we are considering on the floor of this House and it requires no imagination to say that matters regarding untouchability, reservations in public services and posts and, especially, I shall not call it failure but I shall call it incapacity of Government to deal with the matters—the hon. Deputy Minister said on Friday that it mainly concerns the States—these are matters that are practically being repeated every year These have also been placed before the House by the hon speakers who have spoken before me

In fact, Sir, there are practically three main points so far as the Report of the Scheduled Castes Commissioner is concerned. Firstly, there is the abolition of untouchability; secondly, there is reservation to services and posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and, thirdly, there is the question of giving facility for education to these unfortunate backward classes.

I consider, Sir, that this question of untouchabiltiy will remain so long as we do not fulfil our objective that has been declared in the Preamble of our Constitution—equality of status and of opportunity, and also justice: social, economic and political. Till we fulfil that it will remain, and for that purpose we are doing our best. But, at the same time, it requires much more. How far Government proceeds and

[Shri Barman]

progresses in the elimination of distinction between castes and cates and distinction between classes and societies so far as their economic circumstances are concerned is the point It is mainly embedded or rooted in the question, how far we are able to remove distinction between one caste and another or the hierarchy of castes So long as that remains in our body politic, in our social system, this question of eradication of untouchability will remain a very difficult question At the same time, we should do our best So, I shall not dilate on that matter any more

As regards the question of reservation of posts and services, it entirely depends upon how far we are able to remove the difficulties in the matter of education amongst these two classes Of course, along with other backward classes, if we can solve that matter, if we can uplift them in the matter of educational standards, the question of unfitness will not be repeated so often I shall not, therefore, touch upon that point also But I am mainly concerned today in placing before the House through you my own anxiety about the new procedure that Government propose to introduce so far as the educational facilities are concerned To our misfortune the hon Home Minister is in hospital We pray for his early recovery and that he should join his regular duties

The other day the Deputy Minister was present and we very much bank upon her heart, woman's heart, which is so affectionate especially for those who are backward But unfortunately we have got the Minister of State I make this distinction because of this Shri Datar knows the conditions from the very beginning, and especially the matter that I am going to mention before this House just now Perhaps Shrimati Alva is new to the post and she may not be conversant with the past history That is my supposition Of course she must have read everything through the proceedings

The matter that I want to mention is this Shrimati Alva has said in her speech thus

> "The next point that agitates the minds of hon Members in the House and also of the public outside is the most important question of scholarships".

I entirely agree with her This is a matter on which depends the whole of our future regarding untouchability, regarding reservation of posts and services, and what not, they follow Once we are able to give our children education, education to our boys, and especially to our girls—Shrimati Alva has also mentioned that girls' education is more important now—that will be good to start with We entirely agree with the Deputy Minister's observation in that regard, but another thing that she has mentioned gives us much concern She says

> "In this matter we have made a far-reaching change in the procedure in the sense that we have decentralised the award of scholarship from now on"

I do not doubt for a moment that this procedure that the Government have decided upon—I still hope that they have not finally decided it—was for the benefit of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and that the scholarships may be distributed to them in time, that it was for their good But I shall place the facts before you and the House that instead of doing good to us it will be very much detrimental to the interests of the Scheduled Caste boys in getting the amount of scholarship

Let me tell you at the outset that I have full faith upon the State Governments also, but I wish to mention that the procedure is such that it will lead to too much of complexity in the matter, and thereby the legitimate advantages—or whatever you might call it—that they have been getting

so long will be curtailed. I shall tell you why.

What is the procedure in the distribution of scholarships? At present, it is done by the Central Education Ministry. The Education Ministry receives the applications from all post-matric students from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes. The Government allots a lump sum. Out of that lump sum, distribution is made I can read from the report but that will take time. But I can mention one or two lines from it. The procedure is this.

> "The Board determines the number of scholarships to be allocated to different States on population basis".

This is the first principle. As I was mentioning, out of that allotted sum, in the beginning, some proportionate allotment is made between these three classes, namely, what will be the proportion that will go to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other backward classes respectively. The amount varies from year to year. It is 40 or 45 per cent for the Scheduled Castes, 40 per cent for the other backward classes, and 15 per cent for the Scheduled Tribes and so on. It varies from year to year. Once that is done, then, whatever is the quota of the Scheduled Castes will be dealt with in this way. I shall specially mention the Scheduled Castes because, as yet, up till now, including this year, I can say that whatever the Government has decided will not affect at least the Scheduled Tribes very much because the hon. Deputy Minister has said that the number of scholarships in respect of them is so small that the money that is allotted for the purpose is not exhausted.

But the hon. Deputy Minister has mentioned certain facts as regards the Scheduled Castes by telling us that the number of Scheduled Caste boys or candidates is increasing very fast and it is to such an extent that Government is not in a position to allot that much money which is required. I shall come to that point last. If the House is convinced, or if the Home Ministry is convinced, that the number of Scheduled Caste candidates has grown to such an extent that considering their population the allotment is more than sufficient for them, then, of course I cannot object to making any restriction.

For this purpose,—I need not tell it and everybody knows it—let us take the census. In the census of 1951, the number of Scheduled Castes was enumerated as more than five crores, and by this time it must have reached at least six crores. Out of that, the maximum number that has to be allotted scholarships is not much. I think last year it did not exceed 30,000. You should know that in regard to the post-matric scholarships, throughout the length and breadth of India all these post-matric boys of the Scheduled Castes get scholarships from the Centre, and no State gives any scholarship to a post-matric student belonging to the Scheduled Castes. Therefore, out of the six crores of population, 30,000 boys got scholarships last year. In Calcutta colleges, you will find that even in one single college, there are 10,000 students belonging to other classes. I cannot consider how the Ministry thinks that the number of Scheduled Caste candidates has increased to such an extent that it is not possible now to give everyone of them a scholarship. What is the maximum? She has stated that Rs. 126 lakhs have been spent last year. I would suggest that if the Ministry thinks that they are so much tightened, so much cornered in their finances let them curtail the expenditure on other heads. But please, for God's sake, give our boys the facility of education, the facility that we have been getting from the year 1952 up till now. Let our boys become men who can stand before the civilized public and stand before their elder brothers as equals in this country. We know that they shall have their own right conceded to them by their own efforts and that no favour will be

[Shri Barman]

required by them for getting educational facilities thereafter Our time is past, but we at least expect that our boys and girls may be honourable men and women in this free India

What happens now? Now, as soon as the quota is fixed, then it is distributed on a population basis There are certain States where the number of boys is small Therefore, there is surplus money That surplus money is redistributed *pro rata* to other States where there are students who are left without scholarships, because the fund is exhausted Once you give it to the State, I can very well say that the year will run out, but the *Centre will not know which is the* State Government that has got surplus money and it will have no option to redistribute it. Why do you make this rotten procedure? It is your money and it is justly the responsibility of the Central Government and the Members of Parliament who are to aid the Government here; this duty lies squarely on you Why do you shun it? Is it because certain things have happened and you are afraid of it? Don't be ashamed of that If simple distribution of scholarships is such a complicated matter to the Central Secretariat, I do not know what to call this administration It is such a simple matter Just strengthen the scholarship distribution board by drafting a few more clerks from the other departments in the beginning of the year. That will solve the whole difficulty. Instead of that, you are making these complications

It is known at least to the scheduled castes and to my friends here that in 1952, when we found that the number of boys from the scheduled castes and scheduled tribes have increased and money allotted in the budget was not sufficient, we approached the hon. Education Minister. He had a large-heart and said, "I am all along trying for this, but it is not in my hands; it is in the hand of the Finance Minister." It must be said to the credit of Shri Deshmukh—we shall never forget it—that we met him in a deputation and told him that whatever provision might be made in the Constitution, it is not a matter to be solved overnight; at least, you can help us by giving our boys education in the post-matric stage Before the matric stage, it is the responsibility of the State

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member's time is up.

**Shri Barman:** I earnestly request you to give me some more time, because it is a very important matter I hope you shall give me a chance to explain why I oppose this procedure

*I shall cut short the story, he rea*dily agreed and since that year till last year, 1958-59, all our boys belonging to the scheduled castes and scheduled tribes have got scholarships. It is in that hope that they are getting admission in the colleges after passing the matric Every year, there was a short-fall in the allotted amount and every year, we approached the Finance Minister and got additional allotment Last year also, there was a short-fall of about Rs 24 lakhs and the hon. Home Minister made good that deficiency, and every boy and girl belonging to the scheduled castes or scheduled tribes was given scholarship

If distribution is handed over to the States, then the Members here would not know, when the year is out, whether any State has got surplus money and that difficulty will arise Our boys, mostly coming from the poorest classes, are getting admission in the hope that they will get scholarships. Once that is discontinued, 50 per cent of the boys will have to discontinue their studies, because they cannot afford the post-matric education, which is so costly In this way, are you advancing our cause so far as education is concerned or are you retarding it? What for are you doing this? Because the matter will be simplified if it is handed over to the States? I can very well say, it will be just reverse.

Sir, I will not encroach on your kindness too much I shall only mention that even if Government has decided finally that they shall hand over this to the States, I do not know how they will solve these complications There is another matter which the hon Deputy Minister mentioned, *i e* some element of selection will have to be introduced

**The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva):** There is a little confusion It was said for the other backward classes that some element of selection would have to be introduced But as far as the scheduled castes go, the difficulty which the hon Member fears will not arise

**Shri Barman:** Then, I have nothing to complain, because as regards the other backward classes, there is already an element of selection imposed If I am assured that this will not change the policy so far as scheduled castes and scheduled tribes are concerned, I have nothing to complain in that regard It is now for Government to see whether the procedure that they propose will facilitate their action or retard it I hope they will consider it

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Hissar) Will every scheduled caste and scheduled tribe candidate go on getting scholarships as now?

**Shrimati Alva:** Yes, Sir; the scholarships will continue

**Shri Datar:** All those who apply will get the scholarships

**Shri Kodiyan** (Quilon—Reserved—Sch Castes) Mr Deputy-Speaker, at the very outset, I must say that the report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner does not help us in having a correct assessment of the progress achieved in regard to the various schemes for the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes. I can, of course, understand the difficulty of the Commissioner. His office has been asking for information from the State Governments, but information is not forthcoming in time In this report, it is stated that the Commissioner has not got sufficient staff to have a correct evaluation of the progress in the various States So, I would request the hon Minister to provide him with sufficient staff, so that he may do his work more efficiently than at present

When we come to the actual achievement in this field, we have to confess that the progress so far made is not satisfactory in all the items of expenditure The hon Deputy Minister while initiating the discussion on the report, painted a rather rosy picture and said, so much has been done in this respect and from now on more is going to be done While going through the report, one must realise the fact that the money allotted to the various States and also money allotted by the State Governments for the various schemes are not properly spent When we take item by item, this failure of State Governments to utilise the allotted amount can be seen from the report

It is rather unfortunate that even after 11 years of welfare work, we are not in a position to assess the situation correctly The Home Ministry I am told, has an evaluation organisation, but I do not know what work they are doing I have to make a suggestion in this respect In every State, there must be an organisation to evaluate the work done in the respective States and the evaluation organisation in the Centre must work in co-operation with the evaluation organisations in the States Unless a correct picture is before us, we cannot plan effectively for the future The third Five Year Plan is in the formative stage If correct planning is to be made with regard to the welfare work of the scheduled castes and scheduled tribes, a correct picture of the actual situation in the country must be before us

Coming to the various schemes for the welfare of the backward classes,

[Shri Kodiyan]

I must deal with the most important and vital aspect of the whole programme of work, that is, with regard to the economic development of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes This vital aspect of the problem, I must say, has not been given sufficient emphasis by the Government Unless the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are helped to stand on their own legs economically, no progress worth the while can be achieved in this respect Scheduled Caste and Scheduled Tribe Members and other responsible leaders of these communities have been time and again requesting the Government to distribute Government land to the Scheduled Castes and other backward classes people, to the landless labour, but the achievement in this respect I must confess is rather very unsatisfactory

The Scheduled Castes Commissioner in his Report has stated that only in certain States land has been distributed In other States also steps might have been taken but he has not been given information on this point He says that in Bihar, Bombay, Madhya Pradesh, Orissa and Tripura lands have been distributed to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes The total amount so far distributed is 43,41,900 acres This includes land distributed on lease-hold basis and also one year leases With regard to other States information is not available

On page 62 of the Report he says that about 112 9 million acres of cultivable land are available with the various State Governments He further states that if about half of this cultivable land is distributed amongst the Scheduled Castes people the problem would be solved He says

> "If efforts are made to settle these people on 58 0 million acres of cultivable land, quite a large number of them (perhaps all of them) can be settled in agriculture. Some efforts were made during the First Five Year Plan period to reclaim land and a total of over 18 lakh acres were reclaimed"

But

> "Figures as regards the scheduled caste and scheduled tribe persons benefited from this scheme are not available"

"It is also significant to note" he goes on saying,

> "that Rajasthan, Orissa and Vindhya Pradesh which have sizeable concentration of cultivable waste land either did very little or did not figure at all in these reclamation and settlement operations"

Then even in States where land is distributed, there are certain difficulties in the way On page 66, he says

> "The Mysore Government have reported that certain types of land have been released by the Revenue Department for grant to the landless Individuals, however, under the preference list come after educational institutions, inferior village servants and co-operative farming societies But among individuals, first preference is given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes There is a limit on land to be granted The cost of reclamation is to be borne by the individuals"

Then with regard to West Bengal he says

> "In West Bengal, pending enforcement of Land Reforms Act, 1955, surplus lands of the ex-intermediaries, raiyats and under raiyats which have been taken possession of by the Collectors are being settled temporarily on year to year lease and for this the Scheduled Castes and Scheduled Tribes take their chance with others"

I need not go on citing instances of the other States I have no time with me This is a very important aspect of the development of the Scheduled Castes and other backward classes

people If millions of acres of land are in the possession of the State Governments, I want to know what is the real difficulty in distributing land to the Scheduled Castes people So far as my State is concerned, it is the smallest State in India We have very little waste land in Government possession We have only 7½ lakh acres of land, but even that we are distributing to the landless peasants and landless agricultural labourers Preference is to be given to the Scheduled Castes people 25 per cent of the land has been reserved for the Scheduled Castes and other landless people

So far as other States are concerned, which have got large tracts of cultivable waste land, they can distribute at least 50 to 60 per cent of this Government land to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to other backward classes people But nothing has been done in this respect Even though some States have taken steps as I have stated earlier difficulties are in the way for the Scheduled Castes and other backward classes people to make use of this distribution of land

Then coming to the other aspect of the economic development of the Scheduled Castes, cottage industries and village industries play a prominent role But here also we can find that the progress made is very unsatisfactory The total provision for the Second Plan period for cottage industries to be started among backward classes people is Rs 547 29 lakhs The amount spent in 1956-57 was only Rs 33,38,022/- and in 1957-58 it was Rs 57,12,698/- The total expenditure during the first two years of the Plan period comes to only Rs 90,50,720/-, that is, much below the yearly average of about Rs 1 crore to be spent for cottage industries for the backward classes

Then coming to the co-operation field also we can find that the Plan provision is Rs. 218·43 lakhs and the amount spent in the first two years was only Rs 88 89 lakhs So, here also we can find that the progress made is rather very slow

With regard to cottage industries, Government have opened certain training centres and in certain other areas training-*cum*-production centres So far as certain training centres are concerned, suitable follow-up programmes are not worked out. As a result of that, the trainees, who get Training in these training centres, cannot start industrial units of their own I would request the Government to change the training centres as far as possible into training-*cum*-production centres and suitable follow-up programme also should be worked out and the trainees should be given liberal financial aid

Then about the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in the services several hon Members have made a reference I do not want to repeat all those arguments but only one point I want to stress, and that is about the lame excuse often put forward by the Government and Government officers that suitable candidates are not forthcoming from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes The employment exchanges' figures given in the Report refute this so-called theory of suitability of candidates The total number of Scheduled Caste Candidates registered in 1956 was 1,78 210 The total number of candidates remaining on the live register at the end of the year 1957 was 92,932 Out of these, 719 were graduates, and 10,813 were matriculates With regard to the Scheduled Tribes also, you can see that the registered number of candidates remaining unemployed on the live register was 19,472 Out of these, 63 were graduates and 729 were matriculates Thus, we can see from the figures furnished by the Employment Exchanges that there were thousands of qualified candidates remaining in the live registers of the various Employment Exchanges and at the same time, the Government put forward this lame excuse that suitable candidates were not forthcoming from

[Shri Kodiyan]

among these people. Therefore, the Government should see the real difficulties in the working of the safeguards. As my hon. friend Shri B. K. Gaikwad has already pointed out, something is wrong somewhere. There is no doubt about it. There are some people who are placed in key positions who do not want the Scheduled Caste people to come up.

**Shri V. P. Nayar** (Quilon): Hear, hear.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member said, somewhere. This hon. Member says, here, here.

**Shri V. P. Nayar:** H E A R.

**Shri Tangamani** (Madurai): They have to be un-earthed.

**Shri Kodiyan:** One word about housing. Of all the items in the programme for the welfare of the Scheduled Castes and other backward people, I must say that this scheme for housing has become very popular with the Scheduled Castes and backward classes. So far as my State is concerned, there is a large demand from the Scheduled Castes people for houses. Last year alone, in my State, more than 1000 houses were constructed for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the last Advisory Committee meeting in my State, demands were put forward by Members unanimously that more money should be allotted for the housing programme. I request the Central Government to give more allotment and provide more money for the housing programme.

About the scholarships, the hon. Member Shri Barman has already dealt with the point. I not only support that view expressed by him, I have also one request to make in this connection. The number of students from the Scheduled Caste people is increasing. It is a very healthy sign. The hon. Education Minister last time, when the Scholarship Board met, told us that from next year onwards, an element of selection will have to be made.

**Mr. Deputy-Speaker:** That has been cleared now.

**Shri Kodiyan:** Yes; we are thankful to the hon. Minister for that. More money should be allotted for that; that is all.

So far as untouchability is concerned, . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** This should not be touched now.

**Shri V. P. Nayar:** Only touch and go.

**Shri Kodiyan:** Only touch and go. Untouchability must be removed. The only point that I wish to make in this regard is that untouchability in our country still prevails. The report says that except in Kerala, Bengal and Delhi, all other States have shown a decrease in the number of cases registered under the Untouchability Offences Act, 1955. This does not mean that in these States, untouchability has come down or disappeared. So far as my State is concerned, there is a Committee for removing untouchability. It meets regularly every month and the situation is taken stock every month, and balance that action can be taken by the police promptly. It is because of that prompt action and vigilance of this Committee that reports come and more and more cases are being registered under this Act.

**श्री साधूराम** (जालंधर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स कामिश्नर की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं । हमारा मकसद यह देखना है कि गवर्नमेंट ने शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासिज के अपलिफ्ट के लिए, उन को ऊंचा करने के लिए, जो कुछ रियायतें दे रखी हैं, उन रियायतों के ज़ेरे-असर हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं । आज जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उस से साबित होता है कि जितनी तरक्की इन लोगों की होनी

चाहिए थी, वह नही हो रही है। उस पर गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने के लिए हमारे लोगों का फर्ज है कि इस सिलसिले में जो त्रुटियां हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने पेश करें। शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासिज की मदद करने के लिए और उन का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा करने के लिए सैकंड फाइव यीअर प्लान में पांच साल के अरसे के लिए ९१ करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। मुल्क की ३६ करोड की आबादी में अगर इस वक्त अदर बैकवर्ड क्लासिज की गिनती तीन करोड की मानी जाये और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की नौ करोड की आबादी को मिला कर बारह करोड लोगो की मदद करने के लिए अगर १८ करोड रुपए सालाना रखे जाये, तो मेरे ख्याल में यह रकम बहुत थोडी है। अगर एक साल मे एक आदमी के लिए डेढ रुपए रखे जाये, तो उस का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा नही बन सकता है। देश मे गरीब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगो की हालत अभी तक काबिलेरहम है—दयायोग्य है। उन को देश के दूसरी जातियो के बराबर लाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उन के लिए बहुत बडा खर्च करने की जरूरत है। इस वक्त हम अगर गावो मे जाते है, तो इन लोगो की हालत को देख कर यह ख्याल पैदा होता है कि दस बारह साल की आजादी के बाद भी वे लोक वही के वही अभी तक पडे हुए है। तालीम मे थोडी सी तरक्की जरूर हुई है, लेकिन वह भी उतनी नही हो पाई, जितनी कि होनी चाहिए थी। इस वक्त जो वजीफे—स्कालरशिप्स दिए जाते हैं उन की रकम बडी थोडी है और वे बच्चो को ठीक टाइम पर नही पहुचते है, जो कि कालेजो और स्कूलो मे अपनी तालीम को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे है। इस के लिए मै ने पिछली दफा भी अर्ज किया था और होम मिनिस्ट्री का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की थी कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट स्कालरशिप्स तक्सीम करता है, उस के काम को जरा तेज करने की जरूरत है। हालांकि साल खत्म हो चुका है और ३० तारीख तक अपनी फीसें अदा करने के नोटिस स्कूलो और कालेजो में लडको को मिल गए है। अगर वे नही करेंगे, तो उन के नाम काट दिए जायेंगे, लेकिन बाज जगह पर अभी तक लडको को वजीफे नही पहुच सके हैं। इस हालत में वे लडके अपनी तालीम को जारी नही रख सकते और उन की तालीम अधूरी रह जाती है और उन के नाम स्कलो और कालेजो मे कट जाते है। वे बेचारे फीसे अदा करने के काबिल नही होते हैं। उन की घरेलू हालत इतनी कमजोर होती है कि वे अपनी तालीम को पूरा करने के अखराजात को पूरा नही कर सकते।

इस के अलावा अभी तक उन लोगो के लिए जमीन की तकसीम का काम गवर्नमेंट पूरा नही कर रही है। आज हमारे देश में बेकार जमीन इतनी है कि काफी लोगो को उस पर एकामोडेट किया जा सकता है, लेकिन हर एक प्रान्त मे स्टेट गवर्नमेंट इस पर ध्यान नही दे रही है। एक तरफ मुल्क में अकाल पड रहा है, अनाज का अभाव है, इतनी महगाई मे अन-एम्पलायमेंट फैली हुई है, लोगो को नौकरिया और काम नही मिल रहे है और लोग भूखे मर रहे है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंटस इस पर ध्यान नही दे रही है कि मुल्क मे बेकार जमीन को सही तौर पर तक्सीम कर दिया जाये। अगर इन बातो की तरफ ध्यान नही दिया जायगा, तो हम यहा पर सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे कायम कर सकेंगे, जिस का कि हम नारा दे रहे है। मै समझता हू कि जमीन को तक्सीम करना एक बहुत बडा काम है, लेकिन उस को किए बिना इस मुल्क में समाजवादी ढाचा कायम नही हो सकेगा।

जमीन की तक्सीम के अलावा उन लोगो के लिए काटेज इंडस्ट्रीज—घरेलू दस्तकारियो—और छोटी दस्तकारियो का भी

[श्री साधूराम]

इन्तजाम करना चाहिए, जिस से कि उन लोगों को काम मिल सके। आज इस देश को आजादी मिलने के बाद भी किसी को रोटी पेट भरने के लिये नही मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा नही मिलता है, रहने के लिए मकान नही मिलता है, तो फिर आजादी का मतलब फेल हो जाता है और उस का कोई मतलब नही रहता है कि आज हमारा देश आजाद है। इस लिए मैं आप की मारफत होम मिनिस्ट्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में जो यह पिछडा हुआ वर्ग है, उस की हालत आज बहुत बुरी है। हम ने इन दस बारह सालों में अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उस मे हम पूरी कामयाबी हासिल नही कर सके है। बारह साल के अरसे में हम इस कलक को इस देश से दूर नही कर सके है। इस पर भी ज्यादा गौर करने की जरूरत है और नए और अच्छे तरीके से इस छुआछूत को खत्म करने के लिए हमे पूरी कोशिश करनी चाहिए।

गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय डिप्रैस्ड क्लासिज लीग और हरिजन सेवक सघ और ऐसी दूसरी सोशल वर्क करने वाली सोसायटियो को छुआछूत खत्म करने के लिए रुपया दिया जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट न उन के लिए एक रैस्ट्रिक्शन पैदा कर दी है कि वे दस परसेंट कान्ट्रीब्यूशन करे और अगर वे नही करेगे, तो उन को वह रुपया नही दिया जायगा। गवर्नमेंट का रुपया देने का मकसद तो छुआछूत को देश से खत्म करना है न कि कानूनी अडचने पैदा करना। मैं समझता हू कि ऐसी पाबन्दिया लगाने मे देश मे जो थोडा बहुत काम छुआछूत को खत्म करने के लिए हो रहा है, वह भी नही होगा और गवर्नमेंट अपने तरीके मे जो काम करना चाहती है वह उस मे सफलता प्राप्त नही कर सकेगी।

**14 hrs.**

हमारे देश मे अभी तक ऐसी हालत है कि लोग अनाज के लिए तरस रहे है, कपडे के लिए तरस रहे हैं और छुआछूत के दबाव से समाज के नीचे कुचले जा रहे हैं। इस सारी हालत को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ ज्यादा होना चाहिए। जो ऊचे लोग, बडे बडे पूजीपति इस वक्त गवर्नमेंट के रुपए से—इस देश के रुपए से काफी फायदा उठा रहे हैं, अगर उस के मुकाबले में इन नीचे गिरे हुए लोगो को इस पिछडे हुए वर्ग को देखा जाये, तो हम पाते है कि उनके लिए बहुत थोडी रकम खर्च की जा रही है और गवर्नमेंट इस बारे मे बहुत कम ध्यान दे रही है। जैसे मैं देख रहा हू कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मसले पर विचार करने के लिए समय भी बहुत थोडा दिया जाता है। चाहे कोई सभा हो या कोई दूसरा फकशन हो, सभी में उनकी समस्याओ पर विचार करने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है और उस चीज को बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसको एक आर्डिनरी काम समझा जाता है। मैं यह समझता हू कि इसके लिये ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये और इस पर इस ख्याल से विचार होना चाहिये कि देश में उन लोगो को ऊचा किये बगैर कुछ नही हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि जो बडे बडे लोग है, जो बडे बडे आदमी है, जो पजीपति है उनको जरा नीचे लाया जाए और जो नीचे है, उनको जरा ऊपर उठाया जाए और अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हू हमारे देश मे समाजवाद आ सकेगा अन्यथा नही। समाजवाद का जो सवाल है अगर हमे इसको पूरा करना है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होगे और जो सही रास्ता है, उस पर हम को चलना होगा। अगर हम उस रास्ते को अख्तयार नही करते है तो मेरा ख्याल है कि समाजवाद आते आते बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और देश मे इस बीच मे ऐसा वातावरण भी फैल सकता है, ऐसा वातावरण भी पैदा हो सकता है कि उन लोगो का इस

चीज पर से विश्वास उठ जाए जो बारह वर्ष से आज तक बना हुआ है। कही ऐसा न हो कि इस तरह की बात हो, इसके लिए भी आपको कुछ करना होगा।

अब मैं जमीन की तकसीम के बारे में कुछ कहना चाहता हू। हमारी गवर्नमेंट का तथा हमारे नेताओ का ख्याल है कि कोओप्रेटिव बेसिस पर हम जमीन के मसले को हल करे। इसके लिए हमें सही रास्ता अख्तयार करना होगा। हम सही रास्ते को, मैं समझता हू, अख्तयार नही कर रहे हैं। पजाब मे मैंने देखा है कि बहुत सी जमीन में जहा पैदावार हो सकती है, जहा काश्त की जा सकती है और उसमे काश्त करके मुल्क के अन्न सकट को हल किया जा सकता है और उनमे उन लोगो को काम में लगाया जा सकता है, जो इस वक्त बेरोजगारी के शिकार हो रहे है उस जमीन मे काश्त करने की कोशिश नही की जा रही है, उस जमीन को इन लोगो का नही दिया जा रहा है। उसकी तरफ कोई ध्यान ही नही दिया जा रहा है। हम बहुत लापरवाही कर रहे है। इतनी जमीन पडी हुई है कि कहना ही नही। वह बजर होती जा रही है। यही नहीं जो जमीन रिक्लेम की जा चुकी है वह भी बजर बन गई है क्योकि उसकी तकसीम नही हो रही है। वहा पर शैड्यूल्ड कास्टस ने कुछ कोओप्रेटिव सोसाइटीज बनाई थी और उनमे जमीन को तकसीम करके काम को चलाया गया था। अब उस चीज को पजाब गवर्नमेंट दुबारा तोड रही है और उनको कोओप्रेटिव बेसिस पर काम करने के तरीके से रोक रही है। वह कहती है कि तुम कोओप्रेटिव सोसाइटी बना करके इस जमीन को काश्त नहीं कर सकते हो। मैंने अपने हल्के में दो चार दिन हुए जा कर देखा है। वहा पर लोगो ने तीन चार साल पहले कोओप्रेटिव सोसाइटीस बना करके जमीन की काश्त शुरू की थी। अब इस चीज को वहा के जो अफसर है, तोड रहे है। जब गवर्नमेंट का ऐसा रुझान है, गवर्नमेंट का ऐसा रुख है, तो मैं पूछना चाहता हू कि वे लोग किस तरह से तरक्की कर सकेंगे। मैं चाहता हू कि इस ओर आपका ध्यान जाए।

सर्विसिस में भी कुछ लोगो की शिकायतें ह। ये शिकायतें चाहे ज्यादा हैं चाहे कम लेकिन हैं जरूर। उनकी शिकायत है कि शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स इत्यादि के नौजवानों को सर्विस में पूरी नुमाइदगी नही मिलती है। मैंने देखा है कि यह बात किसी हद तक जरूर दुरुस्त है। इसके बारे में अगर सैंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कोई डायरेक्टिव जारी करे और इस की जाच पडताल के लिए कोई कमेटीस मुकर्रर करे, चाहे वह पार्लियामेंट के मेम्बरो की हो या स्टेट एम० एल० एस० की जो कि इन क्लासिस से ताल्लुक रखत हैं तो पता चल सकेगा कि सर्विसिस में इन लोगो को पूरी नुमाइदगी देने मे कितनी कोताही की जा रही है और क्यो पूरा हिस्सा नही दिया जा रहा है और वे कमेटीज आपको सुझाव दे सकती है, कि इसके बारे मे क्या कुछ किये जाने की आवश्यकता है। इन सब चीजो के बारे में पूरी रिपोर्ट सैंट्रल गवर्नमेंट के पास आ सकेगी और उसके बाद सैंट्रल गवर्नमेंट उस पर विचार कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम देश मे समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमे ठोस कदम उठाने होगे। मैं समझता हू कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर जो मुकर्रर किये गये हैं, उन्होने बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हू। उन्होने देश में फिर फिरकर दौरे करके, जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश की है, उसको मैंने पूरा पढा है और मैं समझता हू कि जो नक्शा इन क्लासिस का आज हम देखते हैं, उसका सही चित्रण अपनी रिपोर्ट मे किया है। लेकिन मैं समझता हू कि उनके जो अख्तयार है, वे बहुत थोडे हैं। उनको कोई अख्तयार नही है कि जो बेइसाफिया स्टेट गवर्नमेंटस करती है, स्टेट्स में होती हैं,

[श्री साबूराम]

उनको दूर करवा सकें, या उनके बारे में स्टेट्स को कह सकें । वह जो रिपोर्ट देते है, वह पार्लियामेंट के सामने पेश होती है । उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करने में भी कई साल लग जाते है । इसका यह मतलब होता है कि उस रिपोर्ट को भी उतना महत्व नही दिया जा रहाहै जितना कि दिया जाना चाहिये । जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, वह बिल्कुल ठीक है और वह वही नक्शा है जो कि आज हम देश में देखते है । मैं आशा करता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस पर पूरा ध्यान देंगे । मै चाहता हू कि हमारी होम मिनिस्ट्री इस तरफ भी ध्यान दे कि जो बेइंसाफियां हरिजनो इत्यादि के साथ हो रही है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मै देख रहा हू कि आज लोगों पर जुल्म और तशद्दुद हो रहे है और पुलिस की तरफ से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जा रही है । मैंने पिछले दिनो देखा है कि गाधीनगर जोकि दिल्ली के पास ही है, वहा के एस० एच० ओ० साहब ने दो हरिजन लड़कियों पर नाजायज केस बना दिया और उसके बारे में पार्लियामट के चार पाच हरिजन मैम्बरों ने जा करके जाच पड़ताल की और पता लगाने की कोशिश की कि आया वह केस गलत है या सही है । पता लगाने पर पता चला कि वह बिल्कुल गलत है । मैं वहा खुद गया तो मुझे ५०-६० आदमी मिले और वह डी० आई० जी० से भी मिले और उन्होंने शिकायत की कि बिल्कुल गलत केस बनाया गया है । इस तरह के केस कितने ही होते है और मै चाहता हूं कि इन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए । अब वहा पर इसको पुलिस द्वारा प्रेस्टीज का सवाल बना करके हरिजनो को तंग किया जा रहा है । ऐसी ऐसी जो घटनायें होती हैं, इन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । आज भी कुछ अफसर हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं और गवर्नमेंट में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं । इस तरह से वे इन गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे यह दबाना जायज हो या नाजायज हो । मै चाहता हूं कि इस ओर गवर्नमेंट का ध्यान जाये । ये जो बेइंसाफियां है, ये बन्द होनी चाहियें । ऐसे जो अफसर लोग है, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए । अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस तरह की घटनाओं की ओर ध्यान देंगी तो मेरा खयाल है कि देश में इन लोगों की हालत कुछ अच्छी हो सकेगी ।

अब मैं रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हू । पार्लियामेंट के कुछ सदस्यो का यह खयाल है कि जो रिजर्वेशन लैजिस्लेचर्स इयादि में है, वह खत्म कर दिया जाय । अगर ऐसा किया गया तो मै समझता हूं कि यह बहुत ही गलत बात होगी और इसका कारण यह है कि वे लोग अभी तक दूसरे लोगो के बराबर आ नही सके है । जब तक पिछड़े वर्ग दूसरे ऊंचे वर्गों के बराबर नही आ जाते तब तक रिजर्वेशन कायम रहना चाहिये । मै यह भी चाहता हूं कि सर्विसिज में जो इन जातियो के लोगों के लिये रिजर्वेशन है, उसको पूरा किया जाना चाहिये । मै यह भी चाहता हू कि इन लोगों पर ज्यादा रकम खर्च की जानी चाहिए।

इन शब्दो के साथ मै आपको धन्यवाद देता हू और आशा करता हूं कि जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया है, उन पर आप विचार करेगे और ज्यादा इस तरफ ध्यान देंगे ।

**Shri Datar:** My hon. colleague will be replying to all the points raised during this debate. So, I should like to confine myself only to a few of them.

While I was listening to the passionate appeals made by a number of hon. Members and by my hon.

friend Shri B. K. Gaikwad, I felt that it was our duty to do whatever was necessary for these down-trodden classes. They have been suffering for centuries together. Therefore, if some hon. Members use more passion or vehemence, then all that we have to do is to see that our efforts are intensified, and not to get vexed with them. That is the reason why we are trying our best to improve the conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and certain other communities.

I have heard the debate till now, so far as the Scheduled Castes are concerned. I should have been happy if some hon. Members had spoken about the unfortunate conditions in which our tribal people are living in a number of outlying areas. Their condition is also equally miserable, and, therefore, I would request one and all to treat the miserable conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other classes as a national problem The problem of the Scheduled Castes should not be dealt with or should not be considered as only the problem of the Scheduled Castes This should be considered as a problem of the whole nation For that purpose, all of us, including not only the Scheduled Castes Members but also the non-Scheduled Caste Members of Parliament, have to take full share in the great work of regeneration of these unfortunate communities. That ought to be our task.

May I also point out to my brethren of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that their condition is hard, but the condition will not improve merely by using strong language or bad arguments which have no validity? Therefore, I would appeal to those hon. Members to take into account the fact that these are conditions which have come down to us down the ages, and all of us have to try and see that the tempo of improvement, and the tempo of progress are improved as early as possible.

In this respect, may I invite your attention to what the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has said in his report? You are aware, Sir, that for a number of years, it has been a great task, if not a great privilege, of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to tour round the country and try to find out to what extent the conditions are miserable and how they can be improved? Whenever these reports are received, it is our duty to send down his comments to all the State Governments concerned, and it is they that are primarily responsible for improving the conditions along the lines recommended by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Shri B. K. Gaikwad:** They are not doing that. That is our complaint, and that is what we have said

**Shri Datar:** I sympathise with the hon. Member. Let him sympathise with our position also. Let him understand that so far as the executive function in connection with the improvement of the lot of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc. is concerned, that in the primary duty of the State Governments, and we come into the picture for the purpose of supplementing by way of grants what they are doing. The limited functions of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be understood. He has to investigate, and he has to report. Even this work has increased to a large extent, and that is the reason why we have appointed as many as nine regional commissioners or assistant commissioners for the purpose of bringing about a greater degree or measure of co-ordination between the Centre and the States. I am very happy to find that the State Governments also are taking a greater interest in these problems. We had a conference last year of the Ministers for Scheduled Castes and Scheduled Tribes or social welfare in the various States. A number of hon. Members also took part in the general deliberations and I am happy to find that all

[Shri Datar]

the State Governments are now aware of their great responsibility so far as the early improvement of the conditions of all these people is concerned.

May I, in this connection, read only one sentence from the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? I would request hon. Members to note at least for the time being that the conditions are improving, although I would agree with all the hon. Members that the progress has to be as fast as possible, and more substantial. The Commissioner has remarked that there has been an all-round increase in the tempo of work relating to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes during the second year (1957-58) of the Second Five Year Plan period as compared to the last year. Unfortunately we could not spend the whole amount during the first five years in respect of all these communities, and therefore we took care to see that the tempo of progress was increased, and here I have before me the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who has observed an increase in the tempo of work.

**Shri M. C. Jain** (Kaithal): There has been a shortfall in the first and second years.

**Shri Datar:** The shortfall will gradually disappear. There are certain difficulties also which have to be taken into account. All the same, hon. Members will agree that there has been an increase, and I wish hon. Members were in a position to give some appreciation to what the State Governments are doing in this respect. With these preliminary remarks, I shall deal with certain points.

An hon. Member, I believe Shri Sadhu Ram, suggested that the amount of Rs. 90 crores would not be sufficient for the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes. May I point out in this connection that the members of all these castes, tribes and communities are entitled to, and they are getting also, the benefits under the general schemes that have been conceived and are being implemented for the purpose of the general uplift of all the people together. The work that we are doing, the amount that has been kept here or reserved, has been by way of additional grant for the purpose of spending over the interests of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is a point which we have always been taking up with the State Governments, and which we have always been explaining to the hon. Members of these various communities, namely that this is not the sole amount that they are entitled to. Under the ordinary budgetary provisions of the various States, they are entitled to, and may I point out they are getting, benefits also to a certain extent, though it may not be so large as the hon. Members may wish it to be.

Take the community development projects for example. There also we have been finding that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes also are getting more and more benefits from the general budgetary provisions. This is in addition because there are certain special problems so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, and that is the reason why the supplementary budget for the Second Plan of Rs. 91 crores has been conceived of.

My hon. friend actually put in a mathematical calculation and stated that Rs. 91 crores were being given to 18 crores of the Indian population, and then he stated that the amount would be extremely small. That is not the correct position. I would request the hon. Members to understand that this is only by way of supplementing what is being done under the general budgetary provisions by all the State Governments and by the Central Government put together.

श्री गणपति राम : मेरी शिकायत तो यह थी कि उत्तर प्रदेश में आप ने अस्पृश्यता निवारण के लिए चार वर्षों में जितना रुपया दिया था वह सब लैप्स हो गया और खर्च नहीं हो सका । और आप इतनी तारीफ यहां पर कर रहे हैं ।

**Shri Datar:** There are some such problems here and there. We are trying to tackle them, and I am happy to find that the State Governments are more and more conscious of their obligations towards the Scheduled Castes, and the amounts also are graddually being spent. It is our desire to see, whenever certain budgetary provisions are made, as for instance this sum of Rs. 91 crores which has been reserved, that the amounts are spent on the welfare of these various communities. Therefore we are anxious that the State Governments also spend as large an amount as possible out of the ceilings fixed for them

My hon friend raised the question of untouchability. Shri Gaikwad was right m saying that untouchability has been removed by the Constitution, but it is still there. I agree with him that it is still there, the more so in the rural areas I myself have travelled through a number of rural areas and I find that unfortunately it is there, and even where it appears not to be there, subtle untouchability is being practised. That fact cannot be gainsaid, and I am not sure whether the citation of certain villages as being against untouchability or where untouchability has gone, will be correct at all. There are a number of villages throughout India, and there untouchability is there, and for the removal of untouchability we have to take steps which will not defeat the purpose we have in view.

My hon. friend Shri Gaikwad was perfectly right in saying that the condition of the untouchables or Harijans especially in the villages is extremely bad. They are also dependant upon the mercies of the other *savarnas* or other members of the community there. Therefore, we have to be very careful.

If in a village you have only five or six Harijan families as against 50 or 100 other families, naturally you will find that if we take any harsh steps, if we penalise them or take any other steps against them, then the results will have to be taken into account. That is the reason why we have to proceed cautiously even so far as the bringing into effect of the Untouchability (Offences) Act is concerned

As has been rightly pointed out by a number of hon. Members, the Untouchability (Offences) Act is there and its presence on the statute-book has a very large restraining or deterrent effect on those die-hard sections of the Hindu community which still believe that untouchability is a part of their religious obligation. That is entirely wrong. So, the Act has had a good effect.

So far as the actual number of prosecutions is concerned, the difficulty is that in a court of law you have to produce evidence under the Indian Evidence Act, and if it becomes difficult to get evidence, then naturally the cases may not succeed, and in some cases the cases are compromised also. If for example the persons who have suffered, the harassed Harijans, do not come forward, it does not mean that they are not harassed, but it does mean that there is not sufficient quantum of proof for establishing the offence against the people concerned. For that purpose Government are anxious to see that all proper steps are taken, all stern steps are taken. Everywhere, we have issued instructions, the State Governments have issued instructions that whenever there is before a police officer any information, he has to check up, he has to investigate into it and file a prosecution. So far as we are concerned, such action is always there, but unfortunately, on account of the helpless condition in which the Scheduled Castes are living, it is perfecly understandable that they cannot come forward to give evidence because in

[Shri Datar]

some case, where the conditions of the Harijans is very bad, the effect of the giving of evidence itself would recoil upon them. That is the circumstance which all of us have to take into account. My hon. friend made a number of suggestions, but we have to weigh the scales properly; otherwise, the remedy is likely to be worse than the disease. That is the approach which all of us have to keep in view.

So far as the so-called *savarnas* and Harijans amongst Hindus are concerned, as far as possible they have to be brought together. They are the citizens of the same land. They are the residents of the same village. Therefore, we have to carry on our efforts, so far as the moral persuasion of these people is concerned. Side by side with this moral persuasion, we must have an Act which will tell them that in case they go wrong, they will be visited with punishments under the Untouchability (Offences) Act. That is the reason why such a cautious policy has to be followed, though all along it has to be firm.

**Shri Sonavane:** How long this moral persuasion will take us to our goal?

**Shri Datar:** It is bound to take us to our goal. Gandhiji succeeded with moral persuasion even so far as our foreign rulers were concerned. Let the hon. Member have greater faith in ourselves and in the great instrument of non-violence that Gandhiji has made for us.

Then I would deal with scholarships. My hon. friend, Shri Barman, who raised this question, is not here You are aware that during the last five or six years, there have been complaints that the grants were not being received in time, and a number of questions were addressed to the hon. Minister of Education. In some cases, we also found that there were students who got scholarships here and who got scholarships under State Governments' schemes also. My hon. friend was not correct in saying that post-matriculation scholarships were not awarded by States. In some cases, they are. Sometimes there was duplication on account of grants being taken from both the sources by the same person. It has also to be remembered that applications received are in terms of thousands. A suggestion has been made on the floor of the House on a number of occasions, and we had last year a conference of State Ministers. They also suggested that in this case there should be what could be called devolution or decentralisation. So far as this decentralisation is concerned, we are going to lay down standard rules. We are anxious that these students get scholarships as early as possible. A number of steps has been taken by the Ministry of Education. But the consensus of opinion of State Governments was that this work should be entrusted to them and this could be carried out by them m a more effective manner without loss of any benefit to the boys and girls who were getting it. As I have stated, rules are being laid down and according to these rules, we shall find out what is the number of eligible students from among the applicants. Then the Central Government will allot monies out of this fund to the various State Governments. We shall see to it that the State Governments proceed with it and the directions would be very clear that as far as possible, after the commencement of the academic year, scholarships should be immediately granted to the deserving or eligible students so that they can carry on their work as well as possible. This is the object we have in view and this has been stated by way of respecting the wishes of this House itself.

Therefore, this question has been taken in hand. Let us see how it works so far as the current year, 1959-60, is concerned. I am quite confident that the Central Government's and the State Governments' monies in this respect will be pooled together and,

as far as possible, every applicant will have some scholarship. Let us see how it works. We also hold the same view as Shri Barman that education is the best solution for the eradication of all these things which are bad and evil. It will improve the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as early as possible. Therefore, this is what we have undertaken. I am confident that under this scheme, the scholars will get their monies as early as possible.

A question was raised as to whether we shall be in a position to satisfy all the claims or whether we shall be able to give scholarships to all the eligible students among the Harijans. It is expected that when all the resources are pooled together, we shall be in a position to satisfy the claims of almost all these students or applicants. In case any difficulty arises, in case a larger number of students come in, it is a matter which can be considered by the Central and State Governments together. My hon. friend, Shri Barman, who is happily here, need not be apprehensive that this particular step has been taken to deprive the Scheduled Caste boys and girls of the benefits they were getting. In fact, we are anxious that they should get this benefit, and as large a number of Scheduled Caste students get the post-matriculation education as possible. Let there be no misgivings on that score. It is hoped that by the pooling together of the resources of the Central and State Governments, it would be possible to satisfy the largest number of, if not all, the claims of these boys and girls. In case it is found that there are a number of applicants amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other classes where we cannot satisfy them, that is a question which can surely be considered with as large a measure of sympathy as possible not only by the State Governments but by us also.

May I point out in this connection that so far as this question is concerned, in 1951-52, we had set apart Rs. 30 lakhs? In fact, if I were to go to an earlier date, in the year 1942 the then British Government had set apart Rs. 2 lakhs for scholarships to all these boys and girls of all these communities put together. In 1951-52, the figure was Rs. 30 lakhs. That figure has been raised to Rs. 2·25 crores now. Therefore, as he has rightly said, the question of education is one that ought to have the highest priority, and if any such occasion arises, if there are a larger number of eligible applicants than can be provided for, certainly the matter will be duly considered with all the sympathy that it deserves. Let not my hon. friend entertain any misgivings on that score.

**Shri S. C. Samanta** (Tamluk): The hon. Minister has said that the resources of the Central and State Governments will be pooled together. Is it not a fact that the State Governments are giving only Rs. 5, Rs. 10, Rs. 15 or at the most Rs. 20 by way of scholarship, and when all this will be pooled together, will it be available to the students who are enjoying that amount of scholarships now?

**Shri Datar:** I am not sure whether the hon. Member is referring to post-matriculation education.

**Shri S. C. Samanta:** Yes. The amount given is Rs. 5, Rs. 10 etc.

**Shri Datar:** If he is referring to that, may I point out that after all these resources are pooled together, these scholarships would be granted at uniform rates; so far as the different courses are concerned, naturally in some cases, the amount is likely to be more, as for example, in medical or technical courses. In some cases, it is likely to be less. But it cannot be Rs. 5 or Rs. 10, as the hon. member points out.

**Shri Barman:** Is the hon. Minister now stating something which is different from the assurance that he gave

[Shri Barman]

at that time? I did not pursue the matter then. In fact, since 1950, uptil 1958....

**Shri Datar:** We have increased it already.

**Shri Barman:** ....every eligible candidate was given scholarship. He said it would be done this year also. If he sticks to that, it is all right. So, let this be continued as it has been from 1952 to 1958.

**Shri Datar:** Naturally, when we make rules, all these circumstances will be taken into account. I am merely answering my hon. friend's misapprehension that some element of selection will have to be introduced. That is, I think, what he fears.

**Shri C. K. Bhattacharya** (West Dinajpur): May I put a question to the hon. Minister? Will the hon. Minister kindly get a report as to how these scholarships are being utilised by those who get them and whether they are being fully utilised by those who get them?

**Shri Datar:** Is it the hon. Member's contention that the students who get these scholarships do not utilise them properly? I shall surely have that matter looked into because it is our business.

Now, I should like to pass on to other things. So far as the services are concerned, I shall have to be brief. May I request hon. Members not to make light of the requirement of suitability. Now that suitability has a different meaning, minimum suitability is required of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is what has been laid down in our rules. May I invite the hon. Member's attention to the rules that we have made so far as the All India Services are concerned? I find that the number of candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes recommended by the Commission is gradually rising.

Take the case of the Special Recruitment of 1956 of which the results have been out. Take the case of the All India Services Examination the results of which are also out. The number of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates is rising. There were 7 candidates who were selected and one who had been selected in the emergency recruitment—a Scheduled Caste candidate—did not agree to accept the offer. In fact, before we passed him over, I had him called to Delhi through a common friend and tried to persuade him to accept it. Because an I.A.S. officer would be in charge of a district, I would have been happy if the candidate had accepted it. But, for certain reasons of his own—mostly financial reasons, he did not choose to accept it. Thus, you will find that we are trying our best to see—even on a personal plane—that the number gradually rises.

We had a special meeting to get a number of assistants from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The number was fixed at 100; and two Scheduled Caste candidates did not come forward to accept the offer at all. I could understand their reasons—they were placed well. But that also shows that we are trying our best to take as many Scheduled Caste people as possible.

In this connection, it is not a mere degree of the University that is useful. Let the hon. House know that we are trying to take steps to have proper tuition given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe applicants for the All India Services examinations. We addressed a communication to a number of Universities. But it was only the Allahabad University which accepted our grant. We are giving a large grant to them—I believe it is Rs. 58,220—for coaching Scheduled Caste and Scheduled Tribes applicants for appearing at the All India Services examination.

I have before me a notification issued by the Secretary to the Vice-Chancellor of the Allahabad University according to which he has called up applications from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates intending to appear at the next I.A.S. I.P.S. and other Allied Services examination. That would show that special efforts are being made. Let not hon. Members indulge in the usual criticism that Government are not doing anything at all in this respect.

For the last 2 or 3 years we have addressed a number of Universities Some Universities did not take up this question. I am very glad that the Allahabad University has taken it up Our desire is to have about 100 students duly trained for appearance at the All India Services examinations.

I know the difficulties under which the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates suffer. Their domestic conditions are not happy; the particular environment which is necessary for a cultural and intelectual life has to be introduced (*Interruptions*)

**Shri Sonavane:** May I know whether the State Government have been intimated about this scheme that the Universities are to train such students?

**Shri Datar:** This is a public notification It is there so far as the candidates for the All India Services are concerned (*Interruptions.*)

**Shri Sonavane:** Did the State Governments secure the consent of other Universities?

**Shri Datar:** No question of consent at all Various Universities were addressed and it was only this University that took up this question. We are giving them a grant of Rs. 58,000 and odd for the year 1959-60 so that a number of boys will have received proper training and proper general education. I am confident that as a result of such training, in the course of the next few years, a far larger number than what we have will be admitted not only to the All India Services examinations but to others as well.

**Shri Sonavane:** Only one University has accepted this.

**Mr. Deputy-Speaker:** What should he do?

**Shri Datar:** What can I do if they do not accept?

**Shri Sonavane:** Why not persuade on a personal plane. ..

**An Hon. Member:** What is the grant?

**Shri Datar:** Rs. 58,000. (*Interruptions*). I will finish in 2 minutes.

Then, another hon. Member suggested that there ought to be Scheduled Caste or Scheduled Tribe members on the Public Service Commissions. May I point out that so far as the Public Service Commissions are concerned, they are statutory bodies and very important and highly-placed persons are appointed

Therefore, my first submission is that let us try to place the greatest measure of faith in these statutory bodies All the same, I am prepared to concede that just as the members of other castes and communities are there, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are also entitled to be there, not necessarily are representatives of the respective communities. Let it be understood very clearly that they would be highly gifted people, highly experienced people and they would continue to give us very good advice

All the same, as I have stated, so far as the Union Public Service Commission is concerned, we have a member who belongs to the Scheduled Castes. He was the Speaker of the Madras Legislative Assembly and he was persuaded to accept this position. He is there, if I mistake not, for the

[Shri Datar]

last 3 years. There are three States where also we have either Harijan members or a Tribal member. In the Assam Public Service Commission, an hon. lady Member of the First Parliament, is now a member. There are two other States—Bombay is one and Andhra Pradesh is another—where you have Scheduled Caste members or the Public Service Commissions.

**Shri M. R. Krishna:** I do not think there is a Scheduled Caste member of the Andhra Pradesh Public Service Commission.

**Shri Datar:** My hon. friend from Andhra Pradesh does not know! Recently, a retired member.... (*Interruptions*).

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order. Let the hon. Minister be allowed to continue his speech.

**Shri Datar:** Thus, you will find that there are such members or at least 4 of the various Public Service Commissions. As and when it is found possible we shall have more (*Interruptions*).

I am not going to accept the contention that only a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe member will advance the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is the privilege of all of us—not only the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes—to advance the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Therefore, I would say that so far as this question is concerned, we are doing whatever is possible.

Then, I am going to speak only on two or three points within 2 minutes. No contribution is asked for from the Scheduled Castes for the construction of a well. My hon. friend is entirely wrong in saying that. It is quite possible that in the Community Development Areas where certain contributions are asked for from the members of the public; and it might be that from the Harijans also such contributions might come. So far as the Government of India's programme and the State Government's programme for the construction of wells is concerned, we do not ask for contribution from the Scheduled Castes or Tribes.... (*Interruptions*).

**Shri B. K. Gaikwad:** We are told that no separate wells will be provided for the Scheduled Castes as that is the policy of the Government. If that is the policy of the Government, how are you going to provide separate money? .... (*Interruptions*).

**Shri Datar:** Sir, he has raised another question and I am prepared to answer. I have said that we do not ask for contribution from Harijans or others. May I also point out this? In certain case where there was great difficulty for the Harijans to go to the other wells in the general locality, certain wells have been constructed as a matter of convenience and I have myself seen them. I asked why separate wells were being constructed and they pointed out the difficulty and hardship and therefore, they suggested that in certain Harijan localities in villages or towns, such drinking water wells should be constructed. We have also taken the step of making it clear by means of a notification that ever public well shall be open to all the members of all the religions and communities in India. In these circumstances, there is no substance in what he said.

I am afraid the hon. Member has over-coloured the picture in regard to forced labour. If there are any instances of forced labour in India and if any Scheduled Caste or other caste persons are asked to do it, we are prepared to make enquiries. I may in fact tell this House of a report received by me from an hon. Member of this House that there was forced labour in certain islands along the coast of Andhra Pradesh known as

Hari Kota. It was an alarming report from an hon. Member of this House that forced labour was taken and the Harijan labourers of the forests were not being given proper remuneration. I purposely went there and I found that the allegations were wrong. I stated there in the public meeting attended by more than 10,000 people that such an allegation had been made and I was assured by the Harijans and tribals there that there was no forced labour at all. Forced labour would be against the Constitution. Therefore, we shall take every steps to check and eradicate it. . . . (*Interruptions*).

**An Hon. Member:** What is the definition of forced labour? (*Interruptions*).

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order. Shall I allow the hon. Minister to answer questions only?

**Shri Datar:** Forced labour is mentioned in the Constitution; I need not define it. So far as Buddhists are concerned. . .(*Interruptions*).

**Mr. Deputy-Speaker:** Now, the hon. Members should listen to the reply; they have had their say.

श्री गणपति राम : उपाध्यक्ष महोदय, गलत इनफार्मेशन दी गई है . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में हम बाद में फैसला कर लेंगे । अभी तो आप बैठिये ।

**Shri Datar:** So far as Buddhists are concerned, it is extremely difficult to treat them as Scheduled Castes. . . . (*Interruptions*)

**Shri B. K. Gaikwad:** They belong to the weaker sections of the people.

**Shri Datar:** This caste is an indication of Hindu religion. If a Scheduled Caste becomes a Buddhist, then, naturally, he is a Buddhist and not a Scheduled Caste at all. All the same, if for instance, the educational or economic condition of that particular person or family is not satisfactory, he is entitled to have all the benefits on the basis of backward communities and therefore, my hon. friend cannot have it both ways. He can be a Buddhist if he likes but he cannot ask for the benefits of Scheduled Castes and Tribes . . . . (*Interruptions*).

**Shri B. K. Gaikwad:** We are not getting monetary help from anybody.

**Shri Datar:** If, for instance, they are to be treated as members of the other backward classes, they would be entitled to some monetary benefits.

I have tried to answer as many questions as possible and I assure the hon. Members that we shall do every thing that is possible to improve the conditions of the Scheduled Castes and Tribes.

**Shri B. K. Gaikwad:** On a point of information,. . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** There would be another reply by the Minister. Then, he will have a chance.

**Shri Basumatari** (Goalpara—Reserved—Sch. Tribes): Mr. Deputy-Speaker, at the outset I congratulate our Deputy Minister for submitting a report and telling us that the Government is going to change the pattern. I thank our Deputy Minister, Shrimati Alva, for giving us an opportunity to discuss the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes. She was observing while submitting the report that the Government is going to change pattern and procedures whereby the State Governments will be given much more freedom for the development of the under-developed society. I have not a shadow of doubt about her sincerity and the honesty of the Government.

But I would suggest from my experience of ten years in the assembly that the money that has been sanctioned from the Centre was not properly utilised. I do remember how I

[Shri Basumatari]

had to check and fight against the misuse of the moneys and the non-implementation of the schemes. I have found that money was sometimes lavishly sanctioned to the schools and colleges; amounting from Rs. 25,000 to Rs. 40,000 where there were only 7 or 8 tribal students. We do not grudge if there are students belonging to the other advanced communities because that free mixing and staying together in the hostel removes the separatist mentality. I cannot but feel very sad when I find that our hon. Members inside and outside do not understand what the actual provisions in the Constitution are. The hon. Minister has now explained many things and he tried his level best to convince us with argument about the activities of the Government. The report submitted by the Commissioner reveals how the recommendations of the Commissioner had not been implemented by the State Governments while it reveals how they are not taken into consideration in the matter of appointments and how scholarships are denied. For instance, scholarships are denied in institutions like the Air Force, Navy, and the Military Academy Schools on the ground that they are costly. There are also such instances in regard to the newly constituted institutions like public schools and though provision was made for 65 students in the case of a certain school, only two Scheduled Castes have been awarded scholarships and five for the backward classes and none to the Scheduled Tribes. The hon. Minister Shri Datar explained the situation of the Government and how sincere they were. We are very reluctant to accept fully his explanations. We want to know this. How far have these tribals been developed? How far have they been appointed in various departments; and what is the percentage of the tribals in various departments and posts? That is the question. If you go into the details you will find a very low percentage. Our hon. friend, Shri Gaikwad, spoke emotionally and he stated that he felt disappointed as the percentage was not even one taking all the departments of the Government of India. If it was ·01 per cent. or something the percentage is nil. If you take into account the class I posts, class II posts and also other posts in the Centre as well as in the States you will find that not even one per cent. of the reserved posts have been filled up in the departments. Shri Datar just now took pains to explain the position, but I do not agree with it. We can only believe in the reason why this special provision was made in the Constitution and why it was not rightly implemented.

15 hrs.

This special provision was made in the Constitution to bring up these undeveloped, down-trodden and ill-fated people to the same level as the advanced people. This provision was made only because of the desire of Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi wanted to have a State where there was no difference between the rich and the poor. Mahatma Gandhi wanted that all these down-trodden people should be brought to the same level as the advanced people. Mahatma Gandhi wanted that all these ill-fated people should be raised up Mahatma Gandhi said that this was a national problem. Though our hon. Minister says that this is a national problem and to develop these people is a sacred duty, I feel that it is only an expression of sympathy from the lips not from the heart.

Sir, I am not saying all this by way of any criticism. We are very anxious to develop ourselves. We know our position. We have also prestige. We cannot go on begging from door to door all the time. We are only requesting the Government to implement the provisions guaranteed in the Constitution. You have guaranteed these things in the Constitution. We are only requesting the Government,

the House, to be true to their guarantee, true to their words

The hon Minister just now said that Shri Gaikwad was not justified in the criticisms that he made I must say, he was not criticising He was only giving out what he felt He is connected with these activities He knows every inch of his community He knows and he feels the difference between caste Hindus, the developed community and the undeveloped community Therefore, he was speaking with emotion That is because we know how down-trodden we are, how ill-fated we are

Sir, I can give you my experience As far as Assam is concerned, I can say that money was spent lavishly without any proper scheme Our hon Deputy Minister said that they are trying their level best to bring up these people If you take the present position in the States and look into the question in detail you will find that it is a very sad thing The other day I had been to Kerala, where I found that the tribal people are so ill-fated, so wretched that you cannot think they are the citizens of a free country There are some tribals called Malai Pandaran, Kanikkar, Pallıyans and others These tribals are living just like pigeons and pigs Kerala, as you all know, has got the most advanced State As far as literacy is concerned, the percentage there is nearly 80 per cent But literacy among the tribal people is nil They have no land, not to speak of any cultivable land Sometimes they take shelter on the river banks sometimes on the PWD road sites, sometimes by the side of river and so on Many times they are evicted from their places of shelter When I enquired about these people, I was told that some of these tribes were the descendants of kings who fought for the country, who saved the country, who fought against the Moghul Empire. Those people are now down trodden and uncared for They have no home, no she-

Again, if you go to the villages, go to the paddy fields you will find that it is these people who work hard there When I enquired how many of them owned lands, I found that they were not the owners They work hard for the whole day and produce, but in return they do not even get sufficient food to eat They also cannot afford to buy clothes This is the condition, Sir, in an advanced State like Kerala

I also had occasion to visit Rajasthan There also I found how the money was being misused When the Prime Minister visited Chittorgarh in 1955 thousands of Gadodia Lohar—flocked to see the Prime Mimster They were the people who fought against the Moghul Emperor They had taken a vow not to enter Chittorgarh, not to own a house in Chittorgarh, not to enter the houses in Chittorgarh They are living without houses moving in carts from place to place for their livelihood When the Prime Minister told them that the country is now independent and Chittorgarh is our own, and requested them to give up their vow now They are ready to construct their own houses and live there They now want land they now want to construct houses A sum of Rs 3 lakhs has been sanctioned for construction of a colony there But that money is being misused I find that some palatial buildings have been constructed there There is a hostel, but I found that hardly 80 students are living with the result that many rooms are lying vacant When I went to the colony I found that some houses have been constructed and some officers have been appointed In Kerala also we found that many officers have been appointed, but no houses are built for the benefit of these people This is the way money is being misused Therefore, my appeal to the Government is that before they change the pattern of activity, before they change the pattern of aid to the States, they should be very careful in framing the rules and regulations so that the

[Shri Basumatari]

money given cannot be misused by the State Governments.

The same is the case in the matter of appointments. Our hon. Minister just now stated that they have done a lot. But if you will see the rules and regulations in the matter of appointments and also promotions, you will find that there are so many loopholes. I have seen some rules where it is stated that in the matter of promotion the question of Scheduled Castes and Tribal people should also be seen. As I said, there are many loopholes in the rules. It is not that there are no rules under which the appointing authority or the Public Service Commission cannot appoint or promote Scheduled Castes or Scheduled Tribes people, but in actual practice they are not followed as the rules so framed do not indicate clearly. What I say is, you cannot change the mind of the people unless they change themselves.

The hon. Minister just now stated that the Tribal people or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are enjoying special allotments, special facilities along with others, caste Hindus and other advanced communities. Here I want to point out one thing. What do we find in the hostels and schools in different places? From the allotment for Scheduled Castes and Tribes the schools and hostels are built but 20 per cent. or 30 per cent. students belong to the Scheduled castes and Scheduled Tribes, are found and the rest belong to other advanced classes. My point is, why is it that these advanced friends do not realise that they are also enjoying the same facility given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes? My appeal to the advanced communities is that they should feel that they are also enjoying the amount that has been sanctioned for the welfare of the Tribal and Scheduled Castes people.

We should treat this as a national problem. I am sure if the leaders of the country put their heads together and go ahead with the work without any mental reservation, I am sure this problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will not remain. From the various explanations that were given by the hon. Minister Mr. Datar it appears to me that it is only a sort of explanation rather than any concrete action. Therefore, my appeal to the hon. Minister is that he should be more sincere to their words. The people in India, whatever the case may be, think everything in a communal way. They think of their own people only. Therefore, when the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes comes, we also feel in the same way.

It is the duty of the people, it is the duty of the learned friends, it is the duty of the advanced communities, if they want to develop the country, to develop the undeveloped people first. That is the main question.

Then I come to the question of reservations. This is a controversial question, whether reservations should be there or not.

15·09 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

I am sure that if reservation is not continued, then even the small representation that we have now will be lost. For instance, in this House of about 504 Members, 76 are from the Scheduled Castes and 31 from the Scheduled Tribes. If the reservation is not continued, I doubt whether even the five per cent. or so will be returned to this House in future.

Take also the State Legislative Assemblies. Out of a total of about 3,202 seats in the Legislative Assemblies in the States, 470 are for the Scheduled Castes and 221 for the Scheduled Tribes. So, in the State Legislative Assemblies also, I doubt whether even the five per cent. will be returned; not to speak about 3 per cent., I doubt whether even two per cent. will be

returned to the State Assemblies, if the reservation is not continued. That too I doubt whether any of them will be returned on Congress tickets. Now, in this democratic country, if only five or two per cent. are returned to the Legislative Assemblies and Parliament, how can you help the development and amelioration of these communities, who will plead their cause?

The other day, while the question of democracy and representation was raised, our Home Minister said that this House is governed not by the minority but by the majority. Well, in a democratic country we quite realise that the democratic country should be governed by the majority. But when the question of democracy comes, even if the two per cent representation that we used to get is not achieved, either in the State Legislative Assemblies or in Parliament, how can you claim that there is proper amelioration and representation? And how can we also claim that adequate representation has been given?

Now, what about the representation for the tribal people areas in this August House itself, there is not a single member from the tribal areas functioning as a Minister in the Cabinet, or as a Deputy Minister. There is no one belonging to the Scheduled Tribes who is a Minister. This is sheer negligence shown to the backward minorities, the Scheduled Tribes, who are only 31 in number in this House. No body is here to hear our voice, and nobody to look to our demands. Here also we are badly neglected.

While the question of democracy is raised, when the question of democracy is voiced, then we must see how the down-trodden people are to be raised and given representation. I have no doubt about the sincerity of the Deputy Minister. She spoke the other day with emotion. Last year also, she gave her reply to the speeches in connection with this Report, and she was emotional. She understands very well, but by understanding if not following it with action will be of no good.

I wish also to congratulate the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In his report he reveals all the difficulties and has shown how his recommendations are not implemented and how action has not been taken on certain recommendations. There also he is clear. So, I wish to congratulate the Commissioner also

In the case of the reservation of seats, the Constitution itself has guaranteed where it was prescribed provisions to determine whether reservation should continue and not. I shall just read out the provisions

**Mr. Chairman:** The hon Member's time is up

**Shri Basumatari:** I shall finish in two minutes From time to time, we are discussing the question of continuation of reservation About reservation, no clear answer is given as to whether it will be continued or not. According to article 339 of the Constitution, a Commission has to be appointed to report on the administration of the Scheduled Areas. Article 339 says·

> "The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

So, it is clear that some Commission should be appointed.

Now, about reservation, according to article 334 of the Constitution, reservation of seats and special representation to certain communities will

[Shri Basumatari]

cease on the expiration of ten years from the commencement of the Constitution. So, if nothing is done now, automatically the reservation will go. To decide whether the reservation should be continued or not, a Commission has to be appointed. That should be reported by a Commission, but it has not been constituted. So, it is a question of a very great anxiety to us. The guarantees given in the Constitution should be implemented, and we should be sincere in carrying out the guarantees. This is the right time to appoint Commission.

With these words, and with thanks to the hon. Deputy Minister who spoke with emotion, I close I believe that, along with emotion, she will try her level best to improve the conditions of the backward people as referred to in the speeches in the debate which were full of emotion

With these words, I resume my seat.

श्री उइके : सभापति महोदय, अभी हमारे राज्य मंत्री महोदय ने जो बहस में हस्तक्षेप करते हुए उत्तर दिया है उससे हम लोगों को बहुत संतोष नहीं हुआ है ।

उन्होंने कुछ कोटेशंस शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट से दिये हैं । उस रिपोर्ट की एक प्रति मेरे पास भी पड़ी है और वह काफी मोटी रिपोर्ट है । जिन माननीय सदस्यों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं होगा वह यह अनुमान लगायेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बहुत से काम हुआ करते हैं लेकिन इस रिपोर्ट में क्या क्या रहस्य हैं उसको शायद बहुत कम सदस्य जानते हैं । खुद हमारे आयुक्त महोदय अपनी रिपोर्ट में कहते हैं और उनके मैंने थोड़े से कोटेशंस निकाल कर रखे हैं । उनका कहना यह है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए चहुमुखी यत्न किये गये । एक तरफ तो यह लिखते हैं और दूसरी तरफ यह लिखते हैं कि अनेक राज्य सरकारें इस दिशा में पूरी तरह जागरूक नहीं हैं । यह भी खूब है कि एक तरफ तो कहते हैं कि चहुमुखी यत्न किये गये, काम किये गये लेकिन दूसरी तरफ वे खुद कबूल करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स जागरूक नहीं हैं । इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में पूरी जानकारी एकत्र नहीं हो सकी यानी इस रिपोर्ट में वह पूरी जानकारी नहीं दे सकते । इस में आदिवासियों और हरिजनों के सम्बन्ध में अधूरी जानकारी रहती है । इस के बाद यह कहा गया है कि उच्च नौकरियों के सम्बन्ध में राज्यों में तो सफलता मिली है, परन्तु केन्द्र में स्थिति संतोषजनक नहीं है । इस में उन्होंने अपनी ऐसी राय दी है । मुझे उस के सम्बन्ध में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है । उस के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कह दिया है । उन्होंने इस का कारण यह दिखाया है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं । वे कैसे मिलेंगे ? क्या इस के लिए धुवाधार प्रचार किया गया है कि उपयुक्त उम्मीदवार मिलें ? कुछ भी किया नहीं गया है । इस को मैं छोड़ देता हूं । बहुत से सदस्यों ने इस विषय को लिया है ।

फिर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को भूमिहीन आदिवासियों और हरिजनों को बेकार पड़ी हुई जमीन देनी चाहिए । मैं यह कहूंगा कि उन्होंने यह जो सुझाव दिया है, वह आज का नहीं है—यह सुझाव बहुत बहुत दिनों से देते हुए चले आ रहे हैं । सब लोग कहते हैं कि आदिवासियों और हरिजनों को परती जमीन देनी चाहिए । लेकिन होता क्या है ? परती जमीन न तो भूमिजनों को और न आदिवासियों को मिलती है । अभी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्रश्न किया गया था, जिस का उत्तर यह दिया गया कि इस की जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं

है। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, मैं अपनी स्टेट के आदिवासियों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि भूमि तो आदिवासियों को एक एकड भी नहीं दी गई, लेकिन उन के पास जो भूमि है, उस का गवर्नमेंट खुद एक्सप्लायटेशन कर रही है। स्थिति यह है कि तीन तीन पीढ़ियां गांव में बसी हुई हैं—आजा मर गया, बेटा मर गया, नाती बूढा हो रहा है, पूरे गांव का गांव बसा हुआ है, पूरे गांव की खेती उस पर है, लेकिन गवर्नमेंट आज कहती है कि तुम्हारा पूरा गांव बड़े जंगल में है, तुम हटो, जमीन भी छोड़ो। ऐसा एक नही, आदिवासियो के सैकड़ों गांवों मे हो रहा है और आदिवासियों में तहलका मचा हुआ है। दो दो एकड़ जमीन के लिए ७०० रुपये, ९०० रुपये फाइन एक बार नही, दो दो बार, बल्कि तीसरी बार किया जा रहा है। मै गवर्नमेंट, गृह मत्री और आयुक्त साहब का ध्यान खास तौर पर इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उन लोगों की जमीन दी जाय, या न दी जाये, लेकिन उन के पास जो पुरानी बरसो और पीढियों से जमीन है, वह उस की रक्षा करें। आज गवर्नमेंट खुद उस को एक्सप्लायट कर रही है।

छोटे छोटे घरेलू उद्योगो के बारे में भी लिखा गया है और बड़ी जोरदार सिफारिश की गई है। लेकिन होता क्या है ? जहां बास पैदा होता है, वहा बेत का काम सिखाया जाता है और जहां सन पैदा होता है, वहा कपास का काम सिखाया जाता है। इस तरह छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के कामो से कुछ नही होने वाला है।

शिक्षा के विषय में उन्होंने संतोष प्रकट किया है। उन्होंने बड़े छात्रावास बनाने पर व्यय करने की आलोचना की है। यह बडी प्रशसनीय बात है। उन्होंने कहा है कि इस में से पैसा बचा कर यह पैसा स्कालरशिप्स में देना चाहिए। स्कालरशिप्स के सम्बन्ध में हमारे सभापति महोदय ने जो कुछ भी कहा है, उस का समर्थन करते हुए मैं यह कहता हूं कि इस साल से स्टेट की तरफ से पोस्ट-ग्रेजुएट स्कालरशिप दिये जाने वाले है। स्टेट खुद जो हाई स्कूल स्टेज पर स्कालरशिप देती है, उन की क्या हालत है ? उस ने अभी हाई स्कूल स्टेज पर स्कालरशिप नही दिये हैं। तब सेन्टर से जो पोस्ट-मैट्रिक और कालेज वालो के लिए जो स्कालरशिप दी जाती है वह भी राज्य की तरफ से—उनकी हालत क्या होगी ? वे तो दो सालो तक नही मिलेंगी।

हमारे मंत्री महोदय आदिवासियों और हरिजनो के खर्च के विषय में करोडो रुपये की गिनती करते है और हमारे सदस्य भाई भी सोचते हैं कि सचमुच करोडो रुपये आदिवासियों और हरिजनो के लिए खर्च किये जाते है। प्रथम पच-वर्षीय योजना मे इस काम के लिए ३९ करोड रुपये रखे गये थे, जिस में से २६ करोड़ ही खर्च किये गये और १३ करोड खर्च नही हुए। यह हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट मे है।

एक माननीय सदस्य शेम, शेम।

श्री उइके : इस सम्बन्ध में मैं अपनी स्टेट का उदाहरण देना चाहता हू। वहां लगभग ५ करोड रुपये द्वितीय पच-वर्षीय योजना के लिए मंजूर हुए है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के तीन साल बीत गये है, लेकिन अभी सिर्फ ९४ लाख रुपये खर्च हुए है। मैं समझता हू कि यही अवस्था सारे हिन्दुस्तान में होगी। निर्धारित रकम में से आधी रकम भी खर्च होगी, या नही, यह मेरी शंका है।

प्रश्न यह है कि पौने दो करोड आदिवासियो के ऊपर ४७ करोड का खर्चा क्यों दिखाया गया है ? क्या सरकार सिर्फ आदिवासियों के लिए सड़के बनाती है ? सारे हिन्दुस्तान में कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स हैं, कुंए, सड़कें, स्कूल, कालेज, दवाखाने बनते है ; वे किसी जाति के नाम ऊपर नही लगाये

[श्री उइके]

जाते हैं। तो फिर इन ४७ करोड़ में से जो सड़कें, कुएं, स्कूल, कालेज वगैरह बनाये गये हैं, उन को आदिवासियों के नाम पर क्यों लगाया जाता है ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों में मन-मुराद पैसा खर्च किया जाता है। इस में से आदिवासियों को कौन सा पैसा मिलता है ? सरकार जो फ़ी माफ करती है, या जो स्कालरशिप्स देती है, या जो थोडी सी रिजर्वेशन रखती है, या उम्र में जो थोड़ी सी सहूलियत देती है, केवल वह ही सही मानों में आदिवासियों और हरिजनो को सहायता मिलती है, जिस का अर्थ यह है कि उन को करीब डेढ़ करोड रुपये की सहायता मिलती है ।

यह भी कहा गया है कि आदिवासियों और हरिजनों को लायन्ज शेयर मिलता है। बड़ी भारी सरकार ने उन को चीज दे दी है। ज्यादा से ज्यादा चार पाच करोड़ रुपये सही मानों में आदिवासियों और पिछडी हुई जातियों को मिलते है। कहा गया है कि लायन्ज शेयर इन लोगों ने ले लिया है,इसलिए इस में धीरे धीरे कमी कर दी जाये। मैं कहता हूं कि लायन्ज शेयर आदिवासी हरिजनों को नहीं मिलता है। उन के नाम पर दूसरे लोगों को—बीच के लोगों को वह मिला हुआ है। आज सोशल वर्कर की एक जात का निर्माण हो गया है और उस ने पैसे का पूरी तरह दुरुपयोग किया है और वह कर रहा है। उस ने अपने काम के लिए इस पैसे का उपयोग किया है। क्यों मुफ्त में हरिजनों और आदिवासियो के विषय में इस तरह आंकड़े दे कर इस हाउस को बताया जाता है कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए खूब काम किया जाता है ।

अभी उपमंत्री जी ने बताया कि सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में ६१ करोड़ रुपये रखे गये हैं। हिन्दुस्तान में सब जगह रेल की लाइनें और सड़कें बनती हैं। क्या वे किसी जाति के नाम पर लगाई जाती हैं। नहीं। फिर जो सड़कें आदि हमारे यहां बनाई जाती है, वे हमारे नाम क्यों नोट की जाती हैं ?

जो छोटे छोटे काम होते हैं, वे किस तरह से होते है ? कुछ इन्टेन्सिव ब्लाक्स बनाये गये हैं, जिन के बारे में कहा गया है कि वे आदिवासियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। एस्टीमेट्स कमेटी ने इन इन्टेन्सिव ब्लाक्स का पोल खोला है। वह मैं आप को बताना चाहता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में स्पेशल मल्टीपरपज ब्लाक्स के विषय में कहा गया है कि आदिवासियों के लिए एक ब्लाक पर २७ लाख रुपया खर्च किया जाता है। एस्टीमेट्स कमेटी को एक ब्लाक ऐसा मिला, जिस में केवल २३३४ आदिवासी है। मैं यह पूछना चाहता हू कि केवल २३३४ आदिवासियों पर इन्टेन्सिव ब्लाक मे २७ लाख की रकम डालना क्या धोखा नही है ? यह पार्लियामेंट को धोखा दिया जा रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : क्या खा गये वह रुपया ?

**श्री उइके** खा नही गये ।

**एक माननीय सदस्य** तो ?

**श्री उइके** यह २७ लाख रुपया उन के नाम लिख दिया गया है। यह पाच साल के लिए है। इन्टेन्सिव ब्लाक आदिवासियों के लिए बना हुआ है, लेकिन उस में केवल २३३४ आदिवासी है ।

यह कहा गया है कि कम्यूनिकेशन्ज पर ज्यादा पैसा खर्च होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आदिवासियों का जितना एक्सप्लायटेशन किया जा रहा है, उस की कोई हद नहीं है। इन स्कीमों से आदिवासियों को जितना लाभ हो रहा है, जितना उन का कल्याण हो रहा है, उस से ज्यादा उन की हानि हो रही है। मन-मुराद कम्यूनिकेशन्ज

खोल दिये गये हैं, सड़कें बना दी गई हैं। इस सुभीते से बाहर से लोग उन लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि उन को एक्सप्लायट करने के लिए जाते हैं। वे उन की इकानोमी को खत्म करते हैं। मैं इस विषय में ज्यादे से यहां नहीं बताना चाहता हूं। मैं पार्टी मीटिंग में विस्तार से कहूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन रोड्ज से हमारा पूरी तरह से एक्सप्लायटेशन हो गया है। रोड्ज बनाना जरूरी है। उस में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को सेफगार्ड्ज देने चाहिएं। मैं उदाहरण दे कर बताना चाहता हूं किस तरह रोड खोलने से किस तरीके से हमारा एक्सप्लायटेशन हुआ। मुझे आशा है कि हमारे हाउस के माननीय सदस्य इस एक्सप्लायटेशन के विषय को ध्यान से सुनेंगे।

मैं १९५६ के हितवादा में से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस से माननीय सदस्य यह न समझें कि यह कोई पुरानी चीज है।

"Timber is gold! Believe it or not, at Hepurkasa village timber sold previously for mere Rs. 420, has now brought Rs. 5,365..."

मैं अपने साथी श्री मुचाकी कोसा गत संसद् सदस्य को ले कर गया। राष्ट्रपति को शिकायत की, गवर्नर को शिकायत की। ट्राइबल वैलफेयर मिनिस्टर वहां पर गये। उस टिम्बर को आक्शन किया गया और जिस टिम्बर को पहले ठेकेदारों ने ४२० रुपये में लिया था, उसके ५३६५ रुपये मिले।

इसके बाद दूसरा केस देखिए—

"Similarly, Chamru of Chahchar now got Rs. 3,840 for his previous Rs. 200 and Pandu of Michewada got over Rs. 20,000 for his previous Rs. 4,850. And the happiest was Lachmi Bai of Amagarh who was thinking even the amount of Rs. 20 given by the contractor more than enough and here now she was wondering what to do with Rs. 1,200 which she was getting for the same timber."



इस से माननीय सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों का कितना एक्सप्लायटेशन किया गया है। कंट्रैक्टर्ज ने उन लोगों का बड़ा एक्सप्लायटेशन किया है। गवर्नमेंट द्वारा उन के टिम्बर को जो ठेकेदारों ने खरीदे वे आक्शन कर के उन को ३२५,००० दिलाये गये, जिस में से ८१,००० रुपये उन्होंने स्माल सेविंग्ज स्कीम में जमा करा दिये। बस्तर जिले की एक तहसील भानुप्रतापपुर में वह फारेस्ट आता है। जो आदिवासियों की जमीन पर है जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ है। अगर गवर्नमेंट उन पर पैसा खर्च नहीं करती है तो न करे, लेकिन उनकी करोड़ों रुपये की जो दौलत है, वह तो कायम रखे, उनके एक्सप्लायटेशन को तो रोके। उनकी आर्थिक स्थिति अगर सुधर जाती है तो कोई जरूरत नहीं आपके स्कालरशिप्स की या दूसरी मदद की। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा एक्सप्लायटेशन बन्द हो। आज तो एक्सप्लायटेशन शुरू हो गया है। आज तक वह नहीं होता था। आपने जो सड़कें बनाई हैं उनसे होने लग गया है। हमारा कल्चरल, पालिटिकल तथा दूसरी तरह से एक्सप्लायटेशन हो रहा है।

थोड़े दिन हुए हमारे श्री मसानी साहब ने जोकि शायद बम्बई के रहने वाले हैं और बिहार से एक आदिवासी इलाके से चुन कर आये हैं—शायद सिर्फ यही उनका नाता आदिवासियों के साथ है—यह कह दिया था कि अगर आदिवासी इलाके में सहकारिता के आधार पर खेती होगी तो खून बह जायेगा। यह जो बात कही गई है उनकी तरफ से यह हमारे ऊपर एक कलंक की बात थी। जब हमें कोई रिप्रेजेंटेशन मिलना बन्द हो जायेगा, तब तो मैं समझता हूं कि हमारा पालिटिकल एक्सप्लायटेशन भी इसी तरह होना शुरू हो जायेगा, अगर हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा, तब इसी तरह की बातें हुआ करेंगी। जिस के पास पैसा होगा वह कलकत्ते का राजस्थान से खड़ा हो कर जीत कर आ जायेगा,

[श्री उइके]

कोई बम्बई का रहने वाला होगा तो वह बिहार में किसी आदिवासी क्षेत्र में खड़ा होकर जीत कर आ जायेगा, पंजाब वाला मध्य प्रदेश से जीत कर आ जायेगा और ये सब पैसे के बल पर जीत कर आयेंगे। आदिवासी जीत नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा तो कोई आदिवासी हरिजन जीत करके आने वाला नहीं है और न कोई उनकी शिकायतें आपके सामने रखने वाला होगा। मैं समझता हूं कि यह आखिरी वक्त है जबकि मैं अपना दर्द आपके सामने रख रहा हूं। मैं मानता हूं कि बहुत से हमदर्द हमारे हो सकते हैं जोकि हमारी तकलीफों को यहां रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि तब देश को खतरा पैदा हो जायेगा। मैं अपनी बात नहीं करता हूं लेकिन सभी हरिजनों तथा दूसरे वर्गों की बात करता हूं। उनकी बात कहने वाला कोई भी होगा। अगर श्री मसानी साहब जैसे लोग चुन कर आ गये और उन्होने पौन दो करोड़ आदिवासियों के खिलाफ झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया, झूठी हवा फैला दी, तो जरूर खतरा पैदा हो सकता है। तब सहकारिता के आधार पर अगर खेती की गई तो जरूर खून खराबा होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आदिवासियों के अन्दर आज भी कोआप्रेशन की भावना विद्यमान है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज भी होशंगाबाद जिले में जा कर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे अगर किसी आदिवासी किसान के पास काश्त करने के लिए बैल नहीं है, तो बस्ती भर के सारे आदिवासी काश्तकार उसके खेत में चले जाते हैं और खेत को जोत देते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा कोआप्रेशन हमारे अन्दर है। हमारे अन्दर कम्युनिटी लाइकिंग है और यह ट्रेडिशनल चीज है। हम में आपस में एकता है। हां अलबत्ता खून खराबा उस वक्त होगा जब हमारा एक्सप्लायटेशन पूरी तरह से शुरू कर दिया जायेगा।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जंगल के मामले को लेकर आदिवासियों के ऊपर गोली चल गई है। उसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं आपको इस चीज को बतलाऊं। ये नई नई बातें हैं जोकि मैं आपको बतला रहा हूं। सरगुजा जिले के खोबी गांव में जंगल के मामले को ले कर गोली चल गई। सिहावा में, जोकि रायपुर जिले—मध्य प्रदेश— में है, जमीन के मामले को लेकर पांच सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासियों का जब एक्सप्लायटेशन शुरू किया जाता है, तो उस वक्त चाहे वे उसका जवाब नहीं देते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती है लेकिन धीरे धीरे वे सब चीज समझने लग जाते हैं और अपना जवाब उस तरीके से देना शुरू करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की आर्थिक समस्या जंगल के साथ बंधी हुई है। ये जो जंगल काटे जा रहे हैं, इससे हमारी इकानोमी नष्ट हो गई है। मैं आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूं कि वे कोरी बातें न करें।

मैं एक बात को कहना भूल गया हूं जोकि अब मैं कहना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने दो तीन दिन हुए एक स्टेटमेंट दिया था या व्याख्यान दिया था जोकि पेपर्स में छपा था और उस में उन्होने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में इस कोआप्रेटिव फार्मिंग को अभी लागू नहीं किया जायेगा, जो बैकवर्ड इलाके हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता इसको लागू किया जायेगा। आदिवासियों में कोआप्रेशन की जन्मजात भावना है। उनके बारे में मैं समझता हूं कि बेजवाबदार बात कोई नहीं कही जानी चाहिये और इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं उनका पालिटिकल एक्सप्लायटेशन करना है। श्री मसानी के भाषण से शायद हमारे प्रधान मंत्री महोदय

ने भी पीने दो करोड़ आदिवासियों के बीच में कहा कि सहकारिता का काम वहां नहीं होगा। मैं एक बात को मानता हूं कि खून खराबा हो सकता है लेकिन उसी वक्त जबकि आप चतुर लोगों से हमारा एक्सप्लायटेशन करवायेंगे। अगर उन्हीं आदिवासियों के द्वारा आप काम को करवायेंगे और उन पर विश्वास करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मूवमेंट है यह सर्वप्रथम आदिवासी इलाकों में ही सफलता प्राप्त कर सकेगी।

मैं समझता हूं कि मैं अन्तिम भाषण कर रहा हूं क्योंकि दूसरे हाउस में गरीब लोग आने वाले नहीं है। यह बात ठीक है कि आदिवासी चाहे गरीब है, उन में यह भावना है कि चाहे आप उन के साथ हजार छल कपट कर लें, हजार रुपया का लालच भी उन को दे लें, आदिवासी बराबर चुन कर आयगे। लेकिन उन के नाम उंगली पर गिने जा सकते हैं। ऐसे दो चार व्यक्ति हो सकते है जो आ सकते हैं। तब उन का पालिटिकल एक्सप्लायटेशन भी शुरू हो जायेगा और यह देश के लिये नुकसानदेह ही साबित होगा। इस तरह से देश को जो हानि होगी, उस हानि से अगर देश को बचाना है तो आदिवासियों के बारे में जो भी निर्णय आप करते हैं, उस को सोच समझ कर करें।

अन्त में मैं जयप्रकाश नारायण जी ने जो इन लोगों के बारे में बम्बई में कहा है, उस को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और अपना भाषण खत्म करना चाहता हूं। उन का कहना है :—

> "दुनिया के उन देशों की बात छोड़ दें जो आज तक पहुंचने की कोशिश में हैं, फिर भी विकास की दृष्टि से भारत कई देशों से आगे बढ़ा हुआ है, इस से इन्कार नहीं किया जा सकता, तब तो यह एक सर्वथा अचरज की ही घटना है, कि बम्बई प्रदेश में सतपुड़ा की घाटियों में बसे ३५६ ग्रामों की ६० हजार आदिवासी जनता स्वराज्य, नेहरू और महात्मा गांधी तो दूर, राम और कृष्ण तक के नाम नहीं जानती।"

यह है हमारे आदिवासी कल्याण विभाग की आदिवासियों की भलाई करने का काम। यह हमारे आदिवासी भाइयों की बम्बई में हालत है और उस बम्बई प्रान्त में जहां पर सब से अच्छा काम आदिवासियों के लिये लिखा हुआ है। यह चीज किसी के लिये भी कलंक वाली सिद्ध हो सकती है। जयप्रकाश जैसे व्यक्ति या आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्ति किसी से पैसा ले कर काम करने वाले नहीं है। वे सच्चे अर्थों में सोशल वर्कर्स हैं और तन मन से इस काम को कर रहे हैं। ठक्कर बापा भी उसी कोटि में आते है। वह सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी से ऑनरेरियम नहीं लेते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि पैसा ले कर जो सोशल वर्क करने वाले हैं, वे मनमाने ढंग से काम करते हैं और हरिजन तथा आदिवासियो के नाम पर पैसा कमाते है।

भूदान नेता जयप्रकाश जी ने आगे कहा है :—

> "वे आदिवासी प्राकृतिक खेती करते हैं। कृषि साधनों की इन्हें कतई जानकारी नहीं है और बाहरी दुनिया पर वे सिर्फ नमक के लिये निर्भर रहते है।"

यह जो जयप्रकाश जी ने उन का चित्र खींचा है, यह बिल्कुल सही चित्र है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आप का ध्यान जाय।

चूंकि समय कम होता है, इस कारण जल्दी में बहुत सी बातें छूट जाती हैं। यह अन्तिम चित्र है, जो मैं ने आप के सामने रखा है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भविष्य का जो खतरा है, जहां तक हो सकेगा उस को टालने की कोशिश की जायगी।

**Pandit Munishwar Dutt Upadhyay** (Pratapgarh): Mr Chairman, Sir, a number of hon. friends have spoken and they have emphasised really very important points.

**श्री प० ला० बारूपाल** (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातिया) हिन्दी में बोलिये ताकि सब समझ सकें ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** मैं इसलिये अंग्रेजी में बोल रहा था ताकि मंत्रिणी महोदया समझ सकें ।

**श्रीमती आल्वा** : मैं भी हिन्दी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूं ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** सभापति महोदय, आज का विषय हमारे देश के उस वर्ग से सम्बन्धित है जो वर्ग कि स्वय अपने लिये कुछ करने में समर्थ नही हो सका है । सामाजिक कारणों की वजह से वह ऐसी स्थिति में है जिस में कि समाज के दूसरे वर्गों का तथा देश की सरकार का भी उस पर विशेष ध्यान जाना आवश्यक है ।

बहुत सी बातें हमारे मित्रो ने जो अभी कही हैं, उन को मैं भी अगर दोहराने लगू तो बेकार ही मैं आप का समय लूगा । बहुत सी बातें बतलाई गई है जिन में से कुछ ऐसी बातें भी है जिन की जानकारी मुझे खुद भी रहती आई है और जिस की शिकायत बार-बार मैं सुनता आया हू । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट्स को धन की स्वीकृति सीधे दी जायगी इस से काम बडी प्रगति और सफलता के आगे बढ़ेगा । लेकिन हमारे मित्रो ने कहा कि इस से और बाधायें पैदा होने का अन्देशा है । इस में कोई सन्देह नही है कि जहा तक वजीफो का मामला है, स्कालरशिप्स की बात है, जोकि हरिजन विद्यार्थियो या दूसरे विद्यार्थियो को मिलता रहा है, अक्सर उस के ठीक वक्त से मिलने में बडी दिक्कत होती रही है । तो क्या सहूलियत पैदा हो सकेगी क्या नही, वह तो मैं समझता हूं कि इसी मिसाल से समझ लेनी चाहिये । लेकिन मैं तो एक पहलू और जो इस रिपोर्ट का है उस के सम्बन्ध में विशेष कर निवेदन करना चाहता था ।

यह रिपोर्ट जो आज हमारे सामने है वह उन वाकयात को हमारे सामने रखती है, वह मसाला हमारे सामने रखती है जो कि दो, पौने दो, डेढ़ या एक वर्ष पहले का है । इस बीच में, साल, डेढ़ या दो साल में हालत क्या हो गई है । हम कहां के कहा पहुच गये, इस का कुछ पता नही है । ऐसी हालत में जो बहस हमारे सामने चल रही है, कितनी वास्तविक है और कितनी बहस हम बातो पर कर रहे हैं, यह मैं नही समझ पाता हू । ऐसी स्थिति में चूकि रिपोर्ट इतनी लेट आती है, हमारे पास कोई कीमत इस की नही रह जाती । मैं निवेदन करूगा कि मुझे जान यह पडता है कि या तो वहा काम करने वालो की कमी है, या दिक्कत दरअस्ल इस मैटीरियल के मिलने में हो जाती है, जिस की वजह से देर हो जाती है । जैसे मेरे कुछ मित्रो ने शिकायत की, हम ने जब महकमा कायम किया है तो उस महकमे को पूरी सहूलियत, पूरा स्टाफ, पूरे आदमी, पूरा सामान और पूरे साधन देने चाहियें ताकि हमारा यह विभाग कारगर हो सके । जिस काम के लिये वह नियुक्त हुआ है, वह काम भी कुछ हो सके, केवल यह न हो कि यहा वहा घूम-घाम कर रिपोर्ट हमारे पास आ गई, इन बेचारो को कोई और अधिकार नहीं, कुछ मतलब नही, कोई उन की सलाह मानने वाला नही, कोई सुझाव सुनने वाला नही, एक रिपोर्ट यहा आ गई और उस पर हम लोगो ने खडे हो कर बहस कर ली । उस में कोई प्रस्ताव पास होने वाला नही, कोई पाबन्दी होने वाली नही, कोई फैसला होने वाला नही । फिर इतना ही नही, हमारे मंत्री जी ने कहा कि यह सारा कारोबार तो स्टेट में हो रहा है, स्टेट सरकारो को सब कुछ करना है, वहा ही लोगों को जानकारी होनी है, वहा ही वायुमंडल

बनना है, वहां ही इस का सारा काम हो रहा है । और, हमारे यहां तो बहस भी हो जाती है, थोड़ा सा अवसर होता है हमारे मित्रों को कुछ कहने का भी, हम को जो कुछ कहना होता है, उस के सुझाव भी हम देते हैं, लेकिन जब हम ने स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात देखी, तो वो एक स्टेट को छोड़ कर कभी कहीं पर इस मसले पर बहस भी नहीं होती । कभी शायद किसी स्टेट को अवसर भी नहीं होता कि वह अपनी राय जाहिर कर सके । तो किसी प्रकार से कोई वायुमंडल वहां ऐसा बन सके, कोई वहां पर सुधार हो सके, ज्यादा खूबी से काम हो सके, जिस से हमारा यह विभाग कारगर हो सके, मुझे ऐसा कोई सामान तो दिखता नहीं । एक तो इतना लेट रिपोर्ट का आना, दूसरे जहा पर सारा कारोबार चल रहा है वहा पर चर्चा न होना, तीसरे उन के पास कोई साधन, सामान नहीं, सुझाव देने से कोई सुनने वाला नहीं, उस का कोई स्थान नहीं है हमारे सारे ढांचे में । तो इतना रुपया खर्च कर देना इस पर, इतनी बहस मुबाहसे की बात पैदा करना, इस का क्या नतीजा हो रहा है, और इसे हम कैसे कारगर बना सकेंगे, इस के बारे में मैं कुछ आप के सामने रखना चाहता था ।

एक बात और निवेदन करना चाहता था । जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, मैं देख रहा था, ढूंढ रहा था कि कैसे हम को यह मालूम हो कि हम ने एक बड़ा भारी कदम उठाया था, एक कानून पास किया था : अनटचेबिलिटी ऐक्ट । हम जानना चाहते थे कि यह अनटचेबिलिटी ऐक्ट कितना कारगर है, या कैसे काम कर रहा है । इस को जानने के लिये जरूरत तो यह थी कि हम को बताया जाता कि कितनी शिकायतें आईं, कितने मुकदमात थे जिन की पुलिस द्वारा तहकीकात हुई, कितने मुकदमात के चालान हुए, कितने सजा पायें, कितने छूट गये, कौन शहादत न पाने की वजह से छूट गये । वह सारे वाकयात हमें मिलने चाहियें थे । मैं निवेदन करता हूं कि इस में से एक भी बात रिपोर्ट में नहीं आई । आया तो क्या कि कुछ थोड़े से मुकदमे थे जिन को अदालत में इस वजह से नहीं भेजा जा सका कि उन में शहादत नहीं मिल सकी । इस से तो कुछ पता नहीं चलता कि कितने मुकदमे आये, कितनों में शहादत मिल सकी और कितनों में नहीं मिल सकी । इस से मुझे यह जान पड़ता है कि शायद मुकदमे आये ही नहीं । जितने आये भी उन में शहादत नहीं मिल सकी, जिस की वजह से वे खत्म हो गये । इस के अलावा कोई और नक्शा नजर नहीं आता । तो अगर इस तरह की रिपोर्ट हो जिस से कुछ पता न चल सके, तो या तो उन के पास साधन नहीं हैं, सामान नहीं है, कोई जरिया नहीं है जिस से कि वह इत्तला इकट्ठा कर सकें ।

**एक माननीय सदस्य** : थाने में कोई रिपोर्ट लिखता ही नहीं है ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : या जरूर कोई ऐसी कमी है जिस को वजह से कोई बात हम नहीं जान सकते कि जो कानून हम ने बनाया उस का असर क्या हो रहा है, वह कैसे वर्क कर रहा है, वह कहां तक उपयोगी है, उस में हम कैसे तरमीम करें, कौन सा रास्ता निकालें । कानून हमारा जहां का तहां पड़ा हुआ है जोकि हम ने सन् १९५६ में पास किया था । जो भी हमारी रिपोर्ट में कमी है वह मैं समझता हूं कि उन के पास साधन, सामान न होने की वजह से । कहीं न कहीं ऐसी कमी जरूर है ।

फिर दूसरी बात मैं यह देख रहा था कि दरअस्ल हालत क्या है । इस अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिये हम ने कानून बनाया, लेकिन अनटचेबिलिटी दूर नहीं हुई, इस में कोई सन्देह नहीं । हां सुधार काफी हुआ है परन्तु कुछ बातें उसी तरह से चल रही हैं । इस में हमारे आफिशल आर्गेनाइजेशन सबै

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

हुए हैं, नानआफिशल आर्गेनाइजेशन भी लगे हुए हैं। वे पैसा भी पाते हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़ा उपयोगी काम करते हैं, कुछ परमार्थी भी हैं इस में कोई सन्देह नहीं है। उद्देश्य भी उन का बहुत अच्छा है इस के प्रति। लेकिन जानना हम इस में यह चाहते थे कि वे लोग काम कैसे कर रहे हैं। बताया गया कि हम ने इतने मन्दिर और धर्मशालायें खुलवा दिये, इतने अस्पताल खुलवा दिये, इतने कम्यूनिटी डिनर करवा दिये, इतनी सभायें करवा दीं सैकड़ों की तादाद में यह चीजें बतलाई गईं, इस में कोई सन्देह नहीं, यह उपयोगी काम हुए लेकिन हम तो ऐसी बातों को जानना चाहते थे जिन से पता चल सके कि दर असल स्थिति क्या है। मैं जानना चाहता था कि इस में वह यह बतायें कि कितनी ऐसी जगहें हैं जहा पर वे गये और जो कुछ खुलवाना चाहते थे वह नहीं खुल सका। अगर वह इस को कहते तो पता चलता कि हालत यह है, इतनी जगहों पर कोशिश की लेकिन इतनी जगहों में सफल हो सके और इतनी में नहीं। पर इस की चर्चा तो रिपोर्ट में नहीं। कितने मामले और मुकदमे अनटचेबिलिटी ऐक्ट के मातहत हुए, यह नहीं बताते। यह नहीं बताते कि कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पर अस्पृश्यता दूर करने में असफल रहे, जहां इन्कार किया गया कि यह काम नहीं हो सकता, जहां रुकावट हुई, जहा बाधा हमारे रास्ते में आई। वह चीज बतायें तो उस की कुछ दवा सोची जाय। ऐसी हालत में जो इत्तलायें, जो सूचनायें, जो मसाला हमारे सामने कारगर हो सकता था, वह मसाला हमारे सामने आना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि वह चीज इस रिपोर्ट में नहीं आती है।

एक चीज मैं ने शुरू में निवेदन किया कि अगर वह आये भी तो हम क्या कर देंगे। कौन सी चीज हम रखने जा रहे हैं, कौन का पावन्द हम इस सरकार को कर देंगे या स्टेट गवर्नमेंट्स को कर देंगे, जिस की वजह से कोई काम हो सकेगा। मालूम होता है कि हमारे कमिश्नर साहब भी यह समझते हैं कि वह महज बहस के लिये है, जो कुछ सामने आ गया, दे दो। कौन सा कारगर काम होने वाला है। इस वास्ते मैं चाहूंगा कि जिस तरह का हमारा यह विभाग काम कर रहा है, उस पर कुछ न कुछ ध्यान दिया जाय और इस तरह से धीरे-धीरे चलता जाये यह पर्याप्त नहीं है।

फिर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे जितने भी मित्र बोले, विशेषकर हमारे जो हरिजन भाई बोले, शेड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्य बोले, उन्हों ने इस के आर्थिक पहलू पर ज्यादा जोर दिया। और दरअस्ल यह आर्थिक पहलू ही है जिस के सही होने से सारा कारोबार सही हो सकता है, क्योंकि अनटचेबिलिटी वगैरह जहा मैं ने देखा, उस में जो कोई जरा सा पढ़ लिख कर होशियार, काबिल, अच्छे कपड़े पहनने वाला, हैसियत रखने वाला हो जाय स्टैन्डर्ड आफ लिविंग जिस का अच्छा हो गया हो, उस के साथ सम्पर्क करने में, उन का साथ लेने में किसी को कोई ऐतराज नहीं मालूम होता। वह सब जगह बराबर स्थान पाते हैं। दर-अस्ल प्रश्न उन लोगों का है जिन के खाने का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं, आबरू का ठिकाना नहीं। हालत दरअस्ल उन की सुधारनी है। जब तक हम आर्थिक रूप से उन की सहायता कर के, उन का स्तर ऊंचा नहीं करेंगे तब तक उन की हालत सुधरने वाली नहीं है। कुछ ऊंचे दर्जे के लोग, जोकि मिडल क्लास के कहलाते हैं, अथवा हाई कास्ट के कहलाते हैं जो समाज में ऐसे लोग हैं, जिन को बिल्कुल गांव में रहने वाला कहा जा सकता है, जिन को कभी गांव के बाहर जाने का अवसर नहीं मिला,

वे गांव में बड़े भारी प्रतिष्ठित हैं, उन के कारण बड़ी मुश्किल होती है, वे ही छूआछूत का ऐतराज करते हैं। इस वास्ते यह नहीं है कि जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उन्हीं की हालत खराब है, दूसरे लोगों की हालत भी वही है। सारा वायुमंडल वहां का इस प्रकार दूषित है, और ऐसा आप देखेंगे इंटीरियर में, गांवों में, जहां किसी की पहुंच नहीं है। वहां यह मामलात ज्यादा उठते हैं, वहीं इस तरह के ऐतराजात ज्यादा उठते हैं। जहां पर लोग थोड़े बहुत विकसित होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, वहां धीरे धीरे इस में कमी होती जा रही है। इसलिये वहां सभी वर्गों को शिक्षित और उन के जीवन स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता है।

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दरअसल इस सारे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए जनता में जो प्रचार करने की जरूरत है और हरिजनों को शिक्षित करने की जो आवश्यकता अनुभव की जा रही है, यह सब चीजें तो आवश्यक हैं ही लेकिन इनमें आर्थिक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सारे लोगों का ध्यान उस ओर गया है। हमारी सरकार का भी ध्यान आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ज्यादा गया हुआ है क्योंकि आर्थिक स्थिति को सुधारने में मैं आपसे एक दो बात कहूं कि उसका कितना असर होता है। आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति का काफ़ी महत्व है और मेरी समझ में सामाजिक स्थिति का उतना महत्व नहीं है।

आप चुनावों को देखें। मैं लोक-सभा के चुनावों में ही देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि कोई ९ सदस्य शैड्यूल्ड कास्ट के जनरल सीट्स पर सवर्ण हिन्दुओं के मुक़ाबले में चुन कर आये हैं। जो ऊंची जाति वाले कहलाते हैं और जो बड़े पापुलर समझे जाते हैं और जिनको कि काफ़ी समर्थन की उम्मीद होती है उनके स्थान पर ९ जगहों पर जनरल सीट्स पर हमारे शैड्यूल्ड कास्ट्स के भाई चुन कर आये हैं और सवर्ण हिन्दू उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके। इसी तरह मुझे मालूम हुआ कि १५ व्यक्ति असेम्बलीज की जनरल सीट्स पर सवर्ण हिन्दुओं के मुक़ाबले चुनाव जीते हैं और उन जनरल सीट्स पर वे चुने गये हैं। इससे यह जाहिर होता है कि चूंकि वे शैड्यूल्ड कास्ट्स के होते हैं इसलिए लोग उनसे घृणा करते हैं और उनको वोट नहीं देते हैं और उनका चुनावों में समर्थन नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि जनता उसको वोट देती है जिसको कि वह समझती है कि यह पढ़ा लिखा और काम का आदमी है और यह असेम्बली व पालियामेंट में जाकर उनका उचित प्रतिनिधित्व करेगा उसको वह बगैर जातिपात का विचार किये अपना वोट देती है और यही कारण है कि जनरल सीट्स पर हम देखते हैं कि यहां पालियामेंट में और प्रान्तीय विधान सभाओं में भी हमारे हरिजन उम्मीदवार चुन कर आये हैं।

**श्री प० ला० बारूपाल :** रिज़र्व सीट्स वाले लोग जो कि इन जनरल सीट्स पर सवर्ण हिन्दुओं के मुक़ाबले चुन कर आ गये हैं तो उसका कुछ विशेष कारण था और आप उसकी जांच करें कि वे विशेष कारण क्या थे जिनकी कि वजह से यह लोग उन जनरल सीट्स पर चुन कर आ गये?

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** मुमकिन है कोई और कारण भी हो परन्तु मैं सोच रहा था कि उसका एक पहलू यह भी हो सकता है। और मैं आप से यह कहना चाहता था कि हमारा जो एकोनामिक पहलू है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर वास्तव में हमें हरिजन उद्धार करना है और उनको अपलिफ्ट करना है तो हमें सब से पहले

[पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय]

उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार लाना होगा और दरअसल जितने भी ऐसे पिछड़े और गरीब लोग है उन सब की आर्थिक अवस्था ठीक करने के लिए क़दम उठाना होगा। तभी सारा वायुमण्डल सही होगा।

एक बात की ओर और मैं सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जो अछूत भाई हमारे बुद्ध धर्म अंगीकार कर लेते हैं और बौद्ध हो जाते है उनको भी सरकार की ओर से सहायता व प्रोत्साहन मिलना चाहिये। कोई बौद्ध हो जाने से वे अमीर हो जाते हों ऐसा तो है नहीं और फिर भी वे ग़रीब ही बने रहते हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि उनको इससे महरूम रखना कुछ मुनासिब नही है। लेकिन वह मौजूदा नियम की रू से सुविधायें पाने के हक़दार नहीं है क्योंकि वह नियम के मुताबिक़ शैड्यूल्ड कास्ट के नहीं रहे हालाकि उसकी आर्थिक अवस्था वही है जो कि उसके शैड्यूल्ड कास्ट के दूसरे भाई की है। इसलिए सारे हालात को देखें तो पता चलेगा कि इस समस्या का आर्थिक पहलू सब से कारगर और महत्वपूर्ण है और आर्थिक पहलू पर विशेष ध्यान देना हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये और ऐसा करके ही हम इन अपने अभागे पिछड़े भाइयों को ऊपर उठा सकते हैं। उनकी आर्थिक अवस्था बेहतर करके ही हम इस समस्या को स्थाई तौर पर हल कर सकते हैं और समाज का उत्थान कर सकते हैं।

एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो मेजर्स एडाप्ट किये गये हैं, तरीक़े अख्तयार किये गये हैं उन तरीक़ों में सुधार लाने की गुजाइश मौजूद है और मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि वे समय समय पर अपने काम का ब्योरा भेजते रहें। चूंकि घंटी बज चुकी है और मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं उनमें नहीं जाऊंगा। उन कामों को देखने के लिए यह आवश्यक है कि कोई न कोई ऐसा तरीक़ा निकाला जाय चाहे वह गवर्नमेंट की तरफ़ से हो या उसके लिए कोई कमेटी तैनात की जाय जो कि यह देखे कि वास्तव में सरकार ने जो नीति निर्धारित की है उस के मुताबिक़ काम किया जा रहा है कि नहीं क्योंकि अगर हम उन पर मुनासिब तौर पर अमल नहीं करवा सके तो यह सब कार्यक्रम व्यर्थ जायगा।

**Mr. Chairman:** We are to continue our sitting to-day up to 5 p.m. or 5.30 p.m.?

**श्री उइके :** उपाध्यक्ष महोदय ने हाउस को साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ाना स्वीकार कर लिया था। आप यदि आध घंटे और अधिक समय बढ़ा दें अर्थात् ६ बजे तक कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

**Shri M. C. Jain** (Kaithal): We should continue up to 6 p.m. today.

**Mr. Chairman:** Even then, I have to request hon. Members to limit their speeches to ten minutes, because the list before me contains so many names. Even now, some States have not at all been represented by any party whatsoever.

**श्री प० ला० बारूपाल :** राजस्थान को भी चांस दिया जाय।

**स्वामी रामानन्द शास्त्री** (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति अभी तक सारे सेशन में नहीं बोले हैं और जिनको कि हिन्दुस्तान का विशेष ज्ञान है उन सब लोगों को विशेष तौर पर बोलने के लिए समय दिया जाय।

**Mr. Chairman:** It is very difficult to make such discrimination. There are certain States which have not been represented at all.

**Shri Manaen** (Darjeeling): May I know when the hon. Minister will start replying?

**Mr. Chairman:** If we sit up to six o'clock, then I shall call the hon. Minister at 5.30 p.m. Hon. Members should try to conclude their speeches within ten minutes.

**Shri Ramdhani Das** (Nawada—Reserved—Sch. Castes): I am very grateful to you for the opportunity that you have given me I should like to take this opportunity to draw the attention of the House towards the pitiable conditions of that section of Harijans, which consists of certain castes like Doms, Bhangis, Rijhwars, and Halakhors etc In this connection, I would like to bring to the notice of the House the observations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as found in the different reports. I shall quote a few lines from the different reports which will go to show how deplorable their conditions are

In the year 1955, the Commissioner says in his report at page 214.

> "Even among the Harijans there exist groups such as the Bhangi, Dom, Madiga, Mala etc who are in minority and who need special protection not only against caste Hindus but also from the dominant Harijan groups"

In 1956-57, at page 122 of his report, in the last paragraph, he says·

> "It has been observed that the vocal sections among the Scheduled Castes take all the advantages of the privileges granted to the Scheduled Castes under the Constitution and of the schemes undertaken by the Central and the State Governments for their welfare.".

In 1957-58, at pages 171 to 172 of his report, in the last para, he says:

> "If the ultimate goal of classless and casteless societies is to be attained, the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and even of other backward classes will have to be reduced from year to year and replaced in due course by a list based on the criteria of income *cum* merit.".

Further, he says:

> "To my mind. income *cum* merit is the only equitable basis for granting concessions to the under-privileged section of the people, though in the case of certain castes which are not still vocal enough to take full advantage of the opportunities so far offered, criterion of caste *cum* occupation will have to be recognised for the present For that purpose list of such caste *cum* vocation considered very low in social structure, will have to be drawn up and maintained for some time".

Again, at page 176 of the report, he says:

> "More emphasis should be given on the education of girls and also of boys belonging to Bhangi, Mehtar and Dom and like communities by offering them more facilities in the shape of scholarships, stipends and/or mid-day meals, as their parents are reluctant to send their children to the schools because they help them to supplement their meagre income."

I must say in this connection that these communities are not getting even enough food to eat.

We also find that they could not get representation in the State Assemblies. What to speak of Assemblies, even in the district boards, municipalities and corporations where they are employed in large numbers. This is so because they are extremely poor, and there is none to represent their case in these bodies. They are lagging behind in every walk of life.

In order to raise their living standards, I would suggest that you have to give them proper education. It

[Shri Ramdhani Das]

is of the greatest importance that the policy of Government in the field of Harijan uplift should be one of 'more-needy-more-help' Unless such a policy is adopted by Government, these people cannot progress as they ought to

Then, I would say that the remarks of the Commissioner in this respect should be given full consideration by Government.

The State Governments should be requested to set up inquiry committees of experts with representatives of these affected communities in order to study their problems and find out ways and means to raise their living standards

Then, the State Governments should also be requested to watch the educational progress of the Harijan communities to see which among them are progressing and which of them are not, and the report should be discussed annually in the State Legislatures

Then, I would like to suggest that wherever Harijans are taken by Government nomination, the nominee should be from the lowest categories of the Harijans

The propagation of the Untouchability (Offences) Act should not be left entirely to the non-official organisations, but it should be done through the officials like the sub-divisional officer, the police sub-inspector, the chowkidars and so on who should be asked to make a survey of their respective areas and who should hold frequent meetings in the area where there is any sort of smell of untouchability still in existence.

Individual Harijans should be given free legal and financial help to the extent of Rs. 500 to enable them to proceed to a court to assert the right given to them under the Untouchability (Offences) Act. In cases of revision petition and appeal, an amount to the extent of Rs 1000 and a lawyer of the rank of Advocate-General should be provided for the individual Harijan. This is very necessary in order to ensure that they are not harassed, and their legal right is guaranteed to them properly.

I want to say a few words about the organisations to which Government are giving aid, such as the Bharatiya Dalit Sangh, the Harijan Sevak Sangh and so on I must say that these organisations which get Government aid must submit their reports about their work monthly, periodically and annually, giving details of their activities. For, I find that there is misuse of money by some of the organisations For instance, I have seen some Harijan Sevak Sangh workers, but in the village from which they come, there is untouchability So, it is of the highest importance that they must be asked to submit their reports monthly, quarterly and annually I have done.

16 hrs

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) सभापति महोदय, सदन में इस समय शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो माननीय सदस्यों द्वारा विचार प्रकट किये जा रहे हैं, तो दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और जहां तक दिल्ली का इस समस्या से सम्बन्ध है मैं इस सदन के सम्मुख कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

जहां तक दिल्ली का प्रश्न है बहुत सारे सदस्यों ने कृपा करके दिल्ली के सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें बताई किन्तु वस्तु स्थिति क्या है उससे वह बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिज्ञ लोग होते हैं वह उदार दृष्टिकोण से उन विचारों को देखते हैं किन्तु मानवता की दृष्टि से यदि देखें तो वह अधिक नहीं होते हैं। जहां तक

दिल्ली का प्रश्न है और अस्पृश्यता का प्रश्न है यह सत्य है कि इस समय दिल्ली में अस्पृश्यता कम हुई है किन्तु आर्थिक अवस्था उनकी निरन्तर गिरती जा रही है और मैं देखता हूं कि आज से दस वर्ष पहले या २० वर्ष पहले जिस प्रकार की आर्थिक अवस्था थी वह आज भी विद्यमान है। मैं जब दिल्ली राज्य के गांवों में जाता हूं तो आज भी गांवो में मैं ऐसे हरिजन भाइयों को देखता हूं जो कि सर्दी के मौसम में सांप की तरह से कुंडली मार कर पड़े रहते है, पावो में पेट डाल कर भूखे पेट सो जाते हैं, सोते तो क्या हैं किसी तरीके से रात बिता देते है। उस गरीब और अभागे हरिजन का घर आज भी सीलन से भरा हुआ है और वहां पर बदबू होती है और उसकी कोई अगर भैंस है तो वह भी वही पर बधती है और वही वह गोबर करती है और वह वहा पर एक नरकीय जीवन बिताता है। गंदगी में आज हरिजन अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे है और आप जाकर गावो में उनकी हालत देखिये और गाव में हरिजन का मकान आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे कि सिर में फोड़ा दिखाई पड़ जाता है। उस तरह का एक मटमैल्ड घरौंदा आपको गाव में उस हरिजन का खड़ा हुआ दूर से दिखाई पड जायेगा और उसकी बनावट से आपको दूर ही से पता चल जायेगा कि यह किसी हरिजन का मकान है। अब यदि वस्तुत: हरिजनो की आर्थिक अवस्था में कुछ सुधार करना है और परिवर्त्तन लाना है तो हमें इन बातो की ओर ध्यान देना होगा।

मै समझता हूं कि जैसी हालत हमारे पिछड़ी जाति वालों की दिल्ली में है उससे भी बदतर हालत उनकी दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर है। किसी भी जाति के उत्थान के लिए या उसको उन्नत होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है वह उसके सामाजिक स्तर को ऊंचा करने की होती है। समाज में उसका सम्मान हो और उसमें शिक्षा का प्रसार हो और शिक्षा के अलावा उसकी आर्थिक अवस्था ठीक हो। यदि यह सब बातें हों तो वह जाति उन्नति कर जाती है लेकिन यदि वह सब बातें न हों तो वह जाति गिरती चली जाती है।

यहां पर आध्यात्मिक बातें भी कही गईं, मंदिरो की बातें भी कही गईं। यह ठीक है कि जहां तक समाज का सम्बन्ध है और आध्यात्मिकता का प्रश्न है जो हिन्दू धर्म को मानने वाले है जिनकी कि आस्था और विश्वास हिन्दू धर्म मे है उनका वह अधिकार भी है कि में भी सवर्ण हिन्दुओ के समान मंदिरो में जायें और वहा बैठ कर पूजा करे। किन्तु जहां तक मेरे अपने निजी विचारो का सम्बन्ध है मैं तो इस विचार का समर्थक हूं कि भूखे भोजन न होत गोपाला, यह लो अपनी कठी माला। पहले पेट का ख्याल किया जाता है बाद में भगवान् को याद किया जाता है। जब इसान भूख से तडप रहा हो तो भगवान याद नही आते है। उसको भगवान ज्यादा याद आता है यह ठीक है किन्तु यह भी सत्य है कि नास्तिक भी हो जाता है। जब भूख की चोटें उस पर अत्यधिक पडने लगती हैं तो उसका विश्वास भगवान् पर से उठ जाता है। आज हरिजनों की यही हालत है। आज हरिजन निरन्तर आर्थिक दबाव के नीचे दबते चले जा रहे हैं और दिन पर दिन उनकी अवस्था शोचनीय होती जा रही है और उनके उत्थान और उन्नति का कोई रास्ता नजर नही आ रहा है और ऐसी हालत में आप स्वयं समझ सकते हैं कि वह क्या करेगा ? क्या वह उन मंदिरो में रखी मूर्तियो की आराधना करेगा और उन से प्रार्थना करेगा कि मेरी उन्नति हो जाय, मुझे शिक्षा मिल जाय, मैं आगे बढ़ू, मेरी जाति आगे बढ़े, हम उन्नति करे और अपने देश के लिए लाभप्रद हो जायें ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। वह पूरा इस बात से होने वाला है कि उसे समाज में सम्मान मिले उसे शिक्षा मिले और वह आगे बढ़े।

[श्री नवल प्रभाकर]

जहां तक शिक्षा का संबंध है, यह सही है कि हम में से बहुत सारे नौजवान पढ़ रहे हैं। किन्तु वे आखिर कितना पढ़ पाते हैं ? कोई आठ जमायत तक और कोई दस जमायत तक। और पढ़ने के बाद भूख का चक्कर उस के सामने आता है। वह बाबू बनने के लिए एम्पलायमेंट एक्सचेंज जा कर अपना नाम दर्ज करवाता है और दफ्तरों के दरवाजे खटखटाता है। आज हालत यह है कि हरिजनों के लिए जगहों के खाली होते हुए भी उस को बार-बार दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आज भी हरिजनों के विषय में यह देखा जाता है कि वे प्रथम श्रेणी में पास हैं, द्वितीय श्रेणी में पास हैं या तृतीय श्रेणी में पास हैं। मैं अपने यहां का एक हदाहरण देना चाहता हूं। टीचर्ज ट्रेनिंग का मामला था अध्यापकों के प्रशिक्षण का। अव्वल तो हमारे यहां लड़कियां पढ़ती नहीं है। छः लड़कियों ने, जो कि मैट्रिक पास थी, चाहा कि वे प्रशिक्षण लें और वे गईं। छः स्थान खाली थे और छः ही लड़कियां वहां गई। किन्तु अन्य लोगों की तरह से उन की परीक्षा ली गई और उस के बाद उन सब को छोड़ दिया गया। जब मैं ने इस विषय में लिखा, तो मुझे मालूम हुआ कि यदि उन के ३३ प्रतिशत भी नम्बर आते, तो उन को ले लिया जाता, क्योंकि दूसरों को ४० प्रतिशत नम्बर प्राप्त करने पर लिया जाता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब किसी पद या कोर्स के लिए एक योग्यता निर्धारित की जाती है, और कोई उतनी योग्यता वाला व्यक्ति प्रशिक्षण लेने के लिए जाता है, तो इस तरह की नीति क्यों अपनाई जाती है। यह स्पष्ट था और फ़ार्म में लिखा था कि जो भी मैट्रिक पास होगा, उस को अवसर मिलेगा, लेकिन मैट्रिक पास लड़कियां जाती हैं और उन को अवसर नहीं दिया जाता है। मंत्री महोदय ने कृपा कर के एक लाइन यह और बढ़ा दी कि रिजर्वेशन में जो स्थान भरे नहीं जायेंगे, उन को आगे के लिए भी छोड़ लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि आगे भी यही हाल होगा, क्योंकि सम्भवतः इस वर्ग के लोग ४० परसेंट या ३३ परसेंट नम्बर नहीं ले सकेंगे और उस अवस्था में यही होगा।

रिजर्वेशन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो रिजर्वेशन है वह आगे भी रहना चाहिए। मैं रिजर्वेशन के बहुत हक में नहीं हूं, किन्तु मैं जब इस अवस्था को देखता हूं .....

सभापति महोदय: अब माननीय सदस्य समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री नवल प्रभाकर: मैं ने अभी आरम्भ किया है।

सभापति महोदय: बात यह है कि हर एक सदस्य को दस मिनट का टाइम मिलेगा।

आठ मिनट हो गए हैं, दो मिनट माननीय सदस्य और ले सकते हैं।

श्री नवल प्रभाकर: अच्छा।

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है मैं देखता हूं कि आज भी अवस्था कुछ अच्छी नहीं है। संविधान की भावना तो यह है कि हम दस बरस में और लोगों के स्तर के बराबर इस पिछड़े हुए सवर्ग का स्तर ले आयेंगे। यदि आज वह स्तर आ जाता, तो मैं आगे के लिए न कहता।

श्री वाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित-जातियां): दिनों दिन स्तर गिरता जा रहा है।

श्री नवल प्रभाकर: आज अवस्था यह है कि हम में कितने डाक्टर या इंजीनियर हैं? जो हरिजन लड़के मिडल पास कर के हायर सैकंडरी में जाते हैं, उन को साइंस का विषय मिलना कठिन हो जाता है। अगर वह साइंस में पास नहीं होगा, तो उस के लिए

उन्नति के सब द्वार बन्द हो जाते हैं और इस लिए जाहिर है कि वह दस जमायत पास कर के बाबू, क्लार्क, बनेगा। माननीय मंत्री महोदया यहां नहीं हैं। रेलवे मंत्री हैं। अगर वह नोट करना चाहें, तो कर लें।

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: मैं सब नोट कर रहा हूं।

**श्री नवल प्रभाकर**: अगर उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो वे इसी तरह दफ्तरों की खाक छानते रहेंगे। आज सरकार को इंजीनियरों, ओवरसीरों और डाक्टरों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरकार कृपा कर के उन को इन लाइनों में लेने का प्रयत्न करे, अगर वह वास्तव में उन की उन्नति चाहती है। नहीं तो बेकारी में और वृद्धि होगी और हरिजनों की कोई उन्नति नही होगी।

अन्त में दिल्ली की एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। पुलिस के सम्बन्ध में मै ने बहुत लिखा-पढ़ी की और बहुत कुछ कहा और उस का परिणाम यह हुआ कि मुझे डी० आई० जी०, पुलिस, ने एक पत्र लिख दिया कि आप के पास पुलिस के लिए जितने व्यक्ति हों आप दीजिये। मैं ने एम्पलाइमैंट एक्सचेंज से इस बारे में मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, हमें लिखा जाय और हम उस योग्यता के व्यक्तियों को देने के लिए तैयार हैं। मै ने पुलिस अधिकारियों से कहा, तो मुझे कहा गया कि हम तो सीधी भरती करते हैं। यह बड़ा विचित्र तर्क है।

अन्त में एक बात और कह कर मैं बैठ जाता हूं। बहुत कहा जाता है कि हरिजनों के लिए इतना रुपया दिया गया है। और राज्यों का तो मुझे पता नहीं है। दिल्ली का मुझे पता है। जब कभी कोई बाढ़ आती है या तूफ़ान आता है और हरिजनों की झोंपड़ियां उड़ जाती हैं, बाढ़ में बह जाती हैं और अगर यह कहा जाता है कि इन लोगों को झोंपड़ियां बनाने के लिए कोई सहायता दी जाय, तो जवाब दिया जाता है कि हरिजन वैलफ़ेयर बोर्ड इस की व्यवस्था करेगा। हरिजन वैलफ़ेयर बोर्ड वाले कहते हैं कि इस के लिए कोई अनुदान नहीं रखा हुआ है और जो जनरल फ़ंड है—सार्वजनिक व्यय की जो राशि है, उस में उन के लिए कोई स्थान नहीं है यहां कहा गया कि जेनरल फंड में से उन के लिए खर्च किया जाता है और उन के साथ सब के समान व्यवहार किया जाता है। लेकिन दिल्ली का मुझे अनुभव है कि जनरल फंड में से हरिजनों को एक पाई भी नहीं मिलती है।

**एक माननीय सदस्य**: बाकी जगह भी ऐसी ही है।

**श्री नवल प्रभाकर**: जो हरीजनों का फंड है, उस का एक-चौथाई भाग वेतनों आदि में निकल जाता है और जो बाकी तीन-चौथाई है, उस को भी बहुत अंश में दुरुपयोग किया जाता है और जो ठीक उपयोग में आता है, वह पढ़ाई के विषय में आता है। मेरा कहना है है कि अब आठ वर्ष समाप्त हो गए हैं और दो वर्ष और शेष हैं। दो भी नहीं, एक ही बाकी रहा है। इस एक साल में अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोग कहां तक उन्नति करेंगे? जो कुछ नौसाल में नहीं हो सका है, वह एक साल में कैसे हो सकेगा? क्या इस हाउस में या बाहर अल्लादीन का चिराग़ घिसा जायगा और उस से एकाएक क्रान्ति आ जायेगी और उन लोगो की अवस्था में एकाएक परिवर्तन आ जायगा? आज जिस हरिजन का पेट पीठ से लगा है, जिस की बगुले की सी सींक सी टांगें हैं, जिस की आंखें धंसी हुई हैं, जिस के स्वास्थ्य की यह दशा है, वह क्या करेगा? मैं कविता की दो पंक्तियां कह कर बैठ जाता हूं। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात को सुनें।

सब के पास हो धरा, सभी के पास धाम हो,
सब को अन्न-वस्त्र हो, सभी के पास काम हो।

**Mr. Chairman:** Shri Padalu. The hon. Member will speak in Telugu.

*Shri K. V. Padalu (Golugonda—Reserved—Sch. Tribes): Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Government for the various steps undertaken by them to improve the lot of the Scheduled Castes and Tribes. It is because of the various welfare schemes of the Government that people belonging to the Scheduled Tribes have come out of darkness and are able to enjoy the benefits of civilisation.

This, I submit, should not, however, make us complacent. Much more in the direction of improvement and welfare of the Scheduled Tribes remains to be done For example, the Scheduled areas are as backward in matter of education as ever. There are in Andhra Pradesh about 11,49,919 people belonging to the Scheduled Tribes. Half of them would be women. Practically all the women are illiterate. Even among men there are very few who can read and write the regional language. Why is it that the tribal people are still so backward in education?

It is true that in some of the primary schools, facilities such as free boarding and clothing are provided. But this does not solve the problem of education of the tribal people. So far, no high school has been opened in the tribal area of my constituency. The boys who complete their elementary and middle school education have perforce to suspend their education. Their parents are not prepared to send their children to far-off places for education. They are not trained like the people in the plains and other areas to send the boys to towns for higher education

16.17 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Therefore, Government should think in terms of establishing high schools right in the heart of the tribal areas.

I sincerely feel that the matter is one involving serious consequences. Boys who have studied for a few years, say, up to VIII standard, are unable to go for higher education and, therefore, suspend their schooling. This class of neo-Tribes are neither sufficiently educated so as to derive fully the benefits of education nor do they have the age old habits of working with their parents in order to eke out a living. This class of boys, I am afraid, would not bring any kind of credit to the tribal people. On the other hand, they may create a dangerous situation in the tribal area, and it needs to be prevented. May I request the Government to consider the seriousness of the situation and do something in the matter?

Sir, it is stated in the Report of the Commissioner for the year 1956-57 that the Government had decided to establish an agricultural farm in Chintapalli village of Andhra State. So far, it had not been established It is needless to point out how useful such an agricultural farm would be to the tribal people belonging to the Andhra State. A large number of the tribal people of Andhra State live in and around Chintapalli. Their chief occupation is agriculture. An agricultural farm would go a long way to improve agriculture of the tribal people. May I request the Government to implement their plan of establishing the farm as early as possible?

Sir in the tribal area of my constituency, the Government of Andhra Pradesh has established recently a Finance Corporation, the chief object of which, I believe, is to offer loans to the tribal people. But, in actual experience, the tribal people find it very difficult to obtain loans from he Corporation. The Government should devise ways and means to liberalise

*Translation in English of the speech delivered by the hon. Member in Telugu.

the method of granting loans from the Finance Corporation.

The Finance Corporation has been authorised by the State Government to have a monopoly in the purchase of forest produce in the tribal area. This is established in order to safeguard the interests of the tribal people But in practice, this has resulted in creating a feeling among the tribal people that the Finance Corporation is not giving a proper price for their produce and that they are precluded by Government from selling their goods in the private market where they feel they would get a higher price. I, therefore suggest that Government should, while continuing the cooperatives run by the Finance Corporation, allow the private dealer also to have his trade. The tribal people would then encourage the institution which is profitable to them. The people in the tribal areas are slow to change and therefore, the State should try to introduce changes by slow degrees alone. The tribal people are like wards of the State; the State should take foremost interest in their welfare and promote it.

I thank you, Sir, for the opportunity you have given me today to speak on this subject.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Ramji Verma. I am sorry; not more than ten minutes are available to each hon. Member.

**An Hon. Member:** Why, Sir.

**Mr. Deputy-Speaker:** If the hon. Members so agree, double the number could be accommodated.

**श्री रामजी वर्मा** (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में कुछ वर्गों के लिये कुछ सुविधायें, कुछ विशेष सुविधायें शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी गई हैं। इस का नतीजा यह हुआ है कि ऐसा प्रतीत होने लगा है कि दो वर्गों का, दो जातियों का कोई संघर्ष सा इस मुल्क में है ? इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उच्च वर्ग, कास्ट हिन्दूस से हमारे पिछड़े भाई, हमारे हरिजन भाई बहुत परेशान रहे हैं, और साथ ही साथ समाज ने भी उन को बहुत परेशान किया है। किन्तु आज स्वतंत्रता के युग में इस प्रश्न को मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये कि जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं, शिक्षा और दूसरे आर्थिक मामलों में चूंकि वे हीन रहे हैं, इस वास्ते उन की सामाजिक स्थिति नीची रही है और उन को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। उन में भी जो आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं, उन को सारी सुविधायें प्राप्त हैं, सभी सुविधाये जो उच्च वर्ग के लोगों को प्राप्त हैं, उन को भी प्राप्त हैं। मैं जानता हूं कि अब जब मुल्क आजाद हो चुका है और लोग स्वतः ही काम करते हैं, तरक्की करने की लोगों में भावना है, वहां हर मामले में, हर चीज में सरकार की ओर देखना कि वह उन की तरक्की करे, वह उन के लिये सभी काम करे, वही उन को आगे बढ़ाये, मैं समझता हूं कि इस से पराधीनता की भावना पैदा होती है और इस से हम को कुछ मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये। हर बात के लिये हम को सरकार का मुंह नहीं ताकना चाहिये, सरकार की ओर नहीं देखना चाहिये, उसी पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

किन्तु आज स्वतः सरकार ऐसे-ऐसे कामों में और कम से कम आर्थिक प्रगति के रास्तों में रोड़ा बन कर जब आती है, तो सभी निर्धन लोगों को सरकार की तरफ ताकने का, सरकार से लड़ने का, सरकार से कुछ कहने का और सरकार से शिकायत करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन मैं इस प्रश्न को किसी और ही दृष्टि से देखता हूं। मैं समझता हूं कि यह कहना कि ये पिछड़े हुए हैं, ये हीन हैं, ठीक नहीं है, वे आज पिछड़े हुए नहीं हैं। मैं तो यह देखता हूं कि इतिहास में हमारे जो बड़े-

[श्री रामजी वर्मा]

बड़े रिफार्मिस्ट नेता हुए हैं, राजा राम मोहन राय जैसे या दयानन्द सरस्वती जी जैसे और जो अपने नाम कर गये हैं, इतिहास बना गये हैं, उन्हों ने जो कुछ समाज कल्याण के नाम पर काम किया है, या सुधार किये हैं, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है, स्त्रियों में परदा प्रथा है, उस के खिलाफ विद्रोह किया है, विधवा विवाह और तलाक प्रथा इत्यादि के पक्ष में आवाज उठाई है छुआछूत दूर करने की कोशिश की है, इन सब कामों को करने से आज भी लोगों द्वारा वे पूजे जाते हैं। आज भारतवर्ष को जिस संस्कृति को अपनाना है, जिस तरह की समाज का निर्माण करना है, जिस तरह की तरक्की करनी है और जहां इस को पहुंचाना है, उस में उच्च वर्ण के जो लोग हैं, उन से अधिक आशा नहीं की जा सकती है। जितने भी दुर्गुण हैं, वे उच्च वर्गों में ही हैं और उन्हीं का सुधार करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। जिन खूबियों के कारण या गुणों के कारण ये सवर्ण लोग, हिन्दू कहे जाने वाले लोग आगे बढ़े हुए हैं, आज वही गुण उनके रास्ते में वही रोड़ा हैं। उन के यहां पर्दा प्रथा है, उन के यहां विधवा विवाह नहीं होता है और जब यहां डाइवोर्स के बारे में बिल पेश हुआ था तो वे घबरा उठे थे, तिलमिला उठे थे।

मैं समझता हूं कि हमारा पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, हिन्दुस्तान का और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उन में ये रोग नहीं हैं। वह भारतमाता के सही मायनों में सच्चे सपूत हैं। उन में वह सब गुण विद्यमान हैं जिन को कि उच्च वर्ण वालों को अंगीकार कर के आगे बढ़ना है। आप कहते हैं कि विदेशियों से हम इन चीजों को और गुणों को लेते हैं मगर मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप को इन गुणों को सीखने और लेने के लिये विदेशियों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है खुद आप के घर में यह गुण मौजूद हैं और जिन को कि आप छोटा भाई कहते हैं, पिछड़े हुए लोग कहते हैं, उन में यह सारे गुण मौजूद हैं। कल्चर के प्रति उन की आस्था है। हर चीज में वे बढ़े हुए हैं। आज दुनिया में श्रम का महत्व है और कोई कौम जिन्दा नहीं रह सकती और उस का कोई आदर व सम्मान नहीं हो सकता जोकि श्रम के महत्व को नहीं जानती और जो कि श्रम से परहेज करती है। भारतवर्ष के लोगों की सब से बड़ी खराबी यह है कि यहां के लोग श्रम से परहेज करते हैं। जो व्यक्ति श्रम करता है परिश्रम करता है उस को तो वह हेय समझते हैं और जो व्यक्ति आराम से गद्दी पर बैठा रहता है और कोई भी काम नहीं करता है उस की वे इज्जत करते हैं। हमारी यह प्रवृत्ति है और इसी कारण हमारे लोग श्रम से दूर भागते हैं और जितने भी बड़ी जाति के लोग हैं और जो धनी मानी हैं उन में यह ऐब और खराबी मौजूद है। मैं तो अपने समाजवादी कहे जाने वाले भाइयों और मार्किस्ट बन्धुओं को जोकि श्रम के झंडे को आगे बढाते हैं उन से कहना चाहूंगा कि अगर हम को श्रम का सबक कहीं सीखना है तो वह रूस अथवा और किसी विदेशी राष्ट्र से नहीं सीखना है बल्कि उस श्रम के महत्व को हमें अपने पिछड़े भाइयों से सीखना है।

इस सम्बन्ध में वह हम सवर्ण हिन्दुओं से कहीं आगे है और कौन कहता है कि वह बैकवर्ड है। आज समाज का झंडा उन के हाथ में हो सकता है लेकिन यह खुद रोना रो रहे हैं कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और मै समझता हूं कि उन के लिये ऐसा समझना बिलकुल ही गलत है और मैं तो कहूंगा कि वे हर माने में आगे बढ़े हुए हैं। जो हमारे में दुर्गुण हैं जो यहां के सवर्णों में दुर्गुण हैं उनसे वे मुक्त हैं उनसे अगली संस्कृति और जो समाज आने वाला है उस का और हिन्दुस्तान का नाम रौशन होने वाला है। श्रम का झंडा उन्हीं के हाथ में है और मैं तो समझता हूं कि उन को दिल में दिलेरी और आत्मविश्वास की भावना

के साथ यह ऐलान कर देना चाहिये कि हिन्दुस्तान की बागडोर और देश को आगे ले जाने का झंडा उन के हाथ में है। आज हिन्दुस्तान के नागरिक ब्राह्मणों के पीछे नहीं जा सकते हैं। उन को तो श्रमिकों के पीछे जाना पड़ेगा और वह हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हमारे नेता व रहनुमा हैं लेकिन अफ़सोस का विषय यह है कि आप खुद समझने लगते हैं कि हम पीछे हैं और अपने पिछड़ेपन का खूब आये दिन रोना रोते रहते हैं तो मुझे यह देख कर हैरत होती है और दिल में एक दुःख व निराशा की भावना पैदा होती है। मैं समझता हूं कि हमारे भाइयों को इस मनोवृत्ति का त्याग करना चाहिये और उन को निराश नहीं होना चाहिये और इस ऐतिहासिक घड़ी में जो जिम्मेदारी उन के हाथ में है उस को वे योग्यता से सम्हालें और बाकी वर्णों के लोगों को श्रम का महत्व सिखायें ताकि अन्य जाति वाले भी श्रम करने से परहेज न करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे भाई आगे बढ़ कर अन्य जातियों के लोगों का इस मामले में पथ प्रदर्शन करें।

यहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग का भी जिक्र हुआ। कोआपरेटिव फ़ार्मिंग के सवाल को ले कर हमारे एक भाई को घबराहट हो गई और हमारे श्री मसानी को उस के कारण इतनी घबराहट हो गई कि वे यह कहने लग गये कि अगर यहां पर कोआपरेटिव फ़ार्मिंग जारी की गई तो देश में क्रांति हो जायगी। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इस के लिये श्री मसानी की इतनी घबड़ाने की जरूरत नहीं है। इस देश में सहकारी कृषि सफल होनी चाहिये और वह होगी बशर्तेकि उस को ठीक ढंग पर चलाया जाय। आज जिस ढंग से उस को बढ़ाया जा रहा है उस में इस बात का खतरा है कि आफ़िशिएलडम न आ जाय। इस बात के लिये हमें सतर्कता बर्तनी होगी। कोआपरेटिव फ़ार्मिंग अगर देश में पनपती है तो उस में भी श्रम का महत्व होगा और उस में उन का भी महत्व बढ़ेगा जोकि किसान कहलाते हैं और उस में भी आप का महत्व बढ़ेगा और उस का झंडा भी आप के हाथ में है . . . . . .

श्री वाल्मीकी : वह तो ठीक है लेकिन उच्च वर्ग वालों की चौधराहट से डर लगता है।

श्री रामजी वर्मा : घबड़ाइये नहीं यह जो उन की काम और श्रम से जी चुराने की मनोवृत्ति है यह बीमारी उन को खा कर ही दम लेगी। सरकार जिस ढंग से कोआपरेटिव फ़ार्मिंग चला रही है उस में आफ़िशिएलडम आने का खतरा है और अगर ऐसा हुआ तो यह योजना तो विफल होगी ही साथ में हमारे मजदूर वर्ग को भी चट कर जायगी। इसलिये इस में विशेष सावधानी बर्तने की जरूरत है और इस मुल्क में मजदूर वर्ग और किसान वर्ग मिल कर कोआपरेटिव फ़ार्मिंग को सफल बनायें और उस का भी नेतृत्व आप के हाथ में है। इसलिये इस से घबराने की बात नहीं है और उस को समझदारी के साथ आत्मविश्वास के साथ और इनफ़ीरियार्टी कम्पलेक्स को हटा कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हिम्मत से आगे बढ़िये। भविष्य आप के हाथ में है।

श्रीमती गंगा देवी (उन्नाव—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेज के कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि समस्त भारतवर्ष की अनुसूचित आदिम जातियों और बैकवर्ड क्लासेज के अपलिफ्ट का जो भार सरकार ने आयुक्त महोदय के कंधों पर रक्खा है उस को उन्हों ने कैसे वहन किया है और उन्हों ने अपने भाइयों को अब तक कितनी सुविधा और राहत पहुंचाई है। मैं

[श्रीमती गंगा देवी]

बहुत थोड़े समय में अपनी बातों को खत्म करना चाहती हूं ।

अभी हमारे दातार साहब ने बहुत सुन्दर भाषण दिया और उस से हमें यह पता लगा कि अछूतों के अपलिफ्ट के वास्ते शिक्षा, हाउसिंग और बहुत से कामों में जो रुपया खर्च हो रहा है उस की सही रिपोर्ट उन को पता नही चल सकती ।

अभी शिक्षा की बात हो रही थी और उस के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है । हमारे अन्य भाइयों ने उस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया है । मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि उन्हों ने जो कहा कि हर एक विद्यार्थी को रुपया दिया गया और सब को वजीफा मिल चुका तो यह बात बिल्कुल ग़लत है । मैं नही समझ सकती कि कौन सी प्रणाली वजीफा देने में प्रयोग में लाई जाती है ? जब गवर्नमेंट ने एक यह नियम बनाया है कि अच्छे नम्बरो से पास होने वाले विद्यार्थियों को आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये पूरी मदद दी जायगी, वजीफे दिये जायेंगे तो क्यों नही यह नियम सही तरीके से पालन होता है ? विद्यार्थियों से वैरेंस लिया जाता है और उस उम्मीद पर लड़के और लड़कियां कालिजों मे नाम लिखवा लेते है लेकिन बीच मे उन को लटका दिया जाता है । पूरे का पूरा साल खत्म हो गया लेकिन अभी भी वही हालत है जोकि पहले थी । मै तो समझ नही सकती कि किस तरीके से उन को वजीफ़े दिये गये और मैं तो समझती हूं कि अभी तक भी किसी भी लड़के को वजीफ़े नहीं मिले....

एक माननीय सदस्य : अभी तक भी नहीं मिले है ।

श्रीमती गंगा देवी : जहां तक मै ने पता लगाया जनवरी तक तो उस का कोई निर्णय नहीं हुआ । और मेरा तो कहना है कि अगर नहीं बाद में इस तरह उन का दम निकाल कर वजीफ़ा दे भी दिया तो वह देना नहीं है । मैं अपने यहां के कितने केसेज ऐसे बतला सकती हूं और मेरे पास कोई ६०, ७० चिट्ठियां ऐसे लड़के और लड़कियों की आई हैं जिन्हों ने वजीफ़े के बारे में मुझे लिखा था कि हमें यह बतला दिया जाय कि हमें वजीफा मिलेगा कि नही । अगर हमें वजीफ़ा नही मिलने वाला है तो फिर हम यही पर अपनी पढ़ाई खत्म करते है । वे हमें लिखते है कि हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है । अब आप ही हमें बतलाइये कि हम इस का उन को क्या जवाब दिया करे । हम उन लोगों से कह देते हैं कि हम क्या करे हमें कोई सही जवाब नही मिलता । ऐटा में एक कालिज है वहा के होस्टल में क़रीब ६०, ७० लड़के शेड्यूल्ड कास्ट के है । उस कालिज के जो प्रिंसिपल साहब है वह हमारे श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी के सुपुत्र है उन को जब जनवरी तक कोई वजीफा नही मिला और बेचारो को फाके से दिन काटने पडे तो उन्हो ने कालिज के फंड मे से कुछ रुपया उन को दिया और इस तरह उन का खर्चा चला लेकिन ऐसे कहा तक चल सकता था । वह यहा आये और मुझ से इस के बारे मे बातचीत की । उन्हों ने बतलाया कि अगर वजीफा मिलेगा तो मै कालिज मैं उनका खर्च चलाऊंगा वरना और बाद मे उस को काट लूगा । जब मैं ने इस के बारे में पता लगाया और अंडरसेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड से इस बारे में जब मै मिली तो उन्हों ने बतलाया कि अभी यह सवाल हमारी किसी मीटिंग में तय नहीं हुआ है और जब इस के बारे में हम कोई फ़ैसला कर लेंगे तो हम इस की आप को सूचना दे देंगे । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार और उस के प्रशासकीय कर्मचारियों का वजीफ़ा आदि देने का यह तरीक़ा है । अब एक तरफ़ तो हम यह कह देते हैं कि हम फ़लां-फ़लां कामों के वास्ते अछूत भाइयों को इतने रुपये की

सहायता दे रहे हैं लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि वह सहायता उन को वक्त पर नहीं मिल पाती है और जिस तरीके पर कि उन पर अमल होना चाहिये वह नहीं होता है और यही कारण है कि हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को आज भी काफी मुसीबत व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

अब शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट को उठा कर जब हम देखते है तो हम पाते है कि अनटचेबिलिटी के वास्ते उन में शिक्षा का प्रचार करने के वास्ते और अन्य उपयोगी कार्यों के वास्ते इतनी-इतनी धनराशि रक्खी गई है, एजुकेशन में इतनी रकम रक्खी गई है और अनटचेबिलिटी के वास्ते इतनी रकम रक्खी गई है, इतना रुपया हाउसिंग के लिये दिया गया, इतना रुपया दूसरे किसी काम के लिये दिया गया, इस तरीके से आकडे गिनने को मिलते है ।

जहा तक एजूकेशन का सम्बन्ध है, अगर सरकार ने इसी तरीके से वजीफे देने है, तो फिर इस व्यवस्था को खत्म ही कर दिया जाय । इस तरह से बीच में लटका कर लडको को परेशान करना ठीक नही है । यदि स्कालरशिप्स बोर्ड को अच्छे तरीके से नही चलाया जा सकता, तो गवर्नमेंट को चाहिये कि ऐसे होस्टल्ज खोले जायें, जहां बिल्कुल फ्री एजूकेशन दी जाये । अगर वजीफे देने का कोई नियम न रहे और सारा खर्च—बोर्डिंग, लाजिंग, ट्यूलन फ़ीस और किताबों का खर्च—सरकार अपने हाथ में ले, तो यह ज्यादा अच्छा होगा । लड़कियों के लिये कुछ ऐसे होस्टल होने चाहियें, जहां उन को शुरू से ले कर आखिर तक पूरी एजूकेशन दी जाये । अगर सरकार सामाजिक सुधार चाहती है, तो लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है । उन को बहुत अधिक पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता, लेकिन सामाजिक सुधार की दृष्टि से उन को शिक्षा देना निहायत जरूरी है । मैं समझती हूं कि इस पर गौर किया जायेगा । गरीब लोग अपने लड़के-लड़कियों को शिक्षा दिलाने मे असमर्थ होते हैं । अगर इस सम्बन्ध में रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाय, तो अच्छा होगा ।

जमीन के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि आज देश के सामने खाद्य समस्या का प्रश्न है और दूसरी तरफ़ प्रश्न है अन-एम्पलायमेंट का । यदि हम एक समस्या को हल करते हैं, तो दूसरी समस्या अपने आप हल हो जाती है । बहुत सारी जमीन ऐसी पड़ी है, जोकि खेती में अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकती है । आज खेतिहर मजदूर, जिन के पास जमीन नही है, भूखे, बेकार और परेशान है । अगर यह जमीन उन को दे दी जाय जोतने के लिये, तो खाद्य समस्या का हल हो सकता है और उन की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है । हम चाहते है कि जमीन का वितरण सही तरीके से हो ।

जहां तक फोर्स्ड लेबर का प्रश्न है, अभी हमारे गृह मंत्री महोदय ने बड़े जोरदार शब्दो में यह कहा कि आज कही पर भी फ़ोर्स्ड लेबर नही ली जाती है—बेगार नहीं ली जाती है, लेकिन कई उदाहरण हमारे सामने हैं, इस प्रकार की कई घटनायें हमारे सामने घटती हैं, क्योंकि हमें पब्लिक मे जाना पड़ता है । सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं कि किस प्रकार से बेगार ली जाती है । अभी हाल की बात है कि मेरठ के एक गाव में श्रमदान हो रहा था । वहा के त्यागियों ने हरिजनो को कहा कि आप को फ़लां काम पर जाना है । हरिजनों ने कहा कि हम ने श्रमदान पर जाना है । इस पर त्यागियों ने कहा कि हम देख लेंगे और दूसरे दिन एक हरिजन को बहुत मारा गया और वह वहीं पर मर गया । इस की रिपोर्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर के पास गई । कमिश्नर साहब की पूरी किताब में इस प्रकार का कोई दृष्टान्त नहीं मिलता है । इस रिपोर्ट को देखने से तो यह पता लगता है कि कहीं पर भी फ़ोर्स्ड लेबर नहीं है और बेगार प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई है । हम चाहते हैं कि जहां कमिश्नर साहब

[श्रीमती गंगा देवी]

इतनी बातों को हमारे और पब्लिक के सामने रखते हैं कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, वहां जो कमियां हैं, उन की तरफ़ भी वे ध्यान दिलायें । अगर ऐसा नहीं किया जायगा, तो उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकेगा और जो त्रुटियां हैं, उन का सुधार कैसे हो सकेगा ?

आज अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिये बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन अगर उस के साथ-साथ हरिजनों को कुछ घरेलू धन्धे और अपने कारोबार खोलने के लिये कुछ रुपया सही तरीके से दिया जाय, तो उन की आर्थिक समस्या सुलझेगी और उस से छूआछूत अपने आप दूर हो जायेगी । क्योंकि जब आदमी के पास पैसा होता है, तो उस को अपने रहन-सहन और खान-पान का ज्यादातर ध्यान अपने आप आ जाता है । मैं चाहती हूं कि सरकार की स्कीमों के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और को-आपरेटिव्ज और बहुत से घरेलू धन्धे देश में चलाये जायें । उन हरिजनों को, जिन के पास कोई भी कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, किसी किस्म का भी अपना धन्धा नहीं है, छोटी इंडस्ट्रीज के लिये, घरेलू धन्धों के लिये खास तौर से रुपया देना चाहिये ।

आज हमारे देश का चर्मकार बिल्कुल निहत्था हो गया है । उस के बल पर बड़ी-बड़ी कम्पनियां--बाटा कम्पनी, आहूजा कम्पनी, फ्लैक्स कम्पनी वगैरह--पनप रही हैं, लेकिन चर्मकार मजदूरी पर अपना निर्वाह करता है । मेरा निवेदन है कि जहां देश में खादी बोर्ड और हैंडलूम काम कर रहे हैं, वहां एक लैदर बोर्ड भी होना चाहिये और वह लैदर बोर्ड उन चर्मकारों को सहायता और प्रोत्साहन दें, जिस से हमारा लैदर अच्छी तरह से हो सके ।

अब मैं सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड के बारे में विशेष रूप से कहना चाहती हूं, क्योंकि उस में सरकार का--देश का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है । लेकिन जहां पर वेलफ़ेयर होना चाहिये, वहां उस का नाम मात्र भी नहीं होता है । जैसाकि अभी उनके भाई ने कहा है, जहां आवश्यकता है, वहां सोशल एक्टिविटीज नाम-मात्र के लिये भी नहीं है । वहां पर लोग जवाहरलाल जी और महात्मा गांधी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उन के बीच में कोई कार्य नहीं किया जाता है । यह बोर्ड जिस प्रकार से काम कर रहा है, उस से जो वास्तव में बैकवर्ड कम्यूनिटीज हैं, उन को क्या फायदा है ? जहां सोशल वर्क होना चाहिये, वहां बिल्कुल नहीं हो रहा है । जितना भी काम होता है, वह एडवान्स्ड कम्यूनिटीज में होता है, जहां एक पिकनिक की तरह खेल खेले जाते हैं । स्त्रियां बड़े ठाट-बाट के साथ गाड़ियां ले कर जाती हैं और पिकनिक में एन्जायमेंट कर के आ जाती हैं । देहात की ऐसी औरतों में, जिन को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, जाने और काम करने की कोशिश नहीं की जाती है । उन लोगों में इतना कष्ट उठाने की प्रेरणा नहीं है । हम चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर बोर्ड की एक्टिविटीज कम से कम बैकवर्ड कम्यूनिटीज की औरतों के बीच जरूर हों । मैं ने अपने क्षेत्र में देखा है कि एक ही गांव में एक तरफ हरिजन औरतें हैं और दूसरी तरफ सवर्ण औरतें हैं और सवर्ण औरतों के बीच में सेंटर चल रहा है और हरिजन औरतें मुंह ताकती हैं । केन्द्र भी कोई परवाह नहीं करता है इस प्रकार के सोशल वैलफेयर बोर्ड से हम को कोई फायदा नहीं है । अभी दातार साहब ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि जितना भी काम होता है, वह सब के लिये होता है । हम मानते हैं कि सब के लिये होता है और सेंटर में भी और स्टेट्स में भी सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड काम कर रहे हैं, लेकिन जिन

स्त्रियों के बीच में काम होना चाहिये, वहां काम कतई नहीं हो रहा है । वहां काम करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो सोशल वैलफेयर बोर्ड की कोई जरूरत नहीं होगी । जिन स्त्रियों में काम होता है, मैं स्वयं समझदार हूं । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिन बातों की तरफ मैं ने ध्यान आकर्षित किया है, उन पर कुछ विचार किया जाये ।

श्री अमर सिंह डामर (झाबुआ—रक्षित अनुसूचित आदिम जातिया): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि अभी तक यह परिपाटी रही है कि अनुसूचित जातियो और आदिम जातियों के विषय में आयुक्त की रिपोर्ट हमारे माननीय गृह मंत्री की ओर से सदन में पेश होती है । मैं सोचता हू कि यह परिपाटी ठीक नहीं है । रिपोर्ट की प्रस्तावना में कमिश्नर महोदय ने अपनी मजबूरी जाहिर की है और रिपोर्ट समय पर पेश न करने का कारण यह बताया गया है कि राज्य सरकारें उन को समय पर सामग्री नहीं देती हैं । इस से यह साफ जाहिर है कि राज्य सरकारे हरिजनों और आदिवासियों की समस्या के प्रति उदासीन होती हैं या जान बूझ कर अपनी नीति ढीली रखती हैं । जहा तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैं विशेष तौर पर आदिवासियों की समस्या की ओर ही आपका ध्यान दिलाऊंगा । मैं मध्य प्रदेश के मध्य भारत एरिया के उस क्षेत्र से आया हूं जहा हमेशा ही सूखा रहता है दो महीने जो बारिश होती है, उसको छोड़ करके ।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ ६७ पर यह लिखा हुआ है :—

"केन्द्रीय आदिमजाति कल्याण परामर्श दात्री बोर्ड द्वारा सुझाव दिया : या है कि, 'आदिवासियों का तीन वर्ष से पुराना सब कर्ज समाप्त कर देना चाहिए और पिछले तीन वर्ष का ऋण कम से कम ब्याज पर या छः प्रतिशत से किसी भी रूप में अधिक न हो, अदा करना चाहिए । इस कार्य के लिए स्थापित की जाने वाली सहकारी समितियों को राज्य सरकारें द्वारा इस विषय में उचित सहायता दी जानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में उचित सहायता दी जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारे आदिवासी लोगों की सहायता करने के लिए इस मामले में आवश्यक कदम उठायें" ।

इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो निर्णय किया गया है, इसको जल्दी से जल्दी अमली रूप दिया जाये ।

मध्य भारत में आदिवासी लोग जो रहते हैं, मैं समझता हूं कि वे जितने पिछड़े हुए है, उतने शायद और कही पर लोग पिछड़े हुए नहीं होंगे । आर्थिक दृष्टि से कहिये, शैक्षणिक दृष्टि से कहिये, आवागमन की दृष्टि से कहिये या और किसी भी दृष्टि से कहिये, वह एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है । कुछ एक गांवों में जो किसान आदिवासी है, जिन के मैं कर्ज के आकड़े लाया हूं, उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं तीन चार व्यक्तियों के नाम तथा कर्ज की राशिया ही बयान करूंगा । श्री कनीराम गमीर गामड़ ने साहूकार माणजी करड़ावद से तीन सौ रुपये लिये । १४१० रुपये चुका चुकने के बाद भी तीन सौ रुपये बाकी निकलते हैं । श्री कचरा कालू गामड़ ने माणाजी करड़ावद साहूकार से ४०० रुपये कर्ज लिया । ८२० रुपये अदा करने के बाद भी ९०० रुपये बाकी निकलते है । श्री मूरजी नाथा ने साहूकार मिश्रीमल गादिया से ३०० रुपये उधार लिये । ६५३ रुपये अदा करने के बाद भी ९०० रुपये बाकी निकलते हैं जोकि चुकाये जाने हैं । बाबू गावा ने मिश्रीमल गादिया से ६६ रुपये उधार लिये थे, ११४ रुपये अदा कर देने के बाद भी ३०० रुपये बाकी निकलते हैं जोकि चुकाये जाने हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लम्बी चौड़ी फेहरिस्त देने से कोई लाभ नही होगा क्योंकि मिनिस्टर साहब इसका जवाब नहीं देंगे ।

श्री अमर सिंह डामर : मै और उदाहरण देना नहीं चाहता हूं । मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि सरकार जो मदद करती है तकावी के रूप में या सहकारी समितियां जो मदद करती हैं, रुपया देती हैं, उसका दुरुपयोग होता है । जैसे ही किसान या आदिवासी रुपया प्राप्त करता है, साहूकार लोग उसके घर पहुंच जाते है और जबर्दस्ती अपना रुपया वसूल कर लेते हैं । यही अगर स्थिति रही तो सरकार चाहे जितनी मदद करे, जितना ऋण चाहे दे, आदिवासी किसान का उद्धार होने वाला नहीं है और वे लोग पिछड़े ही रहेंगे । इस दृष्टि से जो यह प्रस्ताव किया गया है, मैं चाहता हूं इसको जल्दी से कार्यान्वित किया जाये और जितनी जल्दी इसको अमली रूप दिया गया उतना ही अच्छा होगा ।

अब मैं आदिवासी बच्चो को जो उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । रिपोर्ट के पृष्ठ ६१ पर यह कहा गया है :—

> "आदिवासी बच्चों के लिए ही खोले गये स्कूलो मे जहा तक आवश्यक तथा व्यावहारिक हो, शिक्षा उनकी मातृ-भाषा में ही देनी चाहिए । प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि मिकिर पहाड़ियों के अतिरिक्त आसाम के सभी स्वायत्तशासी पहाडी जिलों में शिक्षा आदिवासियों को अपनी मातृ-भाषा में ही दी जाती है" ।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रारम्भिक अवस्था में ही उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो आगे चल करके हिन्दी भाषा बोल सकना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा तथा हिन्दी सीखना बहुत मुश्किल होगा । वे शुद्ध हिन्दी बोल नहीं सकेंगे । इस वास्ते मेरा सुझाव है कि यह जो सुझाव दिया गया है कि प्रारम्भिक अवस्था में उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए यह ठीक नहीं है । उनको उस अवस्था में निजी भाषा न पढ़ा करके कुछ हिन्दी सिखाई जाए और उसके बाद आगे चल कर मातृ भाषा सिखाई जाए तो उत्तम रहेगा ।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ २६ पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित लोगों के बारे में जो कुछ लिखा गया है, उसको मै पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और उस पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं । इसमें लिखा है :—

> "अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्तियों का विचार है कि यदि वे दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जायें, समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और उनकी सामाजिक नियोग्यतायें भी स्वयमेव समाप्त हो जायेंगी । यह एक सन्देहास्पद मामला है, क्योंकि देश के कुछ भागों में विशेषकर दक्षिण में, जो हरिजन ईसाई हो गये हैं वे अब भी सामाजिक नियोग्यताओं के शिकार है, तो भी, इस वर्ष देश के कई भागों से अनुसूचित जातियों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की खबरे आई । बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने का यह आन्दोलन उस समय से आरम्भ हुआ जब डा० बी० आर० अम्बेदकर ने, अपनी मृत्यु के के कुछ मास पहले १९५६ में नागपुर में दीक्षा ली, पर इस आन्दोलन को वेग मिला उनकी मृत्यु के बाद ही । फिर भी यह आन्दोलन, मुख्यतया, बम्बई राज्य के मराठी भाषी प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा । आरम्भ में, इस आन्दोलन के नेताओं ने यह मांग की कि अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली शिक्षा, नौकरी और दूसरी सब रियायतें और सुविधायें

धर्म परिवर्तन करने के बाद भी इन लोगों को मिलनी चाहियें। भारत सरकार में इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उन सब रियायतें पाने का अधिकारी है जो अनुसूचित जातियों को मिलती हैं। संविधान में और संसद की कार्यवाही में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि चूंकि बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न धर्म है, अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति धर्म बदल कर बौद्ध बनता है, उसी समय से वह अनुसूचित जाति का नहीं रहता"।

इसमें ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखने वाली बातें भी लिखी हुई हैं। जिनको मैं पढ़कर हाउस का समय लेना नही चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि हरिजन और आदिवासी दोनों हिन्दु जाति के लोग हैं और यदि एक हरिजन ईसाई बनता है तो उसको संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अथवा सुविधायें जो सरकार की ओर से दी जाती हैं, या रिज़र्वेशन सर्विस में रहता है वह खत्म हो जाता है। मैं नहीं समझता कि यदि कोई आदिवासी ईसाई बन जाता है तो उसकी ये सब योग्यतायें खत्म क्यों नहीं होती है। मैं समझता हूं कि यह बात विशेष तौर पर सोचने की है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की पांच तहसीलों के अन्दर बहुत ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है। वे लोग धर्म के नाम, पर, सुधार के नाम पर लोगों का जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, झाबुआ की जजमेंट की कापी मेरे पास है और उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है :—

District Magistrate's Court, Jhubua
Case No. 3/57

Harisingh s/o Bijiya — Applicant

vs.

Father Narona, Catholic Mission, Thandla. — Non-applicant.

Application under section 552 Criminal Procedure Code.

*Judgment*

Catholic Mission, Non-applicant. is made before this court are briefly stated as under:

"That the applicant Harisingh, s/o Bijiya, Bhil resident of village Navapada, Tehsil Tandla was married to one Baddu, daughter of Khima Damar, Bhil, resident of Chhotidhamni, about two and a half years ago....".

उपाध्यक्ष महोदय : सारी जजमेंट को आप पढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि वक्त नहीं है।

श्री अमर सिंह डामर : दो चार लाइनें ही पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में ईसाइयों द्वारा बहुत जोरों से प्रचार कार्य हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो लोग हजारों मील दूर रहते हैं और अपने धर्म का प्रचार हिन्दुस्तान में करते हैं, उनसे हमारी यहां की गवर्नमेंट लोगों की रक्षा नहीं कर सकी है, यह खेदजनक बात है। इस जजमेंट में आगे लिखा है :—

'Baddu, a minor wife of the applicant Harisingh being found to be unlawfully detained at the Christian Mission by Mr. Narona for unlawful purpose under section 552 Cr. P.C. is hereby ordered to be restored to her husband, the applicant Harisingh,

Dated the 22-3-58.

मेरे कहने का मतलब यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में उन लोगों ने हम लोगों का एक्सप्लायटेशन शुरू कर दिया। जिस प्रकार से सूर्य के सामने चराग़ की रोशनी कुछ माने नहीं रखती है, उसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। अगर वह इसी तरह से बैठी रही तो धीरे-धीरे

[श्री अमर सिंह डामर]

सौ दो सौ सालों के बाद सभी लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित कर लिये जायेंगे ।

इस क्षेत्र के बारे में मुझे और भी बहुत सी बात कहने को थीं । लेकिन अब तो समय नहीं है, इस वास्ते . . . . .

**Shri L. Achaw Singh** (Inner Manipur): We have been discussing the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the economic and social conditions of this unfortunate section of our society.

We have not been given proper information about the acceptance and the implementation of the recommendations made by the Commissioner. We have very little information about this. We are in the dark as to whether these recommendations of the Commissioner have been accepted by the State Governments as well as the Central Government, and whether all of them or only some of them have been implemented.

In the Report of 1956-57 as many as 258 recommendations were made, and in the Report of 1957-58, the latest Report, 208 recommendations have been made. In the absence of details as to how these recommendations have been dealt with by this Ministry as well as by the State Governments, the discussion is reduced to a sort of routine business in the State Legislatures as well as in the Lok Sabha. I would, therefore, urge upon the Ministry to supply us in future the details as to how these recommendations have been dealt with.

My part of the country, the north-east frontier of India is mostly populated by the Tribal people. Their problem is primarily one of communications and education. During the days of the British most parts of NEFA, the Naga Hills and Manipur, were not properly administered, were not brought under the administration, and their main problem was communications. After independence, some of these areas have been brought under normal administration, but then the problem of communications is still very difficult.

In many of these areas, transport is by air for the public as well as the officials. If there is food shortage or famine, the only means of sending food is by air dropping, and the necessary requirements of the officials in the remote areas and the headquarters are met by air dropping. So, the most urgent and important problem is that of communications.

I have recently toured the Tamenglong subdivision which is mostly populated by the Naga tribes. A special multipurpose block has been started here two years ago. The headquarters is at Tamenglong, about 100 miles from Imphal. The journey lasts three or four days from Imphal, and high officials of the Government have not taken the trouble of visiting the headquarters itself. They have not been able to acquaint themselves with the actual conditions prevailing in these parts.

**17 hrs.**

Now we have been hearing reports and disquieting reports—of hostile activities in this area. They have many difficulties in carrying out this programme. I have studied the different development schemes in those parts. I have visited many schools, dispensaries, arts and craft centres, government demonstration farms of agriculture and animal husbandry. Now, they have made a very steady progress, specially with road construction, in starting schools, in terrace cultivation and in land reclamation work. In this area where this special multi-purpose block has been started, there are shortages of technical men; there are no agricultural officers, no medical men, no trained nurses. Still, they have done whatever they can. There are water tanks for supply of water to the villagers, but due to some defect, they cannot get proper water. This has to be investigated. I have visited many tanks.

They are made of concrete and cement, but they are without water I have visited some of the schools and dispensaries They are also without proper equipments In the dispensaries, they are without proper medicines.

These people are very poor, and they have been asked to contribute half in making roads and in carrying out schemes of development They cannot afford to work without food Most of them do not have enough food for the whole year and have to earn the food themselves So there is this difficulty Unless the people in these parts are paid some advance, it is not possible for them to work on road construction In order to make the road construction easier, it will be advisable to give some advance money to these people

The greatest obstacle in these parts is the hostile activity Some of the Naga hostiles have penetrated into these areas But then Government have also created some problems there Recently there have been some police operations in these parts, and in the name of collecting arms and rounding up the hostile elements, they have raided several villages. They go to the village before daybreak Every house is searched and the able-bodied people are brought out and beaten so that they could extract some information. But this sort of approach is wrong Recently the police chief issued a statement to the Press that every Naga is a hostile. I have travelled seven days through these areas and visited many villages and also visited many villages on the way I found that most of the Nagas in those parts are not at all hostile. They are innocent people, and honest people also They are ready to work for the development of those areas. They have given their utmost cooperation, and to call them hostile and start all sorts of police operations and beating would not help us at all.

We have heard of the psychological approach. Very often, it has been said that we should make some psychological approach We find that Dr Varrier Elwyn, Adviser to the NEFA Administration, has done a god service in publishing a book called "Myths of North East India". He has recently published a book in which he has stated that these people have a culture, they have also originality, and they should be encouraged to develop their culture and they should be taught how to respect themselves. Unless we approach them in a sympathetic way, unless we approach them with mutual respect, we would not be able to win their co-operation and sympathy

I would say one thing more That is about the Chakpas of Manipur. They are about 46,000 people and they have been clasified as Scheduled Castes There has been no caste system in my State and it is historically wrong to call these Chakpas Scheduled Castes I would request the Government to reconsider their decision and bring them under the head 'backward classes' They are sufficiently economically backward; and that is the only way to save them. They have already made a representation to the Government; and I hope Government will consider their appeal.

श्री प० ला० बाकपाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे आयुक्त की रिपोर्ट पर बोलने का मौका दिया है, उस के लिए मैं आप का आभारी हू । मेरे साथियो ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया है । आज स्थिति यह है कि हरिजन तो कहते है कि हम आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक दृष्टि से पिछडे हुए है और अन्य सज्जनो और सरकार का जो रवैया है, वह यही बताता है कि हम ने हरिजनो के लिए बहुत कुछ किया है । प्रश्न यह है कि वह नाप-तौल का कौन सा थर्मामीटर है, जिस से हम मापें कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है । लेकिन मै ठीक नही समझता कि डीटेल्ज में जा कर सारी बातें बताऊ, क्योंकि

[श्री प० ला० बारूपाल]

समय नहीं है और न आप ही ये सब कहने के लिए मुझे समय देंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में सरकारी पैसे से जिन जलाशयों का निर्माण हुआ है, आज तक हरिजनों को वहां पर समानता से पानी भरने का कोई अधिकार नहीं है। इस से आप माप सकते है कि हरिजनों मे कितनी उन्नति की है।

श्री बाल्मीकी : ऐसा दूसरी जगह भी है।

श्री प० ला० बारूपाल : सरकार ने हमारे लिए जो नौकरियों में रिजर्वेशन रखा है, अधिकारी ने तो उसको एक तरह के टालने की कोशिश की है। "तू लम्बा है, तू पतला है, तू मोटा है, तुझ में शिक्षा नही है, तू लायक नही है", इसी तरह कर के सरकार ने दस बरस तो निकाल दिये हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कर्जा ले लेता है और बाद में उस को अदा करने की शक्ति उस में नही होती है, तो वह घास-फूस, डगर वगैरह दे कर वह कर्जा चुकाने की कोशिश करता है—वह थोडा बहुत दे कर टालने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट का भी यही रवैया है कि हरिजनो का समाज पर जो कर्जा है, वह हम ने ये काम कर के चुका दिया है। लेकिन सरकार पर मेरा यह साफ आरोप है कि ईमानदारी से कोई काम करने की उस की नीयत नही है। मेरे पास इस के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज गावो में हरिजनो पर शाहराहे-आम डाके डाले जाते हैं, उन को लूटा जाता है, लेकिन पुलिस उन की कोई मदद नही करती है और अगर वह कुछ करती है, तो वह यह कि ईमानदारी से, ठीक तरह से मामला रजिस्टर नही करती है, मुकदमे खराब करती है और वे अदालत में फ़ेल हो जाते हैं। इस प्रकार का न्याय स्वतंत्र भारत में आज भी हरिजनों को मिलता है। थोड़े दिन का किस्सा है कि एक भंगी को, जो कि चूंकि भंगी था, इसलिए वह असमर्थ था, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी था, पुलिस वालों का कहा न करने से हत्या कर दी गई। डाक्टर और पुलिस की रिपोर्ट है, लेकिन उस के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही नही की गई। जैसा कि मै ने पहले भी कहा है, जब तक सैन्टर से हमारे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर साहब या हमारे मुख्य मत्री इन मामलों में व्यक्तिगत रूप से इन्ट्रेस्ट नहीं लेते है, तब तक उन लोगो को कोई इन्साफ नही मिलेगा। कब तक हम लोग इस प्रकार रोते रहेंगे और कब तक आप लोग ये सब बातें सुनते रहेंगे और कब तक हरिजनों की हालत इसी प्रकार रहेगी ? मै ये बातें कोई भावुकता के वश हो कर नही कह रहा हू। यह बिल्कुल सचाई है, और बिल्कुल ईमानदारी है और सरकार इस पर विश्वास करे।

सरकार ने रेफ्यूजियो का मामला तो दस बरसो में हल कर दिया। आज हिन्दुस्तान में कोई रेफ्यूजी दिखाई नही दे रहा है। लेकिन हरिजनो पर सवर्णों ने सदियो से अत्याचार किया, उन को कुचला और पैरों तले रौंद कर रखा और वे सदियो से शरणार्थी है, लेकिन उन को गवर्नमेंट कोई रियायत नही देती है। इस सम्बन्ध मे उन का आर्थिक स्टैंडर्ड ऊचा करने की बाते कही जाती हैं। लेकिन मै कहना चाहता हू कि उन का आर्थिक स्टैंडर्ड ऊचा करने से उन की सामाजिक हालत अच्छी नही होगी, कोई उन की इज्जत नही करेगा। मैं आप को इसका उदाहरण देना चाहता हू। हमारे रेलवे मिनिस्टर हिन्दुस्तान में सब से माने हुए आदमी हैं, आला दिमाग के आदमी है और सब उन की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं उन के सम्बन्ध में राजस्थान की एक बात बतलाना चाहता हू। मै बड़े दुख के साथ उस को आउट करना चाहता हू कि उन्होने एक सेठ के घर में भोजन किया, तो उन की थाली कर्मचारियों ने नहीं मांजी। आखिर वह सेठ उन की थाली को मांजने के लिए तैयार हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हमारी बिरादरी कटने वाली है, हम को

निकाल दिया जायेगा और तब उन्होंने वह वाली मांगी । यह हिन्दू समाज की मेन्टेलिटी है ।

कहा जाता है कि हरिजनों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है । पैसा खर्च करने में कोई कमी सरकार की ओर से नहीं है, लेकिन वह पैसा किस तरीके से लगाया जाता है ? वह बरबाद किया जाता है । हरिजनो का काम करने वाले ईमानदार आदमी नहीं हैं । जब तक अच्छे आदमी काम नहीं करेंगे, तब तक कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है । आज वहां पर भाई-भतीजावाद चलता है, आज वहां पर पक्षपात चलता है । किन आदमियों को गावों में काम करने के लिए लगाया जाता है? जिन्होंने शहर की गलियां नहीं देखी, जो सिनेमा देखें, जो लिप-स्टिक लगायें, क्या क्या करें, उन लोगों को गावों में काम करने के लिए लगाया जाता है । वे लोग गावों में पैदल भी नहीं चल सकते हैं । बी० डी० ओ० शिकार करने के लिए जाते हैं और ग्राम-सेविकाओं को रंग-रलिया करने के लिए बुलाते हैं । इस के प्रूफ हमारे पास है और मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन क्या किया गया ? सरकार उन को ज्यादा से ज्यादा ट्रान्सफर कर सकती है, लेकिन किसी गरीब को न्याय नहीं दिला सकती है । अगर मैं ईमानदारी से सब बातें कहूं, तो लोग हसेंगे कि यह क्या बक रहा है । हम को चिल्लाते हुए आज दस बरस हो गये, लेकिन गावों और शहरों में हरिजनों को बगैर पैसे के जमीन का पट्टा नहीं दिया जा सका है । क्या स्वर्ग के देवता देने के लिए आयेंगे ? राष्ट्रपति जी कहते हैं कि शिक्षा के बारे में यह होना चाहिए– मैं उन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं– मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यह होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वह होना चाहिए । आखिर स्वर्ग के देवता तो यह सब नहीं करेंगे—वे लोग ही करेंगे ।

रिपोर्ट की हालत यह है कि कहा जाता है कि हमें रिपोर्ट मिलती नहीं है, आंकड़े ठीक नहीं आते हैं । क्या नहीं आते हैं ? कोई काम नहीं करते हैं, तो आंकड़े क्या आयेंगे ? राजस्थान की रिपोर्ट देख लीजिये कि एक भी छुआछूत का मुकदमा दर्ज नहीं है, जहां कि रोज-मर्रा मुकदमे दर्ज होते हैं, जहां कि रोज-मर्रा के झगड़े तय होते हैं । इसलिए इस पर मेरा कोई विश्वास नहीं है । मैं ने पहले ही कहा था कि थोड़े बहुत एम० पीज० हो गये, दस, बीस, पचास एम० एल० एज० बन गये, लेकिन जहां तक हरिजनो की हालत को सुधारने का प्रश्न है, मैं बिल्कुल असंतोष प्रकट करता हूं और बिल्कुल निकम्मा काम समझता हूं । हरिजनो के लिए कुछ नहीं किया गया है । मैं आप से माफी चाहता हूं । अर्ज यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए । जिन हरिजनो को भेजा गया है, अगर वे नहीं रहेंगे, तो हमारे कोई दूसरे भाई आयेंगे । प्रश्न यह नहीं है कि हम लोग पार्लियामेंट में आयें और हमारा सम्मान बढे । यह बात जरूर है कि अगर आज रिजर्वेशन न होता, तो पन्ना लाल बारूपाल और बाल्मीकी जैसे को यहां कोई नहीं आने देता और दीवार को हाथ भी नहीं लगाने देता । इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इस प्रश्न पर फिर से सोचे और अगर वह नहीं सोचेगी, तो पता नहीं कि इस का रिजल्ट क्या होगा । इस प्रश्न पर हर तरीके से विचार कर के दूसरा कमीशन नियुक्त कर के देखे कि कौन हरिजन है, उन की क्या अवस्था है । पार्लियामेंट के मेम्बरों को गावों में भेजे । आज भी उन की हालत किसी से छिपी नहीं है । अगर सरकार उस को नजर-अन्दाज करना चाहती है, तो हमें कोई परवाह नहीं है । अगर सरकार दिवालियेपन से कर्जा चुकाना चाहती है, छोटे मोटे काम कर के हरिजनों के कर्जे को चुकाना चाहती है, तो जैसी उस की मरजी हो, वैसे वह करे ।

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri M. R. Krishna. What I have got, I will distribute among the hon. Members as many as I can accommodate, I

shall do; after that I will be helpless.

**An Hon. Member:** Five minutes at least for each.

**Shri M. R. Krishna:** Sir, before I deal with the Commissioner's report, I would like to make a few observations on the speech by the hon. Shri Datar. Referring to forced labour in the villages, he has said that it has been abolished and if there are any cases of that nature, the Member should bring them to his notice.

I do not want to give instances or cases of this nature prevalent in the whole country but I would only like the hon. Minister to take pains to find the works which are being done by the Harijans in the villages: works of this nature, such as, crop survey, field survey, crop estimates, etc. Who carries the luggage of the patel and the patwari? Have the State Governments or the Central Government got any evidence or information about people who are doing this kind of work in the villages? Let them find out how these things are done and whether the people who do this work are paid for that, whether this is not forced labour or whether they get any allowance or any income for these things. I would like the hon. Minister to make an enquiry and let this House know about it.

Coming to the Commissioner's report, I may say that every year we discuss this report. The Commissioner makes his recommendations. Not only that. This year we are having the Estimates Committee report. It is really very valuable. Apart from this, I am told that the Home Ministry or the Government is going to appoint another committee to go into the question of the Scheduled Castes and Tribes' welfare and so on. I do not know what are the reasons for appointing so many committees. I would be very grateful to the Ministry if the Ministry could take all the recommendations of one Committee. They may take either the recommendations contained in the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes or the recommendations contained in the report of the Estimates Committee. Only after those recommendations are fully implemented they can think of any other committee to go into these matters. Otherwise we will be wasting our time in discussing the reports of these committees only and there will be nothing in action. No doubt, the Home Minister has personally taken very keen interest in the welfare of the Scheduled Castes. I think the few bright patches in the gloomy report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is mainly due to his personal effort.

Sir, the Home Minister and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have said that the schemes are not properly implemented because they are all to be implemented through the State Governments. Most probably it is because the people are not co-operating with the Government that the schemes have not been properly implemented. This thing will continue for some more time. Now, even responsible persons, I hear, while speaking about the caste system and caste superiority, try to defend the existence of caste system by saying that this kind of discrimination is also existent in the Harijan community itself. I think this kind of people were solely responsible for the British to continue in this country and make this nation a slave nation for ages. Even today I think it is because of these people that there is corruption or dishonesty, if any, among the officers. If a corrupt officer is told that bribe taking is bad and the argument he gives out is that his chaprasis or constables also live on bribes, the officer conveniently forgets or he does not want to believe in the truth that if the top man becomes honest it will take only

a few seconds for the men who work under him to become more honest than the officer himself. Therefore, I do not think that any responsible Member would be doing any good to the Harijan community and to the entire nation by saying that because there is this feeling of caste system existing in the Harijan community they should also go on perpetuating this caste superiority over the others. It should be put to an end as soon as possible

Now I come to a very important point on which the whole country is agitated A large section of this House and the country feels that there must be a ceiling on the land We also welcome it There must be a ceiling But before taking any definite steps in this connection, I would like to caution about one thing Today the Harijan population which depends on agricultural labour is nearly to the extent of 70 per cent to 80 per cent Nearly one-third of the total agricultural landless labour is from the Scheduled Caste community We have the experience of the Hyderabad State When the jagirs were abolished, it was said that the lands will be distributed to the landless people Now we are introducing the ceiling We are trying to reduce the quantity of land owned by some people Here again there will be a very big danger These pepole today at least get half a meal and one wear Even if they work as seasonal labourers they will be able at least to live for some time But if the ceiling is imposed and if the land available is not distributed to the Harijans, they will not get any employment They will not have any land, nor will they be able to find jobs in the cities and towns Therefore, before any step is taken in this direction, I would like the Central Government first to see and ask from every State Government how much land will be available after imposing the ceiling and what amount of land will be available for distribution to the landless Harijans and Adivasis. It must also be ascertained as to who will pay the compensation The land owners will have to be paid compensation The point is whether State Government will pay the compensation or the Central Government will pay These are very important questions I want the Home Ministry to take note of these things, find out the details and get a complete scheme Even if it is a matter of appointing a few more officers the Home Ministry should not hesitate to do it They must get a definite scheme from every State before the ceiling is effected Otherwise, a large section of the people who are depending on the lands as agricultural labourers will be deprived of their existence

I come to another point, and that is about housing The Home Minister was kind enough to set apart nearly Rs 34,63,750 for Harijan housing during 1957-58 This is really a very good sum, and if that amount had been totally expended on building houses for the Harijans, it would have been very helpful, but he will be astonished to know that out of this amount only Rs 12 81 lakhs were spent last year This kind of tardy progress will not help the Harijans, and if the facilities accorded to Harijans are provided at this rate, and in this way I think it will take another 100 years for them to improve their standards

The Home Ministry would say that they have not been getting the schemes for construction of houses for Harijans I remember a specific scheme from one of the taluks of Andhra Pradesh—Jagtiyal taluk in Karimnagar district Under the Bhoodan Movement, land was distributed to nearly 127 Harijans The people wanted to construct their own houses Some of the Members of Parliament discussed the matter with the Deputy Secretary concerned with the Harijan welfare in the Ministry of Home Affairs, and after getting a definite assurance from him, the scheme was formulated and submitted to the

[Shri M. R. Krishna]

Home Ministry. But since October, 1958, nothing has been done, and those poor people who had to dismantle their original huts have to live now in the open and have to suffer in wind, rain and sun. Therefore, I want the Home Ministry at least to see that this scheme is implemented, and whatever amount they are going to set apart for the Harijan housing in the coming year must be fully spent. Otherwise, merely sanctioning an amount will not help.

The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has rightly said that education is a very strong weapon in the hands of the Harijans to get rid of the evils from which they are suffering today. But what help has been given to the Harijans today in the matter of education? About scholarships many Members have spoken, and therefore I do not want to stress on it. But I can say that the education which is being imparted to the Harijans is not *of any superior quality*. Still, they will have to compete with people who did not have any difficulty in getting good education in the schools. The Harijan community has suffered for long. The Harijans did not have schools; they did not have the opportunity of sitting with other children in the school. But yet this community is denied a special kind of education even though it is said in the Constitution, for instance, that the rights of education are available to all. Take, for instance, the public school education in India.

Now, the Home Ministry of the Government of India has sanctioned nearly a lakh of rupees last year, and it has also said that about 65 scholarships would be given to Scheduled Castes candidates. They perhaps wanted to make a beginning with that number. But, as I could learn from the Report of the Commissioner, out of those 65 scholarships, two scholarships have been awarded to Scheduled Caste people, five to other backward classes and none to the Scheduled Tribes. That is all. This is not the way in which you can impart education to the Harijan community and the Adivasis. I find that the Home Ministry has established some technical schools for the Scheduled Tribes. That is a very welcome sign, and I would request the Home Ministry to establish some more schools of that nature. If not, they can at least assist private institutions at different places to impart technical education to the Harijan community. Technical education alone would be able to solve the many problems which the Scheduled Caste and other backward communities are facing today.

श्री अजीत सिंह (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर रिजर्वेशन का काफी जिक्र हुआ है । मैं समझता हूं यह चीज एंडलेस पीरियड के लिए होनी चाहिए । इसका कोई समय मुकर्रर नहीं होना चाहिए और जब तक हरिजन भाई दूसरे लोगों के बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक यह चीज चलनी चाहिये । हम चाहें तो बेशक इस चीज को दस साल के बाद रिव्यू कर सकते हैं और तब की पोजिशन को देख सकते हैं ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पंजाब में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सर्विसिज में जो रिजर्वेशन दिया गया है वह १९ परसेंट है और दो परसेंट बैकवर्ड क्लासिज को दिया गया है । इस तरह से कुल मिलाकर २१ परसेंट रिजर्वेशन वहां है । कुल मिला करके मैं समझता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बहुत नुकसान होता है । मैं समझता हूं कि यह जो नुकसान होता है, इसकी जांच भी कमिश्नर साहब को करनी चाहिए । उनको यह देखना चाहिए कि किसी भी सूबे में अगर ऐसा होता है तो इसको रोकें । ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासिज को

शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों का जो कोटा है वह दे दिया गया ।

यहां पर लैंडलेस एग्रिकलचरिस्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । पहले पांच साला प्लान में एक करोड रुपया निकाला गया था जिससे जमीनें कुछ हरिजनो को दी गई । दूसरे प्लान में अभी तक गवर्नमेंट कसिडर ही कर रही है कि जमीन खरीद के देवे ।

हमारे शैडयूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लैंडलेस एग्रीकलचरिस्ट्स को बसाने के लिए तीन सोर्सेज की तरफ इशारा किया है । एक तो वह जमीन जो कि श्री विनोबा भावे को भूमिदान और ग्रामदान की शकल में मिलती है उसकी लैंडलेस हरिजन एग्रीकलचरिस्ट्स को दे दिया जाय । दूसरे वह जमीन जो कि लैंड होल्डिंग्स् पर सीलिंग लगाये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त हो, ऐसे रिलीज्ड लैंड को उनको दिया जा जा सकता है और तीसरे अवेलेबुल वेस्ट लैंड जो कि सरकार के पास पडा हो उसको हरिजनो में बाट दिया जाय । अब जहा तक हरिजनो को अवेलेबुल वेस्ट लैंड दिये जाने का ताल्लुक है उससे तो मैं एग्री करता हूँ लेकिन दूसरे से मैं एग्री नही करता हूँ । सीलिंग जब तक कि हमें पता नही चल सके कि कितनी जमीन हमारे पास है और कितनी सीलिंग से निकली और कितनी हमने डिस्ट्रिब्यूट की तब तक इससे कोई फायदा नही । भूमिदान वाली जमीन जो कि आम तौर पर लिटीगेशन वाली है कुछ झगडे वाली है और बजर और खराब है तो ऐसी नाकारा जमीन पर हम हरिजनो को बसा कर उनका क्या फ़ायदा कर सकेंगे । जिला भटिंडा तहसील फ़रीदकोट में जो सरप्लस जमीन है उसकी गवर्नमेंट पजाब अभी फ़रोख्त कर रही है । एक तरफ़ तो हम यह कह रहे हैं कि नागपुर रेजोलूशन को हमें पूरी तरह से कामयाब करना है और कोआपरेटिव फ़ार्मिंग करनी है और गवर्नमेंट की जो फालतू जमीन है उसकी लैंडलेस हरिजन एग्रीकलचरिस्ट्स को बाट देना है । दूसरी तरफ हमारी पजाब सरकार क्या कर रही है । जो फालतू जमीन है वह बेच रही है । मैं प्रार्थना करूगा कि ऐसी बातें जिस किसी भी स्टेट में हो उनको सुधारने की उचित व्यवस्था की जाय ।

एक बात और है कि जब तक कि हम अपनी सहकारी खेती को शुरू नही करते है तब तक के लिए हमें चाहिये कि वे गरीब हरिजन जो कि दूसरो की जमीनो पर मजदूरी का काम करते है उनके लिए एक आल इडिया ऐक्ट पास किया जाना चाहिये जिसके जरिये से मिनिमम वेजेज और मैक्सिमम आवर्स आफ वर्क उनके वास्ते तय कर सकें ताकि आज जो वह सुबह के दो बजे से जब सुबह का तारा निकलता है तब से लगातार खेत में जाकर रात के दस ग्यारह बजे तक जो जी तोड कर काम करते रहते है उसमें कुछ कमी की जा सके और उनको कुछ इस सम्बन्ध में राहत दी जा सके । हाउस साईट्स के बारे में कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा है । हमें खुशी है कि हमारी पजाब स्टेट में हरिजनो के लिए काफी बदोबस्त किया जा रहा है । पजाब गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में बडा अच्छा काम कर रही है और वह हरिजनो को हाउसिंग के वास्ते कर्ज और सबसिडीज दे रही है । मैं उम्मीद करता हू कि इस सहायता से काफी हरिजन अपने मकान बना लेंगे । इसके साथ ही पजाब गवर्नमेंट ने यह भी किया है कि वह कुछ जमीनें खरीद कर हर जिल में हरिजनो को दे रही है । यह पजाब सरकार की काफ़ी अच्छी पालिसी है ।

एक बात मुझे और कहनी है कि यह जो कंसालिडेशन आफ़ लैंड होल्डिंग्स हमारे पजाब में हो रहा है और पजाब एक्ट के मातहत जितनी फ़ालतू जमीन है उसका हक़ पचायतों

[श्री अजित सिंह]

को दे दिया गया है और पंचायतों को यह भी हक दे दिया गया है कि वह हरिजनों को जमीनें मकान बनाने के लिए देवें । अब होता यह है कि अगर कोई पंचायत अच्छी हो या जिसके दिल में कुछ इंसानियत का भाव हो वह तो हरिजनों के लिए कुछ जमीन अलग दे देती है मगर बहुत सी पंचायतें ऐसी भी देखने में आई हैं जो कि हरिजनों को जमीनें देने में बिल्कुल खुश नहीं हैं । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह की भी तजवीज होम मिनिस्ट्री की तरफ से सब स्टेट्स को जानी चाहिये कि हरिजनों को अवश्य जमीन दी जाय और शामिलियतों में जो हरिजन हों उनमें उनका हिस्सा बराबर होना चाहिये ताकि सिर्फ पंचायतें उनको ठेके पर देकर उनकी काश्त करवायें और उसका पैसा जो हो वह खर्च करे ।

रिहैब्लिटेशन का जहां तक सवाल है उसके लिए मुझे मिनिस्ट्री आफ़ रिहैब्लिटेशन को मुबारकबाद देना है । पंजाब में मैंने देखा है कि हमारी रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री ने हरिजनों के वास्ते बड़ा अच्छा काम किया है । गावों में हरिजनों का मकान १० रुपये और २० रुपये पर मकान के हिसाब से दे दिये गये हैं । जो भी हरिजन चाहे वह क्लेमेंट हो अथवा नान क्लेमेंट, चाहे बाहर का हो अथवा लोकल रेफ़यूजी हो, चाहे नान रेफ़यूजी, वह तमाम मकान और इवेकुई मकान उन्होंने हरिजनों को दे दिये हैं मगर शहरों में हरिजनों के वास्ते मकानों की बहुत तंगी है । शहरों में ऐसे मकानों का जो वैलुएशन किया गया है उसमें एक कड़ी शर्त यह लगा दी गई है कि उस मकान का जितना टोटल वैलुएशन हो उसकी कीमत का पांचवा हिस्सा हरिजन को बतौर पहिली किस्त देना पड़ता है । मैं समझता हूं कि यह पांचवे हिस्से का जो इंस्टालमेंट रक्खा गया है यह हरिजनों की आर्थिक अवस्था को देखते हुए अधिक है और वे इतना अदा करने की पोजीशन में आज नहीं हैं और इस लिए वे बड़ी मुश्किल में हैं । कीमत ना देने की सूरत में मकानों की नीलामी फिर शुरू की जा रही है । मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के जिनके कि क्लेम्स् वैरीफाइड नहीं हैं उनके वास्ते ३० इक्वेल इंस्टालमेंट में कीमत अदा करने की व्यवस्था की जाय ।

इसी तरीके से कुछ ऐसी गवर्नमेंट साइट्स हैं जिन पर कि हरिजनों ने अपने रहने के वास्ते मकान बना लिये हैं । अब यह कह कर कि चूंकि उन लोगों ने बगैर इजाजत के गवर्नमेंट लैंड पर अपने वास्ते मकान बना लिये इस लिए उनको वहां से मकानों में ताला लगा कर बाहर एविक्ट किया जाय, यह कुछ मुनासिब नहीं है । अलबता उस लैंड पर कि जिस पर कि उन्होंने यह मकान बना लिये हों, उस लैंड की कीमत उन मकानों में बसने वाले हरिजनों से वसूल कर ली जाय ।

आखिर में मैं जनाब वाला यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम कानून तो बना देते हैं और यह भी पास कर सकते हैं कि अनटचेबिल्टी कोगनेजेबुल औफेंस है मगर जिस तरीके से उस पर अमल होना चाहिये आज वह अमल नहीं हो रहा है । मैं चाहता हूं कि अनटचेबिल्टी को कंगनेजेबुल औफेंस करार दिया जाये जो कि मेरे ख्याल में शायद अभी तक नहीं है । लेकिन कानून बनाने से भी जरूरी बात यह है कि आज हरिजनों के दिलों में से डर की भावना निकाली जाये और सरकार अपने अमल द्वारा यह सिद्ध कर दे कि वह सिर्फ उनके वास्ते कानून बना कर ही संतोष न कर ले वरन् यह देखे कि उन कानूनों पर ठीक तौर से अमल होता भी है या नहीं ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब जिन्होंने बारबार यह गिला किया है कि उनकी जो सिफारिशें हैं उन पर

स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे और ठीक तरीके से अमल नहीं करती हैं, इस साफगोई के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साफ तौर पर यह शिकायत की है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनकी सिफारिशों पर ठीक से अमल नहीं करती है । मैं इस सम्बन्ध में होम मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहूंगा और उन से यह कहना चाहूंगा कि कमिश्नर साहब जिनको कि उन्होंने मुकर्रर किया है अगर कमिश्नर साहब की बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर कमिश्नर साहब को रखने की जरूरत ही क्या है और उस हालत में आप कमिश्नर साहब और उनके मुहकमे को रखते ही क्यों हैं और उनको हटा क्यों नहीं देते ? मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब ऐसी व्यवस्था करें ताकि कमिश्नर साहब जो सिफारिशें करते हैं उन पर राज्य सरकारों द्वारा पूरा अमल हो । अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये थोड़ा समय दिया ।

**Shri Shree Narayan Das** (Darbhanga): Before the hon. Deputy Minister replies, I would like to have one minute.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं डिप्टी होम मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिये बुलाने जा रहा था । खैर उससे पहले आप एक मिनट ले लें ।

**श्री श्रीनारायण दास** : मैं बताना चाहता हूं कि मेरा भी यही खयाल है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये पार्लियामेंट और असेम्बलीज में आगे के लिये भी रिजरवेशन होना चाहिये । लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर जब भविष्य में कभी पार्लियामेंट में बहस हो तो उस पर विचार प्रकट करने के लिये नान शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये भी कुछ रिजरवेशन होना चाहिये, उनका कुछ कोटा होना चाहिये और सारे का सारा समय केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों द्वारा ही न ले लिया जाये । इसलिये मैं आगे के लिये यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर बहस के लिये नान शेड्यूल्ड कास्ट्स वालों के लिये भी कुछ रिजरवेशन होना चाहिये ताकि यह न हो कि खाली शेड्यूल्ड कास्ट्स वाले ही सारा समय ले जायें ।

**Shri Manaen** (Darjeeling): Sir, the hon. Deputy Minister, Shri Datar, intervening in the debate said that besides the funds allocated for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes they also get the benefit from the funds allocated for the NES and CD blocks. This might be true in other areas, but I might point out that in the tea garden areas, particularly, in the Terai, Dooars and Darjeeling, the policy seems to be that NES and CD blocks should not work in tea areas. That is what the policy seems to be. About the Tribal Welfare Department in Terai and Dooars a large number—almost 99 per cent—of the working population consists of tribals, but whenever I have craved the indulgence of these officers to do some work in the tea gardens they always say that the affairs of the tea garden should be looked after by the management themselves. In this regard I want a categorical statement to be made by the hon. Minister as to whether the Government have any particular instructions that Tribal Welfare Department should not work in tea gardens.

One more point and only one sentence I shall say. A Social Welfare Study Team has been formed by the Planning Commission. It is very strange that in the Committee not a single representative of the tribals has been included. Secondly that Committee, as far as I know, has not toured the areas which are predominantly inhabited by the tribal people. For example, in Darjeeling and Jalpaigari districts there are peculiar Scheduled Tribes, like the Leches, Totos and Bhutias. This Committee has not studied them. So, I suggest that a tribal member be included in this Committee and that its life be further extended. Instead of subjecting the Report of this Committee to scathing criticism later, it

[Shri Manaen]

is better to extend its life and do the job over again.

श्री वाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से केवल एक मिनट में अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन यह खयाल रहे कि एक मिनट पर आप कायम रहें ।

श्री वाल्मीकी : आज सदन में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है और अभी कुछ ही देर में मंत्राणी महोदया बहस का उत्तर देने वाली हैं ।

मैं तो केवल यही कहूंगा कि हमारे देश में भंगियों की स्थिति अभी भी दयनीय है और उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार पहले की ही तरह जारी है । यह गलत बात है कि देश से अस्पृश्यता खत्म हो रही है बल्कि हकीकत यह है कि वह अभी भी जारी है । भंगी समाज और स्कैवेंजर्स अभी भी नीचे दबे हुए हैं । शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है :

"The working conditions of the scavengers and sweepers require to be improved as early as possible, as the dirty and inhuman conditions under which they have to work have contributed to a great extent in treating them as 'untouchables'".

गृह-मंत्रालय के हरिजन-कल्याण-बोर्ड के अधीनस्थ भंगी जांच कमेटी उनकी अवस्था की जांच के लिए बनी है यह इनक्वायरी कमेटी उनके बारे में जो रिपोर्ट देगी उससे पता चलेगा कि कैसी उनकी वर्किंग कंडिशंस हैं । भंगियों द्वारा सिर पर पाखाना ढोने के लांछन को छुड़ाने के लिये कमिश्नर साहब ने जो सुझाव दिये हैं उन पर जैसे अमल होना चाहिये, अमल नहीं हो रहा है और भंगियों द्वारा सिर पर पखाना ढोये जाने की बात अभी भी जारी है और वह खत्म नहीं हो रही है । मैं मंत्रिणी महोदया का ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि यह खराब प्रैक्टिस खत्म हो ।

मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि वजीफों की तथा अन्य जितनी भी सहूलियतें मिलती है, वे ऊपर ही ऊपर बंट जाती हैं और नीचे के लोग उन से वंचित रह जाते हैं । पहले उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था थी कि इस तरह के लोगों को, जो कि स्कैवेंजर कम्यूनिटी के थे, सहूलियत दी जाती थी । मैं आशा करता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा और खास तौर से उन की वर्किंग कन्डीशन को, जो कि आज भी बहुत खराब हैं, सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा । आज भी उन की हालत गिरी हुई है । और अगर भंगियो के लिहाज से अस्पृश्यता-निवारण को देखा जाये, तो हम इस परिणाम पर पहुंचते है कि इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नही हुआ है । आज भी उन के ऊपर जुल्म होता है । मैं एक उदाहरण दे कर इस तरफ आप का ध्यान खीचना चाहता हूं । गुडगांव में आठ आदिमयो को नंगा कर के पुलिस ने उन पर अत्याचार किया । आज देश में सब जगह हरिजनों पर भयंकर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर दबाव बढ रहा है, कत्ल भी हो रहे हैं और आगजनी भी हो रही है । मैं इस सम्बन्ध मे माननीय मंत्राणी जी के विचार जानना चाहता हूं कि उस तरफ क्या हो रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊपर ऊपर जो काम होगा, उस का कोई भी लाभ नही होगा । जो काम नीचे से शुरु किया जायेगा, उसी से वास्तव में हरिजनों को लाभ होगा । वैसे नारी होने के लिहाज से माननीय मंत्री जी का मां का हृदय है और वह समझती हैं कि कौन पीछे हैं । भंगी समाज को गांधीजी समाज की मां कहते थे । मैं चाहूंगा कि इस बारे में इस दृष्टि से विचार किया जाये ।

**Shrimati Alva:** Mr. Deputy-Speaker, Sir the debate on this subject of welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has, indeed, overshot its mark in the sense that we have not been able to finish it in the scheduled time, with the fact that despite that attempt, we have gathered no rich harvest in the shape of concrete and constructive suggestions as they should have come from the many hon Members who took part in it.

I am very grateful to the many hon Members who participated in this debate Nevertheless, I sympathise with Shri Shree Narayan Das There should be no reservation in this debate The sooner the privileged ones step in, the quicker shall we solve the problems that are facing the country

**Shri Pahadia** (Sawai Madhopur—Reserved—Sch Castes) That means, more time should be given

**Shrimati Alva:** That is for the House to decide That is for the Speaker to rule That is not my province

**Mr Deputy Speaker:** That is for the Members themselves When the motion is put to them, they take no exception When their own decision is enforced, everybody feels offended

**Shrimati Alva:** In this vast and ancient land, this is no new problem as some hon Members want to make it out The problem is as old as the hill, as ancient as the land, and is like the cancer that calls for newer and quicker methods of eradication Therefore, it becomes the responsibility not only of the Government, not only of the Ministry of Home Affairs, but it becomes the responsibility of each and all Therefore, if those Members who spoke with so much passion and zeal, could also with the same passion and zeal of a real and true missionary, would go round the country and find the difficulties, it would help As I said the other day, we are open to suggestions; we are open to advice Our policies are not rigid. Therefore, what you see around the country must be brought to our notice

For all the sins of commission and omission, this Government is charged. And yet, how far can a Government go? It is the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who has stated in his report that the tempo has grown in expenditure and work With the tempo growing in expenditure and work, I find the temper is also rising in the House It is a good omen that the tempers rise because with that raise of temper, we expect you to join us, because money and legislation cannot buy the solution, and it is only through concrete suggestions that we can arrive at a solution Shri Naushir Bharucha made a suggestion about land the other day, and he brought it out to our notice how the abolition of the *vatans* has brought some kind of relief in the Bombay State to these people, that is, the landless people, in the shape of emoluments That spirit must grow And how can it grow with governmental agencies?

Today, the task is well in hand as it never was before, twenty or thirty years ago, could you speak of this problem in the manner in which we have done today? I think we have tackled it fast enough, though I do admit, and I feel along with those who have spoken about it—believe me when I say I feel in the same passionate way—that we should go faster enough Therefore, I have stated that belief and action must be wedded Unless belief and action are wedded by each one of us in our approach to the problem, we shall not be able to solve, and many a day we shall sing this song year in and year out, many a report will come and go, and yet the problem will be baffling and defying us

But, nevertheless, we want this under-privileged section of our society to gain not in standard of living but in standard of life I want here to make a very fine distinction between

[Shrimati Alva]

standard of life and standard of living. It is our duty to give them a standard of life. It is the standard of life by which they will come up to the level of any other section in society; it is not the standard of living, which has a tinge of sophistication in it. We want to raise their standard of life. Therefore, we have provided in the Second Plan, Rs. 91 crores over and above the general schemes of the Five Year Plans, which cover the people generally and overall for the whole country.

Poverty there has been in this land for ages past, and poverty is passed on from sire to son. It is only now that independent India wants to raise her stature, by which she can look up and march ahead and say that no section of her people suffer any kind of stigma or shame. The removal of the grinding poverty will raise the standard of life to what we look forward to in these people.

I say once again that it is only the women who can be the liberating force in any section of society, educate the girl, and she will educate a family. So, educate the women. The women were backward; who fought for the women? We have gained now Therefore, there is no room for pessimism any more that this underprivileged section of our community is going to remain where it is for many a year to come.

In such a vast land ridden with superstition, religion and fanaticism, how can you take a step forward without purity of heart? Unless I believe every word I say, unless I practise everything I put forward in my speech, I cannot go ahead. What we require today are missionaries, not workers so much. They must have strength of conviction and the fervour of the crusader that this shall not be, that this stigma shall go because the nation has to achieve a stature It is not for you or me or a section of the society; it is for the glory of India that we have laid down these guarantees in our Constitution. We derive our sanction from that. It was the Father of the Na ion who showed us the way, and that dream must be fulfilled in the shortest possible period of time.

It has been stated, and very rightly, that this is the best Report so far. Is that progress or not?

**Shri D. C. Sharma** (Gurdaspur): No.

**Shrimati Alva:** Shri Sharma does not think so. I would commend to him to read this Report once again, if he has read it at all. He has gone!

There were many points raised about the expenditure on the Commissioner's office, but we must realise that it is an expert agency where all the data is collected, where all the material is gathered. Ours is not a unitary Government Why do we forget that fact? We have to take the States with us, whether they go as fast as we want them to go or slower than what we are doing It is not a unitary Government, and therefore the States are concerned in these welfare activities, and therefore the Report of the Commissioner must mention the loopholes that exist, the progress reports that do not come

Despite the loopholes, we still feel that the tempo has grown, and this House is aware that the tempo is growing. If you and I can join this tempo, it will grow still more. If we can speak outside the House also with the same passion and, as Shri Gaikwad has said, bring pressure of opinion, I am sure it will grow.

I do know that in rural life it is very hard because orthodoxy does not die, because poverty does not die. How can orthodoxy die, how can this stigma be eradicated, how can the sin be washed away unless there is economic uplift? It is a socio-economic problem.

It is not seen so much in the cities, as some hon. Members have stated. In the cities there is a rising equality, and therefore no one questions you who you are. But you go to your village, you go to the district, you go to the rural area. It is poverty that grinds this section down, and therefore, the first thing we should attend to is education, the second thing is economic uplift.

I do not know how hon. Members say that money is wasted. Money is bound to be wasted to some extent, the only thing is that we have to keep it to the minimum. As a housewife I can say that money is wasted everyday in my home. The budget could be stricter if I staped there Nevertheless, even if money is wasted, here are the MPs and MLAs; it is for them to go and see and report to us, and suggestions are always welcome. Let us minimise this wastage more and more

That brings me to the problem of properly trained personnel. It is true that we suffer from lack of proper personnel We suffer from this lack of personnel because we have not got the required number of trainees or men and women who believe in the cause There are many who rush to work, there are few who will work for the mere calling There has to be a calling, an avocation which summons you to do something, and therefore the training of the right personnel is very necessary In the Tata School of Social Sciences, workers are trained in this field, Adivasis also. We are trying to gather more and more men and women. It is not the number of rupees that you must count. It is the number of heads that you must count, the real genuine workers who will interpret a rupee and turn it into ten rupees for you. That is where the nation has to make advance. That is where each individual counts Collectively and individually, if we make up our minds, we can go far ahead.

Now, I come to scholarships. Almost every hon. Member has touched the subject of scholarships. From Rs. 30 lakhs we have raised the amount to Rs. 225 lakhs I gave the break-up of the figure the other day while opening the debate. I have also explained and tried to remove the misapprehension that was lingering in the minds of some The scholarships are decentralised from this year for the simple reason that there was a grievance against the Ministry of Education and the Ministry of Home Affairs that they did not reach in time, with the result that the needy students, both tribal and others, were not able to gather the benefit and carry on their academic work. It is true, and it is a very practical thing which every man and women understands If a student is not given his free in time, it completely defeats the purpose, mentally more than even academically If a boy or girl has not got the wherewithal to pay his or her fees and sits in the class, it is psychologically killing him or her That was the trouble We have now evolved a new pattern It may be, as Shri Barman has said, that this is also not going to work Let us not be so pessimistic Even if it does not work, we shall seek advice from him and find a new solution again Let us find a solution from day to day so that we can come to some kind of working arrangement by which our youngsters will not suffer. I call them youngsters because gradually this opinion must grow in the country, that our hostels should not be labelled tribal or Harijan hostels They should be general. This opinion must grow in the country Are we going to perpetuate this label by running these institutions? But the call must come from the people We as Government provide the money. We guarantee, we ear-mark, so much for scholarships, so much for hostels, and so much for other things But the call must come from the public, that they do not want this reservation, this water tight compartment any more; throw it more and

[Shrimati Alva]

more open so that the stigma is not felt.

Therefore, we must inculcate in the heads of the young ones who are studying in schools and colleges that this is a thing of the past, that today in the New India, they must not feel and have this inferiority complex.

I do not think the fear that Shri Barman expressed that the scholarships that come from both the States and the Centre for the Scheduled Caste students will not be enough to go round, is justified. I think there is no such fear in the immediate one or two years. We have provided well.

But if this situation does arise, we are prepared to reconsider with whatever means at our command. We are always considering. We are always examining these issues. We do not want any child to suffer. It is because India is growing gradually and education is not yet free in the country; otherwise, this question would never have arisen. If we could give free and compulsory education to our youngsters, this problem should never arise. Nevertheless, if at all such a situation does arise, we shall give it due consideration with all the seriousness at our command, and with the means which we may have or may not have, we shall try to do our best.

Shrimati Ganga Devi talked of scholarships. In the old system, *ad-hoc* payments were made. She rightly said that there were students who gave it up. I do also feel the same from my own conviction and academically, because I have not had a single concrete case before me, but I feel that only those who had the means and were the children of Scheduled Caste and Scheduled Tribe parents did go to college in many cases for the simple reason that they could not wait. You cannot wait and attend a college unless your father has the means to buy your books. So that for that reason, I think the House should welcome this decentralisation and watch the working of it as keenly as we are going to do from our end.

Then, we come to the special multi-purpose blocks. There are 43 multi-purpose blocks. Somebody rightly pointed out that some blocks are not working well. It has been time and again, said that all our schemes are not working well. The Prime Minister himself says that some schemes work very well and some do not work very well. It is true that when an experiment is made on such a vast scale, everything does not turn out as you want. All the cakes in your oven will not be evenly baked. Therefore, *it is with patience and forbearance* that we can proceed. But, with a spirit of criticism without constructive suggestions backing your speeches, it is difficult for us to carry on the work

Some of these blocks are over-sized indeed. There is no doubt about it. The tribal population is small in some of them as was pointed out. Somebody said no committees should be appointed. I think it will be a happy day when we can do without committees and commissions. But that happy day is far away. We shall have to bear with committees and commissions, for every time we come to a bottle-neck we want some expert body to show us how we can proceed and jump over the hurdle. It is a simple affair.

Therefore, even in this matter we have proposed that a committee be appointed to concentrate on the problems of these multi-purpose blocks—how to make them effective and well worth for the Tribals.

**Shri Supakar** (Sambalpur): May I know why there are a few multi-purpose blocks?

**Shrimati Alva:** There are 43 blocks.

**Shri Supakar:** Not enough.

**Shrimati Alva:** It is with the Ministry of Community Development

and it is all the time being examined as to the number of blocks and the places where they should be situated

**Shri C M Kedaria** (Mandvi—Reserved—Sch Tribes): May I know whether the Adivasi Seva Sangh has passed some resolution to pass some blocks to the non-agencies?

**Shrimati Alva:** I shall come to that later on I am coming back to the problem of the tribals The tribals need more attention than even the Scheduled Castes for the simple reason —as hon Member after Member has said—that some of the tribal areas have not even heard the name of the Prime Minister nor the name of the Home Minister and, perhaps, they have no idea of what kind of democracy we are running (*Interruptions*) Some of them are dying out We are making all efforts to see that they are rehabilitated and are in healthy and economic condition The Todas, for example, are dying out and we have been able to do something for them and they are getting back to health and better life So also, there were some tribal people in Himachal Pradesh to which our attention was drawn and we were able to do something for them—I think it was the Doghri community

Therefore, wherever some hon Member finds that some tribes are dying, it is for him to give suggestions and it is for us to look into the matter and see that we preserve these tribes, rich in their culture, rich in their simplicity and rich in their integrity

I want to say that the simplicity and the integrity of the tribals are worth our imitating As Mr Barman says, civilisation carries many evils to them We have to learn so much from them At the same time, we have to teach them so much.

Some other hon Member talked of roads and of exploitation It is for us to step in and see that proper co-operative methods are taken up so that this exploitation is stopped in the best possible way.

Now, it is very heartening for a woman to feel that the tribal women have become vocal and they are able to tell you what they feel about our schemes They are able to tell you that the school master does not come and when he comes he makes the children gather faggots That is the progress we have made I do not know how then can we say that we are not progressing We have progressed substantially Otherwise, could you think of tribal women coming to me and saying that these are their grievances, this is what we are doing and this is not what we are not doing? That is progress

**An Hon Member:** What is the percentage?

**Shrimati Alva:** The percentage depends on where you go I would like you to find out the percentage (*Interruptions*)

**18 hrs**

**An Hon Member:** What is the percentage given to the Assam tea labourers?

**Shrimati Alva:** I am not a walking-talking dictionary or directory You will have to ask me a question and I shall give you a reply How much time shall I have?

**Mr. Deputy-Speaker:** As much as she likes

**Shrimati Alva:** Is the House prepared to sit longer?

**Mr Deputy-Speaker:** How long does she require?

**Shrimati Alva:** About 15-20 minutes

**Shri Naushir Bharucha** (East Khandesh) She may continue tomorrow

**Mr. Deputy-Speaker:** I request the hon Members to have a little patience because this should be concluded today Tomorrow we are so fixed up that there will be no time absolutely. I request the hon Minister to be brief.

**Shrimati Alva:** I must state a few figures to show the progress and it will take a few minutes. I come to the physical targets achieved.

**Mr. Deputy-Speaker:** So far as figures are concerned, they can be laid on the Table of the House.

**Shrimati Alva:** I shall finish it with speed. For the education of tribals alone, we have given 1,42,103 scholarships, 78 higher schools, 59 adult education centres, 175 hostels, 150 hostel buildings and supplied books to 30,556 students and nearly 26,000 students were given mid-day meals.

The main thing in economic uplift is to supply bullocks, buffaloes, pigs, poultry, manure, seeds, etc. and nearly 6,000 families have been benefited. About 883 demonstration farms were opened, which is not a small number indeed. I want to convince the august House that we are going ahead with the funds at our command and the workers at our command with all the zeal we have. 289 gain golas were opened—this is only for the tribals; 22,308 acres of land were reclaimed and agricultural co-operative societies were established. 408 cottage industries training centres were started, which is not a small figure, for the whole of India. 459 students were given technical and vocational training and 897 trainees were trained before. 969 co-operative societies were opened.

These figures will convince anyone that we have done well. Our attention was drawn to scheduled areas and to article 339. I may tell the House that a Commission is proposed to be appointed shortly which would go into the whole question with a view to suggest improvements of the scheduled areas.

Then, the scavengers' problem was raised. This reminds me of a speech made by one of the hon. Members last year that there was so much caste system within the Scheduled Castes themselves that it baffles even the best planners. Therefore, we appeal not only to the workers in the field, but to the Scheduled Castes and non-Scheduled Castes, to everybody that we should speedily remove this feeling among the Scheduled Castes themselves.... (*Interruption.*) I am saying that this feeling has to be removed among themselves and unless this is removed it is very difficult to deliver the goods to the scavengers on a large scale. Nevertheless, Rs. 6 lakhs have been provided and 2,567 wheel barrows were provided to do away with that inhuman method of carrying night-soil on one's head. It is for the municipalities to come forward. All of us live in towns where there are municipalities or in districts where there are local boards and civic boards It is for us to carry this suggestion to them so that this most inhuman method of carrying night-soil becomes a thing of the past. The scavengers can then look up to us and start a new life.

**Shri M. C. Jain:** What about Malkani Committee's Report?

**Shrimati Alva:** It is not here today with me, but the Malkani Committee's Report will also contain recommendations which we shall examine and adopt as far as possible.

Then I come to religious conversion Conversion on the scale on which it used to be in India is a thing of the past. Anyone is free to change his religion, but it must come with an inner conviction. No longer can any missionary be allowed to convert on a mass scale. If you or I feel that we need a change of religion, it must be free for us to do so. It is a fundamential right guaranteed in the Constitution. But I want to mention that the Tribals do not lose their tribal character by conversion. They remain Tribals, whereas the Scheduled Castes lose their character at the time of conversion. How can you carry in religions that accept universal brotherhood like Islam and christianity this scheme of Scheduled Castes?

**Shri B. K. Gaikwad:** By conversion these things go.

**Shrimati Alva:** Buddhism is also a way of life. Therefore, by conversion they can claim the benefits on the plane of socio-economic backwardness. Only on the plane of socio-economic backwardness they become the other backward classes, and it is for the Government, for the social workers and for the agencies, both official and non-official, to consider them so. But to carry caste system polluting religions that do not have this scheme is something which sounds very strange.

Sir, every one of the Members has demanded that the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be prepared. Hon. Members know that there is a rush to be included among the Scheduled Castes, there is a rush to be included among the backward classes.

**Shri B. K. Gaikwad:** No, no, Scheduled Castes are living as Scheduled Castes.

**Shrimati Alva:** All that I want to tell Shri Gaikwad is that sometimes on this side of the border a caste is Scheduled and on that side of the border a caste is not Scheduled. Therefore, the move should be to bring the first caste out of the Scheduled list rather than put the second one in the Scheduled list. That, I think, would pave the way for better progress. They would go into the other backward classes. The sooner we expand and enlarge the other backward classes the better it is for our minds, the better it is for our progress. Sir, I think I have made myself clear on these two important points about conversion and the list.

Then comes the question of forced labour. There was a time in this land when from father to sons poverty was passed on.

**श्री जालमीकी :** बीस दिन हुए बुलन्दशहर में ६० किसानों ने एक लड़के को जान से मार दिया ।



**Shrimati Alva:** Sir, I am not yielding. Let me have my say.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Deputy Minister is not yielding. Let her proceed.

**Shrimati Alva:** Sir, wherever there is grinding poverty, there will be forced labour. Wherever there is economic ill in this land, there will be forced labour.

**An Hon. Member:** You admit it.

**Shrimati Alva:** Forced labour in what sense? Forced labour because of lack of economic benefit. Now, we have done away with child labour, but children are still being employed. Therefore, in the same fashion this evil may continue for some time. Nevertheless, we have to make an effort and remove this . It is more economic exploitation rather than anything else. In the Bombay State, as Shri Bharucha pointed out, they have abolished the institution of *watans* and they have brought in the system of emoluments. They earn their wages for the work they do on the land. This system must grow.

Then I come to the question of housing.

Some Members expressed satisfaction on the housing plan that is going on in the country. Nevertheless, wherever there is a colony coming up and if I happen to be there, I go and see to satisfy myself that it is a good as you and I would like to have. In some places I have found that there was no provision for latrines. In some places I have found that there was no privacy for women and children. We have to put these things right, and this is where we welcome your suggestions. As you go round the country, show us these little things that are missed, perhaps by oversight, perhaps by bad planning and perhaps by neglect. We have to give them a standard of life. You cannot give a family a standard of life unless you have set up a latrine in the house or created the civic sense or given the women a little corner for their privacy to bathe their infants and themselves. This is

[Shrimati Alva]

where constructive suggestions are welcome from everyone of the hon. Members here.

I do not wish to proceed any more except to refer to the reservation of seats.

**Shri Manaen:** What about the other backward classes?

**Shrimati Alva:** About the other backward classes, I mentioned the other day in my opening speech. There is no time. Let me rush through. About the reservation of seats, one of the hon. Members said that nine are here in this hon. House and 15 are in the legislatures all over India. What does it mean? It means that money cannot buy a good worker, a conscientious candidate. It is good progress that nine and 15 Members respectively are there without the reservation given to them.

**An Hon. Member:** What is the proportion?

**Shrimati Alva:** We need not fight on that principle. We have not come up to that stage. If each hon. Member is prepared to do his best, then we shall talk of proportions as early as next year. About the reservation of seats, it is the Home Minister who is giving it active consideration and it will get the priority it deserves and it will be decided in time.

Sir, there is nothing more to add. There were very many points. I think I have been able to give a survey of most of the points raised, though some here and there may have been left out. But I want to convince the House that as compared to yesterday or 30, 40 or 50 years ago, the forgotten man has arrived; the forgotten man has arrived on the promised land; and the great march has begun. And, therefore, with the poet, let us say that "we are all to be blamed until we see that in this human plan nothing is worth the making that does not make the man".

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

> "That this House takes note of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1957-58, laid on the Table of the House on the 9th December, 1958."

*The motion was adopted.*

---

**18·14 hrs.**

## BUSINESS OF THE HOUSE

**The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):** With your permission, I wish to announce that the House will take up the Reserve Bank of India (Amendment) Bill tomorrow as the first item of Government Business to be followed up by other business as already announced

This, as you know, is a very important Bill and we have to get it passed by this House before the 30th. It is, therefore, essential that it should be taken as the first item of Government Business.

**Shri Naushir Bharucha** (East Khandesh): I must strongly protest against this repeated change in the order of business. It completely upsets our work and our time schedule also. The Government must also understand that if they have a time schedule, the Members also have a time schedule. I strongly object to this sort of repeated alterations in the programme.

**Shri Satya Narayan Sinha:** There is no question of repeated alterations. As you know, it is a very important Bill. We had not included it in the agenda. In the very nature of things, we could not have included it in the agenda. Hon. Members must realise that the nature of the Bill was such that we could not include it. There were top secret things.

**Shri Naushir Bharucha:** You are changing the programme.